हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

24.03.2026/1100/RKS/HK-1

अध्यक्षः प्रश्नकाल आरम्भ।

प्रश्न संख्याः 3750 (स्थगित)

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की योजनाओं की डिटेल दी गई है, उनमें किसी योजना का कार्य 70 प्रतिशत और किसी का 80 प्रतिशत पूर्ण दर्शाया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक योजना 3897 करोड़ रुपये की है जिसमें 3704 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। प्रैक्टिकली इस योजना का कार्य 60 प्रतिशत से ऊपर नहीं हुआ है। सूचना में जो इस योजना के कार्य की परसेंटेज लिखी गई है वास्तव में धरातल पर उतना कार्य नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है कि क्या माननीय उप-मुख्य मंत्री इस स्कीम की वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध करवाएंगे? जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया कि इस योजना की कुल लागत 3897 करोड़ रुपये थी जिसमें से 3704 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब इस स्कीम के लिए जो 9.34 करोड़ रुपये और चाहिए, यह पैसा कहां से आएगा?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल भी ऐसा ही प्रश्न उठाया था जिसकी सूचना इन्हें दे दी गई थी। जल जीवन मिशन के तहत इनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 79 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। ये शेष 9 योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपकी लाइबिलिटीज कुल 32 करोड़ रुपये की है। यदि हम आपके क्षेत्र की सभी योजनाओं को जोड़ लें तो इन योजनाओं के निर्माण कार्य के लिए 49 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। हमें कुल मिलाकर 75 करोड़ रुपये की जरूरत है। वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत हमें धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें केंद्रीय मंत्रालय की ओर से आश्वस्त किया जा रहा है कि अप्रैल माह में इस हैड में धन उपलब्ध करवाने का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री की कैबिनेट मीटिंग के बाद जल जीवन मिशन 2.0 शुरू करने

का फैसला किया गया है। अब जल जीवन मिशन 2.0 में क्या-क्या प्रावधान हैं, हम उस हिसाब से अपने मसले उनके समक्ष उठाएंगे।

श्री बी.एस. द्वारा जारी.....

24.03.2025/1105/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 3750 क्रमांगत....उप-मुख्य मंत्री जारी...

अभी तक तो उन्होंने इनकार कर रखा था कि आपको हम कुछ नहीं दे सकते। आप स्टेट फंडिंग से करो। फिर हमने उनसे कहा कि आपने हमें जो पैसा कमिट किया है, वह तो खर्च हो चुका है। अब ठेकेदारों को पैसा देना है या फिर कोई स्कीम्स कंप्लीट करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। अब उन्होंने कहा है ठीक है। आप जो भी आपकी प्रपोजल है आप उन्हें भेजें। माननीय सदस्य जो 10 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं या जल जीवन मिशन का जितना भी मसला है, यह सारा यूनियन को जाएगा और वहां से जैसे-जैसे सैंक्शंस आएंगी हम उन्हें करेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन में हर साल कुछ न कुछ पैसा आ रहा है। परंतु जहां पर विपक्ष के विधायक हैं, वहां एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। वर्ष 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में केंद्र का बजट सिर्फ 17,000 करोड़ रुपये था। अभी जो वर्ष 2026-27 का बजट है, उसमें 74,000 करोड़ रुपये है और जितनी भी जल जीवन मिशन में पुरानी स्कीमें हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए पैसा दिया जाएगा। जहां पर हमारी स्कीम 60-70 प्रतिशत कंप्लीट हो गई है, क्या उप मुख्य मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि उन स्कीमों को पूरा करने के लिए विपक्ष के विधायकों को भी जो पैसा दिल्ली से आएगा, उसको देंगे? और इसमें एक स्कीम है जिसमें मैंने जो बताया है कि यह 3800 करोड़ रुपये की थी उसमें से 3700 करोड़ रुपये खर्च हो गया है, अब इसके लिए 9 करोड़ रुपये और चाहिए। यह जो बीच का अमाउंट है। जब स्कीम 3800 करोड़ रुपये की थी और 3700 करोड़ रुपये खर्च कर लिया तो 9 करोड़ रुपये के लिए क्या स्टेट फंड्स से करेंगे या इसको अलग से आप सेंटर गवर्नमेंट को भेजेंगे?

24.03.2025/1105/बी.एस./एच.के.-2

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस हाउस के बहुत पुराने सदस्य हैं, ठीक है आप विपक्ष में हैं। आपको दोषारोपण का अधिकार है कि आप सत्ता पक्ष पर दोषारोपण कर सकते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन का पैसा ऐसा नहीं है कि वहां से आएगा तो हम आपकी कांस्टीट्यूएंसी में खर्च नहीं करेंगे।वह स्कीम-वाइज आता है और वह आपकी कांस्टीट्यूएंसी में आता है। कोई भी पैसा जो जल जीवन मिशन का आता है, वह पार्टिकुलर स्कीम को आता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष पर खर्च हो जाएगा या विपक्ष पर खर्च हो जाएगा। वहां पूरा चेक है। वहां पर ऐसा चेक है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी भी स्कीम का एक भी पैसा दाएं-बाएं नहीं कर सकते। जो आपको आएगा वह आपको वहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए यह जो आपने आरोप लगाया, आप इसे वापस ले लें।

दूसरा, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि स्कीम में पैसा ज्यादा लग रहा है। आपकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब स्कीम को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, तो पैसा ज्यादा लग जाता है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए कोई माध्यम निकले और सेंटर को भी बोलेंगे। मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्री हैं। आप इनसे खुद भी मिला करो। ऐसे क्वेश्चन करने से काम नहीं होता है। वित्त मंत्री के पास जाकर बताना भी पड़ता है कि मेरी स्कीम कंप्लीट हो सकती है। बाकी हमारा जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपया लंबित है और सेंटर से टॉक्स चल रही है। केंद्र ने जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया है। पिछले साल का जो आप कह रहे हैं 17,000 करोड़ रुपये था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल जल जीवन मिशन में जांच बिठाई थी। क्योंकि जो वह चाहते थे कि पूरे देश में जिस लेवल का रिजल्ट आये शायद उससे वह संतुष्ट नहीं थे। तो पूरे देश में जगह-जगह स्कीम्स की जांच हुई। हमारे यहां भी ऑफिसर्स आए थे। उन्होंने ग्राउंड पर देखा कि स्कीम्स उपलब्ध हैं या नहीं हैं? उसके बाद अब कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसमें आगे बढ़ा जाए। टाइम भी एक्सटेंड किया है और पैसा भी दिया है। लेकिन अब इसमें 19 शर्तें लगी हैं कोई भी स्कीम का पैसा देने से पहले वे सारी शर्तें चैक होंगी तब जा करके पैसा आएगा। हम इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल जीवन का पैसा आए जैसे ही आपकी स्कीम के लिए पैसा आएगा हम जल्दी से

इस काम को करेंगे। नहीं तो आप दिल्ली जाते रहते हैं, आप भी कोशिश करें। मुख्य मंत्री जी से भी मिलें, सोर्स तो दो ही हैं, या इधर है या उधर है।

24.03.2025/1105/बी.एस./एच.के.-3

मुख्य मंत्री : नहीं-नहीं यहां नहीं है।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, जिनमें सारी मशीनरी आ गई है और फिट हो हो चुकी हैं। सिर्फ तीन-चार-पांच लाख रुपये की जरूरत ह और 5 लाख रुपये से हजारों लोगों की प्यास बुझ जाएगी और

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1110/DT/YK-1

प्रश्न संख्या 3750 जारी

श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी...

इन स्कीम्ज में 10 से 12 करोड़ रुपये के लगभग खर्च कर दिया गया है। केवल तीन-चार स्कीम्ज ऐसी हैं जिनमें यदि 5 लाख रुपया अतिरक्ति उपलब्ध करवा दिया जाए तो काम हो जायेगा। ठेकेदार ने भी यह स्कीम्ज इस लिए पूरी नहीं की क्योंकि शायद उसकी पेमेंट नहीं की गई है। क्या सरकार इन स्कीम्ज को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करेगी?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने पहले ही बोल दिया है कि वह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। लेकिन चलिए उप-मुख्य मंत्री महोदय आप क्या कहना चाहेंगे?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर दो-चार लाख रुपये देने की बात हुई तब तो माननीय सदस्य के आग्रह को कंसीडर किया जा सकता है। अगर उसका पहले का कोई पैसा फंसा है, जैसे वह पैसा जल जीवन मिशन से नहीं आया, कहने का अर्थ है कि काफी अमाउंट फंसा है, तब तो जब केंद्र सरकार से पैसा आयेगा तभी इस काम को हम कर पाएंगे। **जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सारा पैसा दिया जा चुका है और दो-तीन**

लाख में स्कीम कंपलीट हो जाएगी तो प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उसे कंपलीट करवा देगी।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय,माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र से स्कीमवार पैसा आता है। केन्द्र को आपके विभाग द्वारा डी0पी0आर्ज0 अप्रूवल हेतु भेजी जाती है। जब विभाग द्वारा डी0पी0आर्ज0 तैयार करके केन्द्र को नहीं भेजी जाएंगी तो फिर इन योजनाओं के लिए पैसा कैसे स्वीकृत होंगा? विपक्ष के विधायको के विधान सभा क्षेत्रों की डी0पी0आर्ज या तो तैयार नहीं की जाती और ये तैयार कर ली जाए तो फिर उसे आगे सेंटर और नाबार्ड की अप्रूवल के लिए नहीं भेजा जाता। इसलिए क्या माननीय उप-मुख्य मंत्री आश्वासन देंगे कि विपक्ष के विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों की योजनाओं की डी0पी0आर्ज0 तैयार करके नाबार्ड या केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजी जाएंगी? मैंने इस प्रश्न के माध्यम से विस्तृत जानकारी पूछी थी लेकिन उसे कर्टेल कर दिया गया है। जो 'क' भाग था वह तो यही था कि जो इसकी जानकारी है वह विधान सभा क्षेत्रवार दी जाए कि तीन साल में केंद्र की योजनाओं का कितना पैसा मिला; योजना सहित व विधान सहित ब्यौरा दिया जाए। वह इसमें से कट हो गया, तो क्या माननीय उप-मुख्य मंत्री जी उसको उपलब्ध करवा देंगे।

24.03.2026/1110/DT/YK-2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठें हैं उनमें से कोई भी सदस्य ऐसा कह दे की हमने किसी स्कीम की डी0पी0आर0 बना कर जल शक्ति विभाग में भेजी थी और वह मंत्री जी के पास पहुंच भी गई लेकिन वहां से फारवर्ड नहीं हुई। आप किसी भी स्कीम का नाम लें जिसमें आप यह कह सकें की हम स्कीम की डी0पी0आर0 बना कर भेजते हैं और वह आगे नहीं भेजी जाती। किसी भी माननीय विधायक की कोई भी ऐसी स्कीम का उल्लेख आप यहां करें। किसी भी विधायक के क्षेत्र की कोई भी स्कीम जो हमारे पास पहुंची है और हमने आगे फारवर्ड न की हो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसमे लिमिट 200 या 225 करोड़ रुपये की है, यानी जो भी लिमिट है, उस लिमिट का पैसा अगर खर्च हो गया है तो नाबार्ड ही उसे पेंडिंग कर देता है या दूसरी फंडिग एजेन्सीज उसे पेंड कर देती हैं। मैं टोटेलटि में भी बता दूंगा कि हमारी कितनी स्कीम्ज फारवर्ड हुई हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के संबंध में पूछा है या टोटेलटि के संबंध में पूछा है तो उन्हें मैं बताना चाहुंगा कि 2288 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार से आया है उसका पूरा बाइफरकेशन हमने दिया है और उसमें दर्शाया है कि कितना-कितना पैसा आया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा मुख्य रूप से बना कर लाया था क्योंकि मुझे पता था कि ये अपनी विधान सभा से संबंधित जानकारी के बारे में जरूर पूछेंगे। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे रहा हूं ये उसमें अपनी प्रत्येक स्कीम के बारे में देख सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। यह दस्तावेज पूरी तरह से सहीं आंकड़ों के साथ बनाया गया है और यह आपको उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

24.03.2026/1110/DT/YK-3

प्रश्न संख्या : 3762

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर जो राशि खर्च हुई है इसमें प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को छोड़ कर जो प्रदेश में जगह-जगह फलैक्स के माध्यम से विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, क्या सरकार द्वारा वे स्थान नोटिफाइ किये गये हैं; अगर नोटिफाइ किये गये हैं तो क्या सरकार ने उसकी आउटरीच विजिब्लिटी कैपेसटी की स्टडी करवाई है ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं इन विज्ञापन के माध्यम से लाभार्थियों को कितना लाभ हुआ, क्या इसके बारे में कोई सूचना सरकार के पास है?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.03.2026/1115/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या : 3762.....जारीश्री सुधीर शर्मा के पश्चात..... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने आई0 एण्ड पी0 आर0 विभाग में कोई ज्यादा व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। पूर्व सरकार के समय से जो व्यवस्था चली आ रही है, हम भी उसी के अनुसार आगे कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमसे तो वैसे भी पब्लिकेशन व

पत्रकार बंधु थोड़े दुःखी रहते हैं क्योंकि हमारा खर्चा बहुत कम है। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। हमने आई0 एण्ड पी0 आर0 विभाग के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा जो खर्च हुए हैं, वे अन्य विभागों ने अपने स्तर पर खर्च किए हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग को किसी रोग से संबंधित बोर्ड लगाना हो या कृषि विभाग द्वारा किन्हीं बिमारियों के संबंध में लोगों को जागरुक करना हो। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले तीन वर्ष के कार्यकाल में लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च किए थे। हमने पिछले तीन वर्षों में 50 प्रतिशत यानी के लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमने डी0ई0बी0 के रेट को भी कम किया है क्योंकि हमने इस व्यवस्था को भी ठीक करना है। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 27-12-2017 से लेकर दिनांक 31-12-2020 तक भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने प्रिंट मीडिया पर 16,19,77,980/- रुपये खर्च किए और हमारी सरकार ने दिनांक 11-12-2022 से दिनांक 31-10-2025 तक 8,48,43,674/- रुपये खर्च किए। इसी प्रकार पूर्व सरकार ने तीन साल में इलैक्ट्रोनिक्स/डिजिटल मीडिया पर 3,91,95,702/- रुपये खर्च किए और हमारी सरकार ने 2,61,86,591/- रुपये खर्च किए। इसके अलावा पूर्व सरकार ने तीन साल में होर्डिंग व एग्जिबिशन पर 6,36,16,557/- रुपये खर्च किए और हमारी सरकार ने 2,40,35,168/- रुपये खर्च किए। इसी प्रकार पूर्व सरकार ने तीन साल में बस पैनल्स पर 1,80,78,261/- रुपये खर्च किए और हमारी सरकार ने 1,23,22,136/- रुपये खर्च किए।

24.03.2026/1115/वाई.के.-एन.जी./2

यह पैसे भी तब खर्च किए क्योंकि माननीय उप-मुख्य मंत्री, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हर-रोज़ बोलते थे कि बस पैनल्स पर विज्ञापन लगाए जाएं। इस प्रकार से हमारी सरकार के तीन सालों में पूर्व सरकार के पहले तीन सालों की तुलना में आधा खर्च हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विजिबिलिटी व नोटिफिकेशन के बारे में बात की है तो इन्होंने यह बहुत अच्छी बात मेरे ध्यान में लाई है। पिछली सरकार के समय में होर्डिंग के जो भी स्थान थे, हमारी सरकार ने भी उन्हीं स्थानों पर होर्डिंग्स को लगाया है। **माननीय सदस्य जो विजिबिलिटी व नोटिफिकेशन के बारे में कह रहे हैं तो हमारी सरकार उस पर भी विचार करेगी।** अभी तो पूर्व की परम्परा को ही अपना रहे हैं।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक पूछने का मतलब यह है कि प्रदेश सरकार क्या इसी वित्तीय वर्ष में इसकी व्यवस्था करेगी कि कहां-कहां ऐसे स्थान होने चाहिएं, जहां पर होर्डिंग्स व फलैक्स को लगाया जा सके? हमारा प्रदेश पर्यटन पर आधारित है और हम, सरकार या कोई अन्य भी कहीं पर भी होर्डिंग्स व फलैक्स लगा देता है। क्या प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी कि इनके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थान होंगे? इसके अलावा उस पर रेट भी फिक्स होना चाहिए ताकि सरकार की आए बढ़ सके। क्या मुख्य मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में इसे सुनिश्चित करेंगे?इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार के पास सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग है और अन्य विभागों द्वारा जब कोई भी होर्डिंग लगाया जाता है तो उसके लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के पास संबंधित विभाग द्वारा अप्रूवल के लिए भेजा जाए। मैं प्रिंट व डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं केवल होर्डिंग्स व फलैक्स आदी की बात कर रहा हूं। मेरा कहना है कि अप्रूवल होने के बाद ही संबंधित विभाग प्रदेश में चिन्हित स्थानों पर अपने होर्डिंग्स व फलैक्स लगाए। कई बार ऐसी जगहों या मोड़ों पर फलैक्स लगा दिया जाता है कि सामने से आने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती।क्या इन चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा? उत्तर में कहा गया है कि 22,87,74,109/- रुपये खर्च हो गए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि यदि इतने पैसे धर्मशाला में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस के निर्माण के लिए पैसे दे देते तो उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू हो चुका होता। यह बात तो अलग है लेकिन मेरी मुख्य बात यह है कि एडवर्टाइजमैंट व पब्लिकेशन नियमों को सेट करके कोई भी कहीं पर भी होर्डिंग लगाने के लिए

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या:3762 जारी ..... श्री सुधीर शर्मा जारी .....

इसके नियमों के ऊपर किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन या एक्ट लाकर प्रदेश के भीतर निर्धारित करेंगे क्या?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न होर्डिंग्स से संबंधित है, जिसमें कई प्रकार की व्यावहारिक अड़चनें आती हैं। इन सभी बातों में कई बार राजनीतिक दल स्वयं ही विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स लगा देते हैं। अब हमारे प्रदेश में इतने राजनीतिक दलों के संगठन है, वे

सभी अक्सर एक महीने के लिए होर्डिंग लगा लेते हैं। कई बार ऐसी जगहों पर होर्डिंग्स लगाए जाते हैं जिससे आम जनता को असुविधा होती है। मैं इस समस्या को समझता हूं। इस चीज को किस प्रकार से करना है वह तो विचार-विमर्श के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। इसके साथ ही, उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दे पर भी बात कही है। अगर हम हमारी सरकार की बात करे तो हमारी सरकार ने लगभग 14 करोड़ रुपये होर्डिंग पर खर्च किए हैं जबकि पूर्व भाजपा की सरकार ने 28 करोड़ रुपये होर्डिंग पर खर्च किए थे। वे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित नहीं कर पाई। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस बनाना है, तो हमें लिखित में यह दिया जाए कि बिजली और पानी का खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और हम फॉरेस्ट के पैसों को जमा करवा देंगे।

24.03.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-02

प्रश्न संख्या : 4024

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मंदिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट लगाने के विषय में था। पूर्व सरकार के समय श्री नैना देवी में जहां तक गाड़िया जाती है वहां से आगे बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए लिफ्ट लगाकर मंदिर तक पहुंचाया जा सके, इस दृष्टि से लिफ्ट का प्रोविजन किया था। इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था, टेंडर जारी हो चुका था, कार्य भी आवंटित हो चुका था और कार्य शुरू भी हो गया था। मेरी सूचना के मुताबिक इस कार्य के लिए लगभग 70—80 लाख रुपये खर्च भी कर दिये गये। इसके अतिरिक्त, जहाँ लिफ्ट लगाई जानी थी उस स्थान को समतल करने का कार्य भी कर लिया गया था। हालांकि, सरकार बदलने के बाद यह कार्य रोक दिया गया। वर्तमान में माननीय उप-मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जा रहा है कि भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर इस कार्य को रोका गया है। अभी हाल ही में प्लानिंग मीटिंग की बैठक हुई थी और मैंने उस बैठक में भी यह प्रश्न उठाया था। उस समय वहां के जिला उपायुक्त जोकि टेम्पल ट्रस्ट के कमिश्नर भी हैं, उन्होंने कहा था कि लिफ्ट का कार्य चल रहा है। जब मैंने स्ट्रोंगली कहा

कि कार्य बंद है तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं निर्देश दिए थे कि यदि कार्य नहीं चल रहा है तो लिफ्ट के कार्य को तुरंत शुरू किया जाए। उस समय किसी भी प्रकार की जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट का उल्लेख नहीं था। अब जब विधान सभा में इस प्रश्न का जबाव देना था तो जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। इससे यह साफ है कि या तो प्लानिंग मीटिंग में गलत जानकारी दी गई थी या अब सदन के माध्यम से हमें गुमराह कर रहे है। इसलिए सच्चाई जो है, उसे बताया जाए। यदि कोई जियोलॉजिकल सर्वेक्षण किया गया है तो बताया जाए की यह सर्वे किसने किया है? कोई एजेंसी होगी या कोई विभाग होगा। उसकी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस आधार पर लिफ्ट परियोजना को रोका गया।

24.03.2026/1120/ए0जी0/ए0पी0/-03

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रणधीर शर्मा जी ने श्री नैना देवी मंदिर न्यास द्वारा लिफ्ट निर्माण का प्रश्न किया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार के समय में मंदिर न्यास ने सिफारिश की थी कि मंदिर में लिफ्ट बनाई जाए। जिसके लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया और उसे स्वीकृति भी दी गई। इसके निर्माण कार्य के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये जारी भी किए गए और कुछ कार्य वहां पर हुआ। लेकिन बाद में नया न्यास बनने के बाद, उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि इस लिफ्ट परियोजना का कार्य रोका जाए क्योंकि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1125/AT/AG/01

प्रश्न संख्या 4024 जारी...उप-मुख्यमंत्री जारी...

यहां पर पहले भी भगदड़ हो चुकी है और वहां ऐसा घटनाक्रम हो चुका है। उसके चलते न्यास ने ही कहा कि इस काम को रोका जाए। अब एक न्यास ने कहा कि इसे शुरू किया जाए, तो इसे शुरू किया गया। दूसरी ओर अब न्यास कह रही है कि इसे रोका जाए। इस बीच में जो सर्वेक्षण चलते हैं, उसमें यह बात आई है कि नैना देवी में लगभग सवा सौ करोड़

रुपये या ढाई सौ करोड़ रुपये के आसपास का काम प्रस्तावित है। उस टोटलिटी में काम होना है। लेकिन मैं आपके सामने यह स्थिति रख रहा हूं कि न्यास ने इसका काम रोकने के लिए कहा है, इसलिए यह काम रूका हुआ है।

अगर मुख्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करते हैं और इनके द्वारा अगर आपको कोई कमिटमेंट कि गई है, तो सरकार मुख्य मंत्री के आदेश के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन न्यास से प्रस्ताव द्वारा यह डलवाया जाए कि जो काम रोकने के लिए कहा गया था उसे जारी रखा जाए। जहां से काम रुकवाया गया है वहीं से हमें डायरेक्शन आनी चाहिए कि यह काम फिर से किया जाए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में विधायक न्यास के मेंबर ही नहीं हैं। न तो हमें स्पेशल इनवाइटेड के तौर पर बुलाया जाता है और न ही हमें मेंबर बनाया गया है। इसलिए हम प्रस्ताव कैसे डलवाएंगे, यह भी एक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, जो भगदड़ की बात आपने की है, यह भगदड़ जहां लिफ्ट बनी है वहां नहीं हुई। यह दूसरी तरफ हुई थी, जहां से लोग पैदल जाते हैं। जहां लिफ्ट बनी है, वहां आज तक कोई भी भगदड़ नहीं हुई है। वहां तक तो गाड़ियां जाती हैं। जिसने भी यह जवाब लिखा है उसने उप-मुख्यमंत्री महोदय आपको भी गुमराह किया है। भगदड़ वहां हुई ही नहीं है और अगर भगदड़ होने की आशंका भी है, तो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग ज्यादा परेशान होंगे। उनके लिए लिफ्ट बन जाएगी तो सुविधा होगी। आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है, वह या तो गलत है या फिर हुई ही नहीं है, आपको गुमराह किया गया

24.03.2026/1125/AT/AG/02

है। क्योंकि वहां पास में एंबुलेंस रोड भी बनाया जा रहा है, वहां भी मशीनरी लगेगी। उस रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। जहां से लिफ्ट बननी है वहां भी मशीनरी लगी हुई है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस लिफ्ट का काम बुजुर्गों और दिव्यांगों के हित में जल्दी शुरू किया जाएगा?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से गुमराह किया जाए। वस्तुतः स्थिति यही है कि ...(व्यवधान) एक मिनट, वह पूरी तरह सक्षम है सवाल पूछने में और जबाव हासिल करने में है तो इसमें सच्चाई यह है कि एक न्यास ने कहा कि इस काम को बढ़ाया जाए जबकि दूसरे न्यास ने कहा कि इसे रोका जाए। दूसरे न्यास ने 12 करोड़ रुपये का एक और प्रस्ताव दे दिया है कि यह लिफ्ट किसी दूसरी जगह से बनाई जाए। पहले यह 6 करोड़ रुपये की थी, अब 12 करोड़ रुपये की हो गई है। मैं चाहता हूं कि इस पर आज मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप करके फैसला कर दें। जो भी फैसला होगा, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अन्यथा सच्चाई यही है कि एक कह रहा है कि यहां बनाओ और दूसरा कह रहा है कि दूसरी जगह बनाओ पहले यह 6 करोड़ रुपये की थी और अब यह 12 करोड़ रुपये की आ गई। Whatsoever the final decision is to be taken, इस पर मुख्य मंत्री जी हस्तक्षेप कर लें और नैना देवी में वैसे भी बहुत बड़ा काम होना है, उसकी भी जानकारी आपको दे दें।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement.

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश शक्तिपीठों का प्रदेश है। जैसा कि माननीय रणधीर जी ने कहा व्यवस्था परिवर्तन, हमारी व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम नैना देवी का एक बड़ा मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां हमारे मंदिर और शक्तिपीठ हैं वहां अच्छी सुविधाएं और सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। उसी दृष्टिकोण से इसका मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1130/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या : 4024 जारी ..मुख्य मंत्री जारी ---

हमने इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रोविज़न श्री नैना देवीजी और ज्वालामुखी वाले के लिए किया है, यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि बजट में हमने पैसों के बारे में नहीं लिखा था। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात की कि विधायक मैम्बर नहीं

होते। जो भी विधायक सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र में अगर मैम्बर नहीं होगा, उसको या तो स्पैशल इनवाइटी बनाएंगे या परमानेंट इनवाइटी मैम्बर बनाएंगे क्योंकि वह वहां का पब्लिक रिप्रेज़ेंटेटिव है तो वह वहां का सदस्य होना चाहिए, यह मैं आज बताना चाहता हूं। जो हमारा धार्मिक पर्यटन है और हिमाचल प्रदेश में शक्ति पीठ हैं, वहां पर जहां प्राकृतिक सौंदर्य है वहां देवी-देवताओं का भी निवास है। **हम अगले एक साल के भीतर एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान बनाएंगे जिसमें बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रोविज़न भी कर दिया जाएगा।** मैं काफी सालों बाद वहां गया था। वहां पर बहुत ही संकरी गलियां हैं। **जितने भी वहां दुकानदार हैं, उनको अच्छा स्पेस दिया जाएगा, सीटिंग केपेसिटी भी अच्छी बनाई जाएगी, शौचालयों की भी अच्छी सुविधा दी जाएगी और उसमें सुंदरता का भी ध्यान रखा जाएगा।** जो हमारी पौराणिक सुंदरता है उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार इस पर कार्य कर रही है। अगले 6 महीने में हम रिलिजियस आर्किटेक्ट को इस काम में लगा देंगे और जहां तक आपने कहा कि मंदिरों में वहां का लोकल विधायक एक स्पैशल इंवाइटी होना चाहिए 'Irrespective of party' हम सुनिश्चित करेंगे कि उसको नोटिफिकेशन कर दी जाए।

श्री नैना देवी मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर को शॉर्टेस्ट रूट से जोड़ने के लिए सड़क के साथ झील के आर-पार Cable Ferry लगाने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। मैं वहां खुद भी देखकर आया, आप भी जाते हैं, वहां काफी नैरो स्पेस हो गया है और पिछले दिनों श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई थी तो उसका एक बेसिक कारण यह भी था। तो जो नीचे से हॉस्पिटल के पास से रोड आता है वह भी बहुत तंग रोड है। **उसको चौड़ा करने का काम इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा और जो नोमिनेशन की बात है, वह भी हम कर देंगे।**

24.03.2026/1130/केएस/एएस/2

प्रश्न संख्या : 4025

श्री केवल सिंह पठानिया : सर, वैसे मेरा प्रश्न जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित नहीं था, यह लोक निर्माण विभाग का प्रश्न था। मैंने स्क्रैप नीति के बारे में प्रश्न किया था कि मेरे

विधान सभा क्षेत्र के अंदर ही लगभग 4 टिप्पर पिछले 18 सालों से पड़े हैं। सभी डिविज़नों में करोड़ों रुपये का स्क्रैप है। प्रदेश के अंदर जितना भी स्क्रैप पड़ा हुआ है, आपके विधान सभा क्षेत्र के अंदर ककरोटी घट्टा से ऊपर जाओ तो वहां भी ट्रक पड़े हैं। सारी जगह पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी लाई जाए। मेरे यहां घृणी नामक स्थान पर लगभग 19 साल से बुलडोजर पड़ा है। मैं लोक निर्माण मंत्री जी से चाहता हूं कि कोई पॉलिसी बनाकर जो 19-19, 20-20 साल का स्क्रैप है, कमेटी बनाकर इसको डिस्पोज़ ऑफ किया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह सभी विभागों का मसला है मगर लोक निर्माण विभाग में हमारा जितना भी स्क्रैप है, स्क्रैप का मतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गाड़ियां या जो मशीन्ज़, बुलडोजर आदि रिडंडेंट हो गए हैं, and which are not in service any more. So, we will frame a policy for them in the times to come. ताकि उनका एक सही रूप से निष्पादन किया जा सके और वातावरण को भी उससे कोई नुकसान ना हो। हालांकि इसको उद्योग विभाग देखता है मगर as far as the HPPWD Department is concerned, we will instruct the officials to come up with the scheme, so that this can be done in a time frame.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बात की थी। मैं टोटल स्क्रैप की बात कर रहा हूं। मैंने भी देखा है कि स्कूलों में बैंच टेबल पड़े हुए हैं जिनसे दो-दो कमरे घिरे हुए हैं। मैडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट्स से 15-15 कमरे भरे पड़े हैं। पुलिस थानों में भी यही हाल है। **हम अगली कैबिनेट में एक स्क्रैप की पॉलिसी लाएंगे और उसमें स्क्रैप का कितने दिनों में डिस्पोज़ल करना है, क्या हमें कानून के माध्यम से डिस्पोज़ल करना पड़ेगा या नियम बनाकर यह कैबिनेट से हो जाएग, यह भी देखना पड़ेगा। कोई नीतिगत फैसला करेंगे ताकि प्रत्येक साल का टाइम-बाउंड डिस्पोज़ल हो।**

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

24.03.2026/1135/av/as/1

प्रश्न संख्या : 4025--------- क्रमागत

मुख्य मंत्री---- जारी

और वह प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हो। अभी क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज और जोनल होस्पिटल्ज में 15-15 कमरे भरे पड़े हैं। सरकारी दफ्तरों में जब कोई प्रथा शुरू हो जाती है तो वह 'क' से 'ख' लिखते ही नहीं यानी कोई उसके बारे में सोचता ही नहीं है। **अतः हम सभी विभागों के लिए यूनिफॉर्म रूल्ज लाएंगे ताकि पूरे स्क्रैप को खत्म किया जा सके।**

24.03.2026/1135/av/as/2

प्रश्न संख्या : 4026

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसोल जोकि आपदा के दौरान सौ प्रतिशत डैमेज हो गया था। जिसके लिए लोगों ने चार बिस्वा जमीन भी दी परंतु आज तक उसका कार्य शुरू नहीं किया गया। दूसरा, मैंने इसी प्रश्न में पूछा है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला बल्ह-चुराणी के भवन का एक कमरा गिर गया है। जिसको बनाने के लिए सरकार ने 2.50 लाख रुपये की राशि दी है। लेकिन जिस भवन का आपदा के दौरान एक कमरा गिर चुका है क्या वह भवन सेफ है? वहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अतः मेरा सम्माननीय मंत्री से यही आग्रह है कि आप जो कसोल के स्कूल भवन हेतु कह रहे हैं कि जमीन कम है तो वहां पर लोगों ने चार बिस्वा जमीन दान दी है जोकि एक सेफ जगह है। आपने जो वहां के लिए 24 लाख रुपये की राशि दी है, उससे उस स्कूल का भवन बन सकता है। इसके अतिरिक्त जहां तक नैन गुजरा स्कूल की बात है तो उसके लिए थोड़ी राशि बढ़ाने के साथ-साथ वहां बच्चों की सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी। अगर किसी भवन का एक कमरा गिर गया और उसको यदि आपने डिस्मेंटल कर दिया तो क्या उस भवन का दूसरा कमरा बच्चों के बैठने लायक रहता है और क्या उसके साथ दूसरा कमरा बन सकता है? मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ है जिससे हमारा विभाग भी अछूता नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमारे 1577 स्कूल प्रभावित हुए हैं और उसमें 614 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया। जहां तक बिलासपुर विधान सभा क्षेत्र का संबंध है तो वर्ष 2023 की आपदा के दौरान आपकी राजकीय प्राथमिक पाठशाला नैन गुजरा प्रभावित हुई थी। जिसके लिए लगभग 2.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसोल के लिए 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहां नैन गुजरा स्कूल में लगभग 11 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्रथम चरण में 2.50 लाख रुपये की राशि दी है। विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां वॉल का नुकसान हुआ था। परंतु

24.03.2026/1135/av/as/3

फिर भी वहां **यदि अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा।** राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसोल में 24 बच्चे एनरोल्ड हैं। वहां पर जो भूमि दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि वह कम है। यहां पर जैसे माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पर चार बिस्वा जमीन दी गई है, **अगर उसमें ड्रॉइंग एडजस्ट हो सकेगी तो निश्चित रूप से उसको भी देखा जाएगा। अगर वहां जमीन की कमी पड़ेगी तो मैं उसके लिए माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके उसमें इंटरवीन करें।**

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं सम्माननीय मंत्री से यह चाहूंगा कि इसकी ड्रॉइंग यदि तुरन्त बन जाए क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत पहले आ चुका है। परंतु ड्रॉइंग अभी तक नहीं बनी है। वहां पर जे0ई0 मौके पर गया और उसने कहा कि यहां पर भवन नहीं बन सकता तथा वहीं से सारा विषय डैफर हो गया। दूसरा, मैं मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इसके साथ दो स्कूल जी0एस0एस0एस0 चलैली और जी0एस0एस0एस0 मल्यावर में आपदा के दौरान मिट्टी गिरी थी जोकि अभी तक नहीं

हटाई गई है। इसके अतिरिक्त आपदा के बाद से जी0एस0एस0एस0 कंदरौर की छत भी टपक रही है और उसका अभी तक कोई काम नहीं करवाया गया है।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्या : 4026.... क्रमागत्

शिक्ष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राइंग का संबंध है उसे बनाने के लिए तुरंत निर्देश दे दिए जाएंगें लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जमीन कम पड़ेगी तो आप भी अपने इन्फ्लुएंस और गुड ऑफिस का इस्तेमाल करे ताकि हमारी यह प्राथमिक पाठशाला वहां बन सके। इसके अतिरिक्त आपके चुनाव क्षेत्र में जो 2-3 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी जानकारी आप मुझे लिखित रूप में दें ताकि उसमें आगामी कार्रवाई की जा सके।

प्रश्न समाप्त

24.03.2026/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

प्रश्न संख्या : 4027

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में यहां पर कई बार डिस्कशन हुआ कि पिछली सरकार के समय कुछ विधान सभा क्षेत्रों में इसके तहत 10-12 रेस्ट हाउसिज बनाए गए। क्या इन रेस्ट हाउसिज को बनाने का प्रोविजन जल जीवन मिशन के तहत था? अगर इसमें प्रावधान था तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भी 1 या 2 रेस्ट हाउसिज बना दिए जाएं। अगर इनके बनाने का प्रावधान जल जीवन मिशन के तहत नहीं था तो क्या विभाग इस पर कोई कार्रवाई करेगा?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ने सिर्फ रोहडू की बात की होती तो हम इन्हें सूचना उपलब्ध करवा देते लेकिन इन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से पूरे प्रदेश की

योजनाओं का डिटेल मांगा है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। जहां तक इन्होंने पूछा कि जल जीवन मिशन के तहत रेस्ट हाउसिज बनाने का प्रावधान था या नहीं तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य पानी उपलब्ध करवाना था लेकिन पूर्व सरकार के समय में अनेक स्थानों पर लगभग 27-28 करोड़ रुपये से रेस्ट हाउसिज बना दिए गए हैं। अब केंद्र सरकार हमसे पूछ रही है कि पानी के पैसे से रेस्ट हाउसिज कैसे बनाए गए? मैं इस विषय को बार-बार नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि इससे माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं लेकिन इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में जल जीवन मिशन से 7 रेस्ट हाउस बनाए। इसके अलावा उस समय के जल शक्ति मंत्री जी ने भी अपने चुनाव क्षेत्र में इस स्कीम के तहत 5- 6 रेस्ट हाउस बनाए हैं। इस तरह से प्रदेश में कुल मिलाकर 20-25 रेस्ट हाउस बनाए गए। अब केन्द्र सरकार हमसे कह रही है कि जो पैसा रेस्ट हाउस पर खर्च किया गया है, वह वापिस किया जाए क्योंकि यह आपकी प्रायोरिटी रही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस फंड से रेस्ट हाउसिज नहीं बनने चाहिए थे लेकिन अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वहां बने हैं तो मेरे चुनाव क्षेत्र में क्यों नहीं बन सकते? **मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब जल जीवन मिशन से रेस्ट हाउस नहीं बनेंगे लेकिन सही तरीके से ये कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर काम किया जाएगा और आपकी कांस्टीट्यूएंसी में रेस्ट हाउस बनाने के लिए जो कुछ संभव होगा, वह किया जाएगा।**

24.03.2026/1140/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

प्रश्न संख्या : 4028

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं, जैसे तीर्थन घाटी, जिभी, शांघड़, सैंज गड़सा और ग्रेट नेशनल पार्क से सटे हुए इलाके। पहले पर्यटक सिर्फ सीजन में ही आते थे लेकिन अब पर्यटक 12 महीने आ रहे हैं। सीजन के दौरान अत्यधिक भीड़ हो जाती है जिससे कारण कई घण्टों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। कई बार तो 4-5 घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसके साथ ही कई बार लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं मिलती है जिसके कारण लोग रात को अपनी गाड़ियों में ही रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे इलाके की कैरिंग कैपेसिटी

का एक सर्वे कराया जाए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दिशा में कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में वहां पर्यटन व्यवस्थित तरीके से चल सके।

एन0एस द्वारा .... जारी

24-3-2026/1145/एन0एस0-डी0सी0/1

प्रश्न संख्या : 4028----- क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि तीर्थन घाटी और जिभी में काफी पर्यटक आते हैं और अब तो बारह महीने टूरिस्ट आते रहते हैं। इन्होंने पूछा कि वहां पर होम स्टे में कैरिंग केपेस्टि़ी कितनी है और कितने बिस्तर लगे हुए हैं तो इसको हम स्टडी कर लेंगे कि वहां पर कितने होम स्टे रजिस्टर्ड हैं और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। अब प्रदेश में टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं जिसके कारण ओवर टूरिज्म ज्यादा होता जा रहा है। ओवर टूरिज्म के कारण हमारी केपेस्टि़ी पर भी फर्क पड़ रहा है। प्रदेश में किस प्रकार का टूरिस्ट आ रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा है कि इन सबको ठीक किया जाए तो इस बारे में सरकार विचार करेगी। एक बार ऐसा हुआ कि हमने मनाली में कैरिंग केपेस्टि़ी करवाई और एन0जी0टी0 वालों ने वहां उसको नहीं करने दिया। इसलिए इसे कैसे ठीक करना है, इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं और प्रदेश की वैसे भी अतिथि देवो सत्कार की प्रथा है। **उसको कैसे ठीक करना है और टूरिस्ट कैसे आ रहा है तथा उसके लिए क्या योजना लेकर आनी है तो इसके बारे में भविष्य में विचार किया जा सकता है।**

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बंजार की सड़कों की हालत बहुत खराब है। सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और नेशनल हाइवे की हालत भी बहुत खराब है। वहां पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए वहां के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए और विभागों को विशेष निर्देश दिए जाएं ताकि पर्यटकों को खराब सड़कों की वजह से दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न से संबंधित सप्लीमेंटरी नहीं पूछी लेकिन सड़कों के बारे में जरूर बता दिया। **इन्होंने कहा कि वहां पर नेशनल हाइवे में सड़कों की स्थिति खराब है तो उसके बारे में हम जरूर ध्यान रखेंगे कि टूरिस्ट सीजन से पहले या जैसे ही बजट का प्रावधान होगा तो एन0एच0 को ठीक करवा देंगे और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि टूरिस्ट सीजन में इसका कोई प्रभाव न पड़े।**

24-3-2026/1145/एन0एस0-डी0सी0/2

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, पर्यटक केवल जिभी तक नहीं आते हैं। वे मेरे क्षेत्र में रघुपुरगढ़, सरयोल्सर लेक और अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनको देखने के लिए भी आते हैं। मेरे क्षेत्र से जब हम कुल्लू जाते हैं तो वहां पर 3 से 4 घंटे का जाम रोज लग रहा है। वहां पर अगर कोई एक्सीडैंट हो जाए तो अस्पताल पहंचाना मुश्किल हो जाता है। एक बार मेरे सामने एक गाड़ी का एक्सीडैंट हुआ तो मैं उनको अपनी गाड़ी में बंजार अस्पताल ले गया लेकिन बंजार पहुंचने में ही 3 घंटे लग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां पर जलौड़ी पास में एक ही पुलिस वाला होता है और ट्रेफिक कंट्रोल नहीं हो पाती है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि गर्मियों में लगातार टूरिस्ट बढ़ता है और अब टूरिस्ट कंटीन्यूटी में आने लग गए हैं। वे लोग गूगल में सर्च करते हैं कि कुल्लू के लिए शोर्टेस्ट रूट क्या है? यह शोर्टेस्ट रूट लूहरी से आनी होते हुए जाता है। मेरे क्षेत्र आनी में भी यही समस्या पैदा हो गई है। वहां पर ट्रेफिक जाम की बहुत समस्या हो गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि वहां की सड़कें चौड़ी की जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न टूरिज्म से संबंधित था और इन्होंने सड़कों के बारे में पूछ लिया, फिर पुलिस के बारे में पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर आप अपनी डिस्क्रिशनरी पॉवर का पूरा सदुपयोग कर लेते हैं। माननीय सदस्य ने यह बहुत अच्छा कहा कि हमें टूरिस्ट सीजन के समय वहां पर पुलिस बल की व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि टूरिस्ट सीजन में लोड बढ़ता जा रहा है और वहां पर पुलिस वाले बहुत कम हैं। **जिन सड़कों में ट्रेफिक जाम होगा और टूरिस्ट की**

केपेस्टिी ज्यादा होगी तो हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी टूरिस्ट सीजन में वहां पुलिस बल की व्यवस्था जरूर करेगी।

प्रश्न संख्या 4029---- आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1150/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 4029

कुमारी अनुराधा राणाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जनजातीय भवन, भुंतर से संबंधित प्रश्न किया है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। जनजातीय भवनों में जनजातीय लोगों की निर्भरता बहुत अधिक है। हम देख रहे हैं कि हमारे दूर-दराज के लोग जब शिमला या अन्य जिलों में जाते हैं तो जो गरीब परिवार या मिडिल क्लास के लोग होते हैं वे होटलों में रहना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए ज्यादातर लोग जनजातीय भवनों पर निर्भर रहते हैं। जो जनजातीय भवन शिमला के ढल्ली में स्थित है उसकी कंडीशन भी पहले इतनी खास नहीं थी परंतु मंत्री महोदय जी के प्रयासों और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से इसके लिए उचित बजट का प्रावधान कर इसकी मरम्मत करवाई गई। यह भवन हमेशा लोगों से पैक रहता है। यहां पर ज्यादातर लाहौल-स्पिति और किन्नौर के लोग रहते हैं। अब इस भवन की हालत सुधर गई है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं जनजातीय भवन, भुंतर की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इस भवन की हालत अत्यंत दयनीय है। मैंने अभी हाल ही में खुद इस भवन का दौरा किया था। इसमें फर्निचर और बिस्तर की हालत इतनी खराब है कि वहां इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। इस भवन का संचालन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है लेकिन लोक निर्माण विभाग में पहले ही स्टाफ की कमी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इसके रख-रखाव के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि इसका संचालन जनजातीय विकास विभाग स्वयं

देखें क्योंकि लोक निर्माण विभाग में स्टाफ की काफी कमी है। वहां साफ-सफाई की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है। वहां पर बिस्तर तक उपलब्ध नहीं है और बैडशीट्स इत्यादि की हालत भी बहुत बूरी है। इस हालत में लोगों का वहां रहना बहुत मुश्किल है। शायद जानवर भी ऐसी हालत में नहीं रह पाएं। वह भवन प्राइम लोकेशन में है और इससे आय भी अच्छी हो सकती है। वहां पर लाहौल और पांगी के लोग स्टे करते हैं अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इसके लिए उचित

24.03.2026/1150/RKS/HK-2

बजट का प्रावधान किया जाए। इस भवन के चारों औ कुछ लैंड भी उपलब्ध हैं। इसलिए इस भवन का विस्तार भी किया जा सकता है और भवन को लीज आउट करके बेहतर यूज किया जा सकता है। अगर जनजातीय विभाग स्वयं इसका संचालन करेगा करे तो इससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोक निर्माण विभाग पर भी हमारी डिपेंडेंसी कम होगी।

राजस्व मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जनजातीय भवन, शिमला की हालत में काफी सुधार किया है। मैं स्वयं कई मर्तबा इस भवन में जाकर आया हूं। इसकी साफ-सफाई और हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। आज की तारीख में अगर हम जनजातीय भवन, शिमला की बात करें तो यह बहुत बेहतर स्थिति में है। हमने जनजातीय भवन, भुंतर के रख-रखाव के लिए पिछले मर्तबा 10 लाख रुपये दिए थे और उससे इसका रख-रखाव बेहतर हुआ है। परंतु इसमें अभी भी काफी कमियां हैं जिन्हें शीघ्र दूर किया जाएगा। मैं जनजातीय भवन, चंबा और धर्मशाला में भी जाकर आया हूं। मैंने इन भवनों का एक-एक कमरा चैक किया है। **आपने जो कमियां बताई हैं वे मेरे ध्यान में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां से इशारा भी कर दिया है कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी जाएगी जिससे इसको और बेहतर बनाया जाएगा।**

24.03.2026/1150/RKS/HK-3

प्रश्न संख्याः 4030

श्री दलीप सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र में कितनी योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और कितनी योजनाओं का कार्य अभी शेष है। प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि कुल 18 योजनाओं में से तीन योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 15 योजनाओं का कार्य अभी बाकी है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिन योजनाओं का कार्य 80 या 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है उस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि लोगों को समय पर पीने का पानी मिल सके। दूसरा मैंने कहा था कि मेरे चुनाव क्षेत्र में JJM के माध्यम से मेरे चुनाव क्षेत्र में 145 टैंक बने हैं। प्रश्न के उतर में दर्शाया गया है कि 22 टैंक का कार्य अभी अधूरा पड़ा है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री को तीन साल पहले बने टैंकों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। तीन साल पहले जो मेरे ही अपने गांव में टैंक बनें थे उनमें अभी तक पानी नहीं डाला गया है। ऐसे बहुत से टैंक हैं जिनमें आज तक पानी नहीं डाला गया है और उनके काम अधूरे हैं। बहुत से टैंक ऐसे हैं जो बगैर छत के हैं। उन पर न तो स्लैब पड़ी और न ही उन पर कोई टीन का ढक्कन लगा हुआ है। कुछ वैल ऐसे हैं जो खड्डे के किनारे बने हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1155/बी.एस./एच.के.-1

प्रश्न संख्याः 4030 क्रमांगत...श्री दलीप ठाकुर जारी...

उनमें भी ढक्कन नहीं हैं। हाल ही में मुझे जो जानकारी मिली थी, मैंने आपके ई0एन0सी0 को भी बताया था कि मेरे क्षेत्र सरकाघाट में एक टैंक में बंदर मर गया और बंदर मरने के बाद वह पानी लोगों को पिला दिया गया। जिससे लोगों को पीलिया हो गया। बहुत से लोग एक-एक महीने तक एम्स बिलासपुर में, मेडिकल कॉलेज नेर चौक में और अन्य जगह दाखिल रहे। वहां उनका इलाज होता रहा। इसलिए मैं उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना

चाहता हूं कि जिन टैंको के ढक्कन नहीं हैं और खुले हैं कम-से-कम उन्हें ढकने का प्रयास करें और जो टैंक बन करके तैयार हैं, जिन्हें बन करके 3-3 साल हो चुके हैं उनमें कम तक पानी डाला जाएगा और जो स्कीमें 80-90 प्रतिशत बन चुकी हैं इनका बचा हुआ कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? यह मैं उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पर है और जल जीवन मिशन की बात हो रही है। जल जीवन मिशन का बिल्कुल स्पष्ट है। सारे हाउस को हम बता चुके हैं कि जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हिमाचल को देना है और वह डिसीजन अभी नहीं हो पा रहा था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर उस पर पड़ताल करवाई जा रही थी कि जितना काम हुआ है, उसकी पड़ताल हो रही थी। जो हमें बताया गया है। पिछले साल जल जीवन मिशन में शून्य पैसा आया है। एक भी पैसा पिछले साल दिल्ली से जल जीवन मिशन के तहत नहीं आया है। हालांकि बजट निर्धारित किया गया था। वह बजट भी स्टेट को नहीं दिया गया। क्योंकि वह चाहते थे कि इसका जो कार्य हुआ है, उसकी पूरे देश में पड़ताल की जाए और उसके बाद मैंने कहा हमारे यहां भी पड़ताल हुई है और स्कीमें देखी गई हैं और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है और जो बजट उन्होंने निर्धारित किया और यह कहा कि अब जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, इसके तहत राज्यों को पैसा जारी करेंगे।

जल जीवन मिशन के तहत आपकी स्कीमों को कंप्लीट करने के लिए 43 करोड़ रुपया चाहिए। आना तो वह केंद्र से ही है जल जीवन मिशन के तहत आपको 192 करोड़ रुपया मिला है। यह बहुत अच्छी राशि आपकी कांस्टीट्यूएंसी को मिली।

24.03.2025/1155/बी.एस./एच.के.-2

आपकी कांस्टीट्यूएंसी 165 के आसपास भंडारण टैंक में बने हैं। अब कंप्लीशन का काम तभी होगा, जब केंद्र से यह 43 करोड़ रुपया आएगा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही यह पैसा आएगा तभी इन स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा और जो आप बता रहे भंडारण टैंक्स हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा।

जो आप कहते हैं कि आपके गांव में पानी नहीं आता। यह तो एक एम0एल0ए0 के लिए बात करना सही नहीं है। आप पूरी कांस्टीट्यूएंसी नहीं देख सकते हैं लेकिन अपने घर का पानी तो देख लो। आप मुझे बता देते, आप मुझे फोन करके कह देते कि मेरे यहां पानी नहीं आ रहा है तो मैं अब तक चेक करवा देता। सदन में आप अपने पानी की बात मत करो अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात करो। आपके घर के पानी के लिए मैं निर्देश करूंगा कि वहां जाकर ढंग से चेक करके आएं ताकि हमारे माननीय सदस्य को पानी उपलब्ध हो सके।

24.03.2025/1155/बी.एस./एच.के.-3

प्रश्न संख्याः 4031

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आप सौर ऊर्जा से चलने पायलट प्रोजैक्ट्स लगाएंगे जिससे आई0पी0एच0 की मशीनरी चलाई जा सके और लोगों के बिल कम आ सके। क्या उसमें मेरे विधान सभा चुनावा क्षेत्र को भी शामिल करेंगे? मैं देख रहा था कि टाहलीवाल वाला तो कवर कर लिया है, लेकिन मेरे क्षेत्र में भी आप कृपा करेंगे? ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। क्या आप इसे भविष्य में लगाएंगे, आपसे आश्वासन चाहता हूं।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राकेश कालिया जी हमारे भाई हैं। अभी सिर्फ एक स्कीम पायलट बेसिस पर सिरमौर में पांवटा साहिब के लिए चैक की जा रही है। जिसके लिए 9 करोड़ रुपया आया है। बाकी स्कीम्स के लिए कोई पैसा नहीं आया है। जैसे ही हमारा नीतिगत तौर पर यह फैसला हो जाता है, हम 44 स्कीमों को सौर ऊर्जा पर चलाना चाहते हैं और जो स्कीम राकेश कालिया जी कहेंगे, उसको भी हम उसमें जोड़ देंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1200/DT/YK-1

प्रश्न काल समाप्त

अध्यक्ष : शून्य काल में कुछ विषय मेरे पास आए हैं। सबसे पहले मैं डॉ0 जनक राज से आग्रह करूंगा कि वे अपना विषय उठाएं।

डॉ0 जनक राजः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की समस्या से संबंधित विषय उठाना चाहता हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं से भरा पड़ा है। लगभग 350 से अधिक मेगावॉट की बिजली मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पैदा हो रही है परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिजली विभाग की जो स्थिति और कार्यशैली है वह बहुत निराशाजनक है। वहां पर बिजली की तारों का स्पेन बहुत लंबा है। बिजली के ऐ पोल से दूसरे पोल की दूरी काफी अधिक है। अनेकों स्थान जैसे ग्राम पंचायत फागड़ी, चढ़ी, बजोल, कूर-इनमें पोल के स्थान पर पेड़ों के साथ बिजली की तारों को बांध दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफारमर की मांग भी है। ग्राम पंचायत धिमला के गांव गंधरा, दाड़वीं पंचायत के गांव जीडू, कर तुंदा, कुगती, खनार, ग्रोंडा,गरोला, होली आदि क्षेत्र हैं। होली क्षेत्र विद्युत उत्पादन में एक अग्रणी क्षेत्र है परंतु होली क्षेत्र की भी दो पंचायतें ग्रोंडा और लास्ट का एरिया जो बड़ा भंगाल की ओर जाता है जिसका नाम धारड़ी खनाल, वहां अनेकों वर्षों से बिजली नहीं है क्योंकि बड़ा भंगाल के लिए सड़क का कार्य चला हुआ है जिसके कारण बिजली के पोल और तारें डेमेज हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस डेमेज को जल्द-से- जल्द ठीक किया जाए। बिजली विभाग में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण वहां कर्मचारियों की कमी है। इन पदों को जल्द-से-जल्द भरा जाए और जब तक ऐसे प्रबंध नहीं होते तब तक धारड़ी, खनाल और जो अन्य क्षेत्र जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है, इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझ समय दिया-आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। विषय को संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जायेगा और की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को अवगत करवा दिया जायेगा।

श्री इंद्र सिंह गांधी जी का भी विषय था पर वे अभी अनुपस्थित हैं।

माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार जी अब आप अपना विषय रखिये।

24.03.2026/1200/DT/YK-2

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में अपनी बात रखने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र में रघुपुरगढ़ है, यह एक पर्यटन स्थल भी है और एक धार्मिक स्थल भी है। वहां पर हमारे आनी, बंजार व सराज के देवी-देवता अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए आते हैं। रघुपुरगढ़ आज पर्यटन की दृष्टि से आज देश वह प्रदेश के मानचित्र पर उभर के आया है। वहां के जो स्थानीय युवा हैं- वे चाहे थनोटी पंचायत है या टकरासी है या कराड़ पंचायत है या करसाईगार पंचायत है-वहां के जो युवा है उन लोगों ने वहां पर मेहनत करके अपने ढाबे खोले और चलाए। इससे वहां जाने वाले पर्यटकों को सुख-सुविधा मिल रही है। मैं इको टूरिज्म की पहल का स्वागत करता हूं। मैं भी इसका समर्थक हूं कि इको-टूरिज्म होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। परंतु इको-टूरिज्म के नाम पर कोई प्रभावित ह ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर 250 युवा अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। उनमें कई महिलाएं भी हैं। यानी वहां काम करने वालों की संख्या लगभग 400 के करीब है। इन 400 लोगों को इको-टूरिज्म के नाम पर उजाड़ दिया गया है। अगर सरकार इको-टूरिज्म के नाम पर वहां की भूमि किसी को देना भी चाहती है तो वे दे, लेकिन जो युवा वहां पर पहले से काम कर रहे हैं और जो सुख-सुविधा पर्यटकों को दे रहे थे, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई स्थाई नीति अपनाई जाए ताकि वहां का युवा जो उस स्थान से अपनी रोजी-रोटी कमा रहा था उस रोजी रोटी से उसको हाथ न धोना पड़े। क्योंकि वर्तमान में अगर आनी विधान सभा की बात की जाए तो चिट्टे के सबसे ज्यादा केस मेरे विधान सभा क्षेत्र में पकड़े जा रहे हैं जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है। वे युवा जो वहां पर रोजी-रोटी कमाने के लिए कार्य करते हैं अगर उनकी रोजी-रोटी पर बात आई तो कहीं वे भी नशे की ओर न चल पड़ें। इसलिए उनके लिए सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि जो लोग वहां पर रोजी-रोटी कमा रहे थे वे प्रभावित न हो। सरकार वहां पर इको-टूरिज्म जरूर चलाए लेकिन वे लोग वहां से विस्थापित न हों इस बात का भी सरकार ध्यान रखे।

अध्यक्ष श्री0एन0जी0द्वारा जारी...

24.03.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./1

श्री लोकेन्दर कुमार के पश्चात..... जारी

अध्यक्ष : आपके विषय का विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है और संबंधित विभाग को भी सूचित कर दिया जाएगा। उनसे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी लिखा जाएगा और की गई कार्रवाई से माननीय सदन व आपको सूचित कर दिया जाएगा।

अब माननीय सदस्य, श्री नीरज नैय्यर अपना विषय रखेंगे।

(माननीय सदस्य, श्री नीरज नैय्यर द्वारा शून्य काल के दौरान मनरेगा पोर्टल बंद होने से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

24.03.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./2

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सितंबर-2025 में प्रदेश ने सबसे बड़ी आपदा का सामना किया था। उस दौरान प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने आपदा को देखते हुए मनरेगा के जो शैल्फ्स थे, जिनके अंतर्गत पहले यह नियम रखा गया था कि 20 से ऊपर जब तक काम पूरे नहीं होंगे तब तक नया काम शुरू नहीं होगा, उस नियम में छूट देते हुए शैल्फ्स खोल दिए थे। उसके बाद आपदा के दौरान मैं भी अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर जगह-जगह पर गया, जहां काफी नुकसान हुआ था लेकिन दिसंबर महीने के अंदर अचानक मनरेगा का पोर्टल बंद कर दिया गया। इसके कारण यह हुआ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैहला और चम्बा ब्लॉक में तकरीबन 1000-1500 परिवार ऐसे हैं, जिनका नुकसान,

जैसे डंगों का नुकसान, सार्वजनिक रास्तों का नुकसान, काफी हुआ। लेकिन उनकी भरपाई पोर्टल बंद होने के कारण नहीं हो पाई।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और पूरे सदन से कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर यह समस्या हुई है। मैं चाहूंगा कि एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रदेश सरकार के माध्यम से भेजा जाए ताकि जो लोग इन योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें विशेष छूट मिल सके। क्योंकि सारी पटवारी रिपोर्टें और अन्य सभी आवश्यक प्रक्रियाएं बी0डी0ओ0 स्तर तक पूरी हो चुकी हैं लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि दिसंबर महीने में अचानक पोर्टल बंद हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित नहीं किया गया और आपको पता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए लगभग 1000-1500 लोग मेरे विधान सभा क्षेत्र में और आपके व अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी, पोर्टल बंद होने के कारण वंचित रह गए हैं। मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इसे गंभीरता

से लेते हुए केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया जाए। क्योंकि अभी VB-G-RAM-G योजना आई है और उसके अंतर्गत यह नियम है कि 10 काम पूरे होने के बाद ही अगली स्वीकृति मिलेगी। लेकिन यह आपदा बहुत बड़ी थी और मुझे लगता है कि अगर इस विशेष कारण से पोर्टल नहीं खोला गया तो बहुत सारे लोग इन योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी, क्या आप इंटरवीन करना चाहते हैं?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक, श्री नीरज नैय्यर जी ने जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके ऊपर चर्चा की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मनरेगा का पोर्टल केन्द्र सरकार द्वारा लॉक किया गया है। यह पोर्टल नए वित्तीय वर्ष में खुलेगा और 90:10 के अनुपात वाले कार्यों को पूरा करने के लिए 2 माह का समय दिया गया है क्योंकि VB-G-RAM-G योजना आ गई है और उसकी तैयारियां चल रही हैं। जो पुराने कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए केवल दो महीने का समय दिया गया है इसलिए यह लॉक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। धन्यवाद।

(माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा द्वारा शून्य काल के दौरान प्रदेश के साथ लगते राज्यों व ट्राइसिटी में निजि स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा ओ0पी0डी0 शुल्क में हुई बढ़ौतरी से हो रही समस्याओं के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

24.03.2026/1205/वाई.के.-एन.जी./4

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा अपना विषय उठाएंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर के माध्यम से यह विषय उठाने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे वे अधिकारी हों या कर्मचारी हों वे विभिन्न अस्पताल जोकि ट्राइसिटी, चण्डीगढ़, पंचकुला व मोहाली में

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0/-01

शून्य काल जारी .....

श्री हरदीप सिंह बावा जारी ...

जोकि ट्राइसिटी, चण्डीगढ़, पंचकुला व मोहाली में हैं। इन सब जगह जहां ये हॉस्पिटल्स हिमाचल गवर्नमेंट के साथ इम्पैनल्ड हैं। यहाँ पर एका-एक हॉस्पिटल के द्वारा ओ0पी0डी0 चार्जेज को बढ़ा दिया गया है। ये जिस तरह से चार्जेज बढ़े हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि इसका सीधा असर गवर्नमेंट एक्सचेकर पर पड़ेगा। जहां तक सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा एकदम इस तरीके का फैसला करना जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के इम्प्लॉइज या हिमाचल प्रदेश के अधिकारी इन सबके ऊपर इससे बोझ पड़ा है। इससे अल्टिमेटली इन प्रिंसिपल ये बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। मेरी इस सदन के माध्यम से गुजारिश है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस मामले पर इंटरवीन करें। मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल की पर्ची है। इस पर्ची को मैं हाउस में ले करना चाहता हूं। यह एक व्यक्ति की पर्ची है जिसमें इस व्यक्ति ने दिनांक 24-02-2025 को ओ0पी0डी0 करवाई थी। उस समय इनसे 350 रुपये पर्ची के लिये थे। इसके बाद जब वही व्यक्ति दिनांक 03-02-2026 को दोबारा ओ0पी0डी0 के लिए गया तो पर्ची की राशि बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया। मैं चाहता हूं, इस विषय में सरकार इंटरवीन करे और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर नकेल डाले ताकि ये बढ़ी हुई राशि को कम किया जाए, धन्यवाद।

(**पर्ची की प्रति को सभा पटल पर रखा गया।**)

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय आपने इस माननीय सदन के ध्यान में लाया है और इस पर विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। हम विभाग से कहेंगे कि इस विषय के ऊपर कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से आपको और सदन को सूचित कर दिया जाएगा।

24.03.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0/-02

नाचन विधानसभा क्षेत्र में जॉन्डिस की गंभीर समस्या

अध्यक्ष : माननीय श्री विनोद कुमार जी।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र की सब-डिवीजन गोहर में पिछले लगभग दो महीनों से जॉन्डिस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जॉन्डिस के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नौजवान बच्चों की मृत्यु भी हो गई है। एक उदित शर्मा सुपुत्र श्री दीपक शर्मा गांव दाड़ी। इस बच्चे की आयु 29 वर्ष थी और परिवार का एक लौता बेटा था, जिसकी मृत्यु जॉन्डिस के कारण हुई है। दूसरा सानिया वाइफ ऑफ श्री सौरव, गांव रौड़ी। इस बेटी की आयु 19 वर्ष थी। इस बेटी की मृत्यु भी जॉन्डिस के कारण हुई है। अभी भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की गोहर सब-डिवीजन में लगभग 250 ऐसे लोग हैं जोकि जॉन्डिस से जूझ रहे हैं। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि पिछले दो महीने से लगातार न्यूज पेपर में भी न्यूज आ रही है। मैंने विभाग के अधिकारियों से एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय पर बात की है। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि किस कारण से जॉन्डिस हो रहा है, उसके कारणों का पता किया जाए ताकि उस क्षेत्र में जहां पर जॉन्डिस फैल रहा है। उससे उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

अध्यक्ष : निश्चिततौर पर बहुत ही गंभीर विषय आपने इस माननीय सदन के ध्यान में लाया है। इस पर विधान सभा सचिवालय ने संज्ञान लिया है। इस विषय को हम संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे और इस पर की गई कार्रवाई से आपको और सदन को सूचित कर दिया जाएगा। सदन यह चाहेगा कि इस विषय पर जल्द आवश्यक कार्रवाई हो।

24.03.2026/1210/ए0जी0/ए0पी0/-03

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी जो पहले रह गये थे।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुकेती खड्ड के साथ नगर परिषद वार्ड न0. 9 डडौर से जुड़ा है जोकि नेरचौक में आता है, जिसे कबाड़ मार्किट बोला जाता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1215/AT/AG/01

श्री इन्द्र सिंह गांधी जारी...

लेकिन बरसात की वजह से जैसे वर्ष 2013 में त्रासदी हुई थी और वर्ष 2025 में जो त्रासदी हुई उस के कारण वहां लगातार इरोजन हुआ है। इरोजन के कारण PWD विभाग की सड़क लगभग 300 मीटर तक नष्ट हो गई है। जैसे ही BBMB की नहर में सिल्ट आती है उस कारण पानी का लेवल भी बढ़ जाता है और हमारी सड़क ध्वस्त हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि वहां कुवाड़ मार्केट में जो मकान और घर हैं उन्हें बहुत खतरा है। मैंने बार-बार इस मुद्दे को इस सदन में उठाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां रहने वाले लोगों के लिए सड़क के किनारे प्रोटेक्शन वॉल या कोई अन्य समाधान किया जाए ताकि सड़क भी सुरक्षित रहे और वहां रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा मिल सके जो कुवाड़ मार्केट, वार्ड नंबर-9 में है। मैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इसमें संज्ञान ले, अन्यथा आगे जब बरसात आएगी तो फिर ऐसी स्थिति न बने। धन्यवाद।

Speaker : Again, a very important issue has been brought to the notice of this Hon'ble House. We will certainly ask the concerned department to take action in this behalf, and whatever action is to be taken by the department in this behalf, the Hon'ble Member will be informed accordingly, as well as the House also.

इससे पहले कि मैं अगली आइटम लूं, आज माननीय सदन की कार्यवाही देखने के लिए हमारे माननीय सदस्य हरदीप सिंह बावा जी की धर्मपत्नी भी इस हाउस में उपस्थित हैं। इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज के छात्र भी आज विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए हमारी गैलरी में बैठे हैं। साथ में अन्य तीन-चार शिक्षण संस्थानों के छात्र भी यहां विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं और यहां

और भी छात्र कार्यवाही देखने के लिए बैठे थे। अब शून्य काल समाप्त होता है। अब कागज़ात सभा पटल पर रखें जाएंगे।

शून्य काल समाप्त

24.03.2026/1215/AT/AG/02

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री जी कागजात सभा पटल पर रखेंगे।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा-27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।
शिक्षा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 15 की उपधारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तथा लेखा कथन रिपोर्ट, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित दस्तसवेजों की प्रति एक- एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 127वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 179वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 128वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 60वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित है; और

24.03.2026/1215/AT/AG/03

(3) समिति का 129वां कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 61वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में

3. अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब किशोरी लाल सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे::-

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक- -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः- :-

(1) समिति का 30वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) पर बने 22वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

24.03.2026/1215/AT/AG/04

अध्यक्ष : अब आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदन की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की प्रति एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का 15वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि सामान्य प्रशासन विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(2) समिति का 16वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि राजस्व विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

अध्यक्षः अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों और वार्षिक वित्तीय विवरण पर आगे चर्चा प्रारंभ होगी और मेरे पास कांग्रेस विधायक दल के 9 माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि,

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1220/केएस/एएस/1

अध्यक्ष जारी ----

भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई भी लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है और क्योंकि लास्ट स्पीकर भारतीय जनता पार्टी से थे, तो अब मैं माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ को चर्चा हेतु आमंत्रित करुंगा । कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि आज 9 माननीय सदस्य तो कांग्रेस से हैं और लगभग इतनी ही सूची भारतीय जनता पार्टी से भी होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि समय का ध्यान रखें और 10 से 12 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और हमारे प्रदेश के साधन बहुत ही सीमित हैं। फोरैस्ट कवर ज्यादा होने की वजह से संसाधनों में कमी आती है। जो आर0डी0जी0 केंद्र द्वारा प्रदेश को मिलती थी वह 16वें वित्तायोग की सिफारिश से बंद कर दी गई है। मैं समझता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो फोरैस्ट कवर है, हम लोग Indian Institute of Forest Management (IIFM) के दिशा-निर्देश के अनुसार लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की इकोलॉजिकल सर्विसिज़ इस देश को देते हैं। हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ इंडिया के लंग्ज़ से भी जाना जाता है और जो जल हिमाचल प्रदेश से पूरे देश में जाता है, उसकी वजह से Water Ball of the Country के नाम से भी जाना जाता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो आर0डी0जी0 हिमाचल को मिलना बंद हुई है, मैं समझता हूं कि जो बजट माननीय मुख्य मंत्री ठाकुर सुखवन्दर सिंह सुक्खू जी ने हमारे समक्ष रखा है, यह सराहनीय है क्योंकि आर0डी0जी0 तो बंद हुई ही है परंतु जो हमें जी0एस0टी0 मिलता था उसकी वजह से भी लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का लॉस पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को हुआ है। बजट में प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। जितने आपके डिपार्टमैंट्स हैं, सभी में नई स्कीम्ज़ लाई गईं हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र होर्टिकल्चर और टूरिज्म पर निर्भर है इसलिए मैं मुख्य रूप से उन पर फोकस करुंगा। क्योंकि हम टूरिज्म से हिमाचल प्रदेश की लगभग 7.78 परसेंट जी0डी0पी0 कंट्रीब्यूट

करते हैं। टूरिज्म के लिए जो विशेष पैकेजिज़ माननीय मुख्य मंत्री जी ले कर आए हैं, मैं समझता हूं उनसे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हम चाहे कांगड़ा एयरपोर्ट की बात करें या भुभू जोत टनल बन कर जो रास्ता कुल्लू से कांगड़ा के लिए जाएगा, मैं समझता हूं कि उससे भी हमारे क्षेत्र को काफी बूस्ट मिलेगा। जो नई स्कीमें मुख्य मंत्री

24.03.2026/1220/केएस/एएस/2

जी ने इस बजट में दर्शायी हैं, जो आपका **Himalayan Ocarina Project for Entrepreneurs (HOPE)** है, जिसने रिकमेंड किया है कि स्लो टूरिज्म को हम किस तरह से गांव-गांव में ले जाए। जो पर्यटक विदेशों तथा देश के अन्य भागों से हिमाचल प्रदेश आते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति, अपना खान-पान, हमारे क्षेत्र की जो नाटी है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हम

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

24.03.2026/1225/av/as/1

श्री भुवनेश्वर गौड़---- जारी

किस तरह से दर्शाए। किस तरह से हमारे गांव-गांव में नये रेस्टोरैंट्स और ढाबे खुले जिससे हमारे गांवों में बस रहे लोगों को राजस्व प्राप्त हों। गांवों में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु 'एच0 पी0 विमन टूरिज्म फण्ड' के तहत तीन लाख रुपये की सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और विमन स्टार्टअप्स को दी जाएगी। यह बताते हुए बहुत खुशी होती है कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में जो एकल महिलाएं आई हैं उसमें शिमला और मनाली को सबसे सुरक्षित स्थान घोषित किया गया है। हमारी महिलाएं जब अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करेगी तो मैं समझता हूं कि उससे हमारे टूरिज्म में ज्यादा इज़ाफा होगा। टूरिज्म के लिए एक और स्कीम लाई जा रही है। वह स्कीम 'कारवां' के नाम से लाई गई है। कारवां टूरिज्म वह टूरिज्म है जिसमें जो भी टूरिस्ट्स अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने आएंगे वे इन कारवां को हायर करेंगे और उसके हिसाब से ट्रैवल करेंगे। जहां पर कारवां पार्क्स बनेंगे मैं समझता हूं कि उनको भी विकसित करने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि विदेशों में भी इन पार्क्स में बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं।

इनमें मण्डी और सोलन को इंक्लूड किया गया है। मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन रहेगा कि इस स्कीम को हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन्ज में भी लागू किया जाए ताकि हमारी ओर भी ज्यादा-से-ज्यादा पर्यटक रुख करें।

यहां पर वीक एंड टूरिज्म की बात भी हुई है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तीन दिन पहली थोड़ी-सी बारिश हुई है। इस बारिश की वजह से नेशनल हाईवे चण्डीगढ़-मनाली जगह-जगह से टूट गया क्योंकि पिछली बरसात में यह नेशनल हाईवे बहुत जगह से क्षतिग्रस्त हुआ था। मुझे याद है केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री अजय टम्टा जी और हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में आए थे। उस समय इन्हें मैं भी मिला था और हमें यह कहा गया था कि आने वाले समय में नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी वल्नरेबल प्वाइंट्स पर आर0सी0सी0 का कार्य किया जाएगा। परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी वह कार्य नहीं किया गया। उसी वजह से पिछले तीन दिन पहले हमारे क्षेत्र में जो थोड़ी-सी बारिश हुई है उसके कारण वह रोड जगह-जगह से टूट गई है। जिससे आने वाले टूरिस्ट सीजन के दौरान पर्यटकों को बहुत प्रोब्लम होगी।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

24.03.2026/1225/av/as/2

बहुत सारे टूरिस्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आने से पहले रोड्ज की कंडीशन चैक करते हैं और इस प्रकार की स्थिति में वे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। मेरा केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय से आग्रह रहेगा कि जो प्रोटैक्शन वर्क इस सड़क पर जगह-जगह होना है, उसको तेजी से किया जाए ताकि आने वाले सीजन से पहले यह सड़क तैयार हो और जिस वीक एण्ड टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से चला सकें।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री भुवनेश्वर गौड़.... जारी

पिछले वर्ष भी फ्लैश फ्लड की वजह से हमारा टूरिस्ट सीजन बहुत खराब हुआ जिसके कारण स्टेट के रेवेन्यू और जी0डी0पी0 में भी काफी कमी आई। इस समय पर्यटन सीजन हमारे सामने है, खाड़ी युद्ध शुरू हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं वह हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। जब सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं होंगे तो जो टूरिस्ट मनाली आएगा, वह अपने भोजन और अन्य व्यवस्थाएं कैसे करेगा? मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से संबंधिति क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से कोटा दिया जाए ताकि कमर्शियल सिलेंडर की कमी से टूरिज्म पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भरपाई की जा सके। टूरिज्म की बात के साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि बी0पी0एल0 फैमिलीज को लेकर बजट में जो बात कही गई है उसके तहत लगभग 28000 ऐसी फैमिलीज हैं जो बी0पी0एल0 में नहीं हैं लेकिन गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्हें चिन्हित करके मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी और साथ में 1500 रुपये की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान राशि के रूप में दिए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारी महिलाओं के लिए सिलाई, बुटीक, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी पार्लर आदि कार्यों के लिए सरकार 1,00000 रुपये तक की सहायता महिला विकास निगम के माध्यम से देगी। बी0पी0एल0 परिवारों की जिन लड़कियों का विवाह होना है उनकी सहायता राशि भी बढ़ाकर लगभग 51000 रुपये कर दी गई है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मनाली में टूरिज्म को बढ़ाने और सौंदर्यकरण को और बेहतर बनाने की जो बात मुख्य मंत्री जी ने कही है उसके लिए भी मैं इनका क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद। कुल्लू हॉस्पिटल में कैथ लैब बनाने की सुविधा के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, उससे क्षेत्रवासियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी।

आज के समय में एक नई पहल मुख्य मंत्री जी द्वारा लाई गई है जिसमें उन्होंने अपनी सैलरी में 50 प्रतिशत कटौती करने की बात कही है, उन्होंने मंत्रियों और विधायकों की

24.03.2026/1230/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

सैलरी में भी कटौती करने की बात कही है। मैं समझता हूं यह एक बहुत बड़ी सोच है। इससे बहुत क्लियर मैसिज जाता है कि सरकार अपने वेतन में भी कटौती करके प्रदेश को किस तरह आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है और इस मुश्किल समय में किस तरह से प्रयासरत है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे वह यू0एस0ए0 के साथ हुए, न्यूजीलैंड के साथ हुए या यूरोप के साथ हुए उसमें सेब पर जो ड्यूटी थी वह खत्म कर दी गई है। हिमाचल में एप्पल से जो रेवेन्यू आता है, वह तकरीबन 5000 करोड़ रुपये का है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्रवासियों को यानी जो हम सेब का उत्पादन करते है

एन0एस द्वारा .... जारी

24-3-2026/1235/एन0एस0-डी0सी0/1

श्री भुवनेश्वर -----जारी

हम सभी को बहुत कठिनाई आने वाली है क्योंकि सीजन में अगर हम लोगों को अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे, कंपीटेटिव रेट्स नहीं मिलेंगे तो इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा और मेरे क्षेत्र के छोटे व मार्जिनल फॉर्मर्स को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में श्री रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, दिनांक 21 मार्च, 2026 को मुख्य मंत्री जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया है और यहां पर इतना लम्बा बजट भाषण दिया जो इतिहास में एक रिकॉर्ड बन गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट भाषण बजट पर कम केंद्रित था और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक उद्देश्य पर दिया गया भाषण था। इस भाषण को अगर राजनीतिक भाषण बोला जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि बजट भाषण में बजट अनुमान, बजट प्रावधान और ज्यादा-से-ज्यादा अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा

होती है लेकिन इस बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने अधिकतर समय केंद्र सरकार व हिमाचल प्रदेश विधान सभा के विपक्ष और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसने में लगा दिया। मुख्य मंत्री जी पानी पी-पी कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रदेश की पूर्व सरकार तथा अबके विपक्ष की आलोचना करते रहे। मुझे लगता है कि इससे यह बात स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के फोबिया से ग्रस्त हैं। हालांकि, राजनीतिक आलोचना करने व विपक्ष की आलोचना करने के लिए अनेक मंच होते हैं। इस बजट भाषण में भी मुख्य मंत्री जी ने आलोचना ही की है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी भाजपा फोबिया से ग्रस्त हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बात आर0डी0जी0 के बारे में की जा रही है तो हमने पहले भी इस विषय पर विधान सभा के अंदर व बाहर बातें की हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी इस विषय को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है और वे जानते हैं कि जब 15वें वित्तायोग ने आर0डी0जी0 टेपरिंग ग्रांट

24-3-2026/1235/एन0एस0-डी0सी0/2

के रूप में दी थी तो अल्टीमेटली बंद होनी ही थी। अब जब बंद हो गई तो ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को भुनाया जाए और इस दृष्टि से मुख्य मंत्री जी व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भाषण दे रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि यह प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था और संविधान के आर्टिकल 275 (1) और 280 हमने भी पढ़े हैं। उसमें कहीं भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट शब्द नहीं आता है। फिर आर0डी0जी0 कहां से संवैधानिक अधिकार हो गया? सेंटर फाइनैंस कमीशन की रिकोमेंडेशन पर ग्रांटस देगा, यह इनमें लिखा हुआ है। सभापति महोदय, ग्रांटस तो आ रही हैं और पहले से भी ज्यादा आ रही हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाओं या शहरी निकायों की बात हो। उस ग्रांट में इस बार 2000 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी हुई है। ...(व्यवधान) अनटाइड ग्रांट जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलनी है। मैं भी जानता हूं कि अनटाइड

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1240/RKS/HK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी.....

आप जो ग्रांट चाहते हैं लेकिन अब यह ग्रांट नहीं मिलेगी। मैं भी जानता हूं कि अनटाइड ग्रांट की चर्चा हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि RDG इसलिए दी जाती थी ताकि आप अपना राजस्व घाटा समाप्त करें। परंतु दुःख का विषय यह है कि हिमाचल ने उस RDG का उपयोग राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए नहीं किया। हिमाचल सरकार ने इस RDG का उपयोग अपने लोक-लुभावन वायदों को पूरा करने के लिए किया जिसके कारण स्थिति यहां तक पहुंच गई। मैं माननीय संजय अवस्थी जी को बताना चाहता हूं कि बाप अपने बेटे को एक ही उम्र तक खर्चा देता है।अगर 25-30 साल तक बेटा खुद न कमाए तो बाप कब तक खर्चा देगा? हिमाचल 55 साल का हो गया है। जब बेटा काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो बाप के पास यही चारा है कि उसे खर्चा देना बंद किया जाए ताकि वह मजबूरी में कमाना शुरू कर दे और खुद भी खाए और परिवार को भी खिलाएं। हिमाचल ने अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास नहीं किया। ...(व्यवधान) हिमाचल की पैतृक संपत्ति आपकी है। हिमाचल की पैतृक संपत्ति को कोई नहीं ले रहा है। ...(व्यवधान) अवस्थी जी, इसे कोई नहीं छीन रहा है परंतु इसका सही उपयोग करना चाहिए। अवस्थी जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी RDG बंद होने के बाद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, आदरणीय पी0 चिदंबरम जी से मिले थे। अगर यह संवैधानिक अधिकार होता तो श्री पी0 चिदंबरम जी कोर्ट जाने की सलाह देते। जब उन्होंने कहा कि इस पर कुछ नहीं होना है तभी आप कोर्ट नहीं गए। फिर आपने सोचा कि अब राजनीति कर लो क्योंकि होना तो कुछ नहीं है। आपने RDG पर चर्चा करवाकर सरकारी संकल्प पारित किया और उसके बाद इतिहास कायम कर सदन को 30 दिन तक स्थगित कर दिया। आपने कहा कि हम RDG को लेकर माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री से मिलेंगे परंतु अब इस पर क्या हुआ? मुख्य मंत्री जी चार दिन दिल्ली रहकर आ गए लेकिन वे न तो प्रधान मंत्री जी से मिले और न ही वित्त मंत्री जी से मिले। इससे पता चलता

है कि RDG के प्रति आपकी कितनी गंभीरता है। वहां क्या किया, यह अलग विषय है और इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। यह आज का विषय

24.03.2026/1240/RKS/HK-2

नहीं है परंतु इसका मतलब यह है कि आप RDG को लेकर गंभीर नहीं है और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में मुख्य मंत्री जी कुछ कड़े फैसले और सही निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते तो अच्छा होता परंतु इस बजट में कहीं भी वे प्रयास नहीं दिख रहे हैं। मात्र कुछ परसेंट सैलरी में अस्थायी कटौती करके छह महीनों के भीतर प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आपको अनेक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आपको फिजूलखर्ची पूरी तरह से बंद करनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस लानी पड़ेगी। आपको एक्साइज पोलिसी में सुधार करना पड़ेगा, माइनिंग पोलिस बनानी पड़ेगी। आपको पर्यटन के क्षेत्र में नये डेस्टिनेशन डवलप करने पड़ेंगे। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि नई परिस्थितियों में आपको अपनी चुनावी गारंटीयों पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। शायद वित्त विभाग ने आपको यह सलाह भी दी थी। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वित्त विभाग ने आपको यह सलाह दी थी परंतु आपने उस सलाह को नहीं माना। आपने वही रास्ता चुना कि

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1245/बी.एस./ एच.के.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबोते जाओ और घी पीते जाओ। उसी रास्ते पर आपने चलना शुरू कर दिया और यह बजट न तो आर्थिक सुधारों को लेकर है, न वित्तीय अनुशासन को

दर्शाने वाला बजट है और न ही फिजूल खर्ची को कम करने वाला बजट है। यह बजट तो पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल पर चलने वाला बजट है। आपने इसमें थोड़ा पॉलिटिकल फ्लेवर डाल दिया है। बाकी इस बजट में कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, अगर मैं इस बजट की चर्चा करूं तो वित्तीय वर्ष 2026-27 54,928 करोड़ रुपये का बजट है। यह बजट 3586 करोड़ रुपये कम हो गया। यह चिंता का विषय है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि आर0डी0जी खत्म हो गई इसलिए कम हो गया। यह सिंपल बहाना है, यह तो अनपढ़ भी कर सकता है। इसे तो कोई भी कर सकता है। आपकी कुशलता तब होती अगर आप आर0डी0जी0 बंद होने के बाद भी बजट आकार को बढ़ाते। अगर बढ़ाते नहीं तो कम से कम वहीं बनाए रखते। परंतु आपने आर0डी0जी0 का बहाना लेकर बजट का आकार कम कर दिया। अब उसके क्या परिणाम होंगे आप देखते जाइए।

मैं बताना चाहता हूं कि बजट का आकार कम होने का कारण सिर्फ आर0डी0जी0 बंद होना नहीं है। अगर आर0डी0जी0 बंद हुई है तो केंद्र सरकार ने उसकी एवज में भरपाई के लिए अन्य अनुदान बढ़ाए हैं। सेंट्रल टैक्स के शेयर में बढ़ोतरी की है और अगर उन बढ़ोतरियों को देखा जाए, तो आर0डी0जी0 को कंपेनसेट करने का प्रयास हुआ है। परंतु आपकी जो अपनी कमियां रही हैं उसके कारण आपके बजट का आकार कम हुआ है। अब मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। आप बजट के अंदर राजस्व प्राप्तियों की ओर नजर डालिए। आपकी रेवेन्यू रिसप्ट क्या कहती है, क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है? आपकी राजस्व प्राप्तियों में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, उतनी नहीं हो रही। जितने टैक्स आपने लगा दिए हैं जितने कर आपने लगा लिए हैं उस हिसाब से तो राजस्व प्राप्तियां कई गुना बढ़नी चाहिए थी।

आपकी हालत यह है कि इस बार आपने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां कम हो जाएंगी। वर्ष 2025-26 में 44,537 करोड़ रुपये और अनुमान है कि वर्ष 2026-27 में 40,361 करोड़ रुपये रह जाएंगी।

24.03.2025/1245/बी.एस./ एच.के.-2

इससे पहले भी अगर पिछले आंकड़ों को देखें तो बढ़ोतरी थोड़ी ठीक रही हैं। वर्ष 2023-24 में 40,446 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2024-25 में 43,704 करोड़ रुपये हुई। परंतु पिछले साल 43,704 करोड़ रुपये से बढ़ कर 44,537 करोड़ पर रह गई। अगर राजस्व प्राप्तियों की डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि स्टेट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि कमी हो रही है। अब सवाल यह है कि स्टेट टैक्स कलेक्शन में कमी क्यों हो रही है? उस पर आप विचार करें। वर्ष 2024-25 में 26.78 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 28.27 प्रतिशत और इस बार 28.55 प्रतिशत रही है। यह बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है?

इसके पीछे कारण वही है, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। आपने टैक्स बढ़ाकर चीजों को इतना महंगा कर दिया है कि लोग हिमाचल में खरीदने की बजाय बाहर से खरीद रहे हैं। हिमाचल में बिक्री कम हो रही है। जब बिक्री कम होगी तो टैक्स भी कम आएगा। यह टैक्स बढ़ाने का नुकसान है, जिसे आप समझ नहीं रहे हैं।

पिछले दिनों खबर आई थी कि मुख्य मंत्री चंडीगढ़ गए थे। हालांकि, यह मेरा विषय नहीं है। परंतु उनके सिक्योरिटी वाले चंडीगढ़ में एक

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1250/DT/YK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी..

किसी वाइन शॉप पर वाइन खरीदने लगे। क्यों खरीदने लगे? आपने शायद इस पर कोई कार्रवाई की होगी परंतु मुझे इसका पता नहीं है। अब यह समझने की जरूरत है कि वे चंडीगढ़ में वाइन क्यों खरीद रहे थे। क्योंकि चंडीगढ़ में हिमाचल से बहुत ज्यादा सस्ती शराब बिकती है। आपने इतने टैक्स लगा दिए हैं की शराब महंगी कर दी गई है। हम अपने पड़ोसी राज्यों से शराब खरीदते हैं। हम चंडीगढ़ से शराब खरीदते हैं। जब आपकी सेल कम होगी और फिर आप टैक्स बढ़ा भी दें तो अल्टीमेटली आपकी टैक्स कॉलेक्शन इफेक्ट हो जाएगी। ...(व्यवधान) स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोकना तो आपका ही काम है। इसलिए जो बिना सोचे समझे सरकार की टैक्स बढ़ाने की पोलिसी है यह आपको फायदा

नहीं दे रही है। आप जनता पर बोझ डाल रहे हैं। आज फोरलेन बन गए हैं और लोग चंडीगढ़ जाकर शॉपिंग करते हैं। यहां तक कि अब तो लोग राशन भी पंजाब से लाते हैं क्योंकि आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसलिए यह जो टैक्स कॉलैक्शन का विषय है इस पर सरकार को देखना चाहिए। हमने पिछले कल भी इस पर बात की थी। अब अगर हम बजट के पैमानों की बात करें तो कल हमारे श्री भवानी सिंह पठानिया जी उछल-उछल कर बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने प्रति व्यक्ति आय केंद्र से ज्यादा बढ़ा दी है। ...(व्यवधान) अब मैं बताना चाहता हूं कि आपकी प्रति व्यक्ति आय अगर राष्ट्रीय स्तर से 57 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है तो वर्ष 2021-22 में जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तब भी हमारी प्रति व्यक्ति आय 2,01,854 रुपए प्रति व्यक्ति थी और राष्ट्रीय स्तर 51,528 रुपये ज्यादा थी। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। हिमाचल की पर कैपिटा इनकम पहले से ज्यादा है। ...(व्यवधान)सेब की फसल इन तीन सालों में नहीं होने लगी है। यहां सेब की फसल पहले से ही हो रही है। यह फसल सुक्खू सरकार ने नहीं लाई है। इसलिए समय-समय पर सब सरकारों ने काम किया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में हमारी केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाओं का भी असर है जिनके कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इसके लिए भी हम प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आपकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उतनी है जितनी वर्ष 2021-22 में श्री जय राम ठाकुर जी के सरकार के समय 8.3 प्रतिशत थी। आपके बजट के पैरामीटर कोई ऐसे नहीं है जिन पर आप बजट की तारीफ कर सकें। सकल घरेलू उत्पाद बजट का महत्वपूर्ण

24.03.2026/1250/DT/YK-2

पैरामीटर है। मैंने इस विषय पर पिछले साल भी चर्चा की थी। इस पर सरकार ध्यान नहीं देती लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम अपना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाते नहीं है। हमें जी0एस0डी0पी0 बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि आप सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत कर्ज ले सकते हैं। कर्ज की लिमिट सकल घरेलू उत्पाद से तय होती है। कर्ज की लिमिट कोई सरकार तय नहीं करती। आप आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी कर्ज की लिमिट तय की है। अगर आपका सकल घरेलू उत्पाद 2.54 लाख करोड़ रुपये है

तो तीन परसेंट तक ही आप कर्ज ले सकते हैं। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाया जाए। आप इसको कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए । परंतु आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि आपको बल्क ड्रग्स पार्क नहीं चाहिए। आप सस्ती जमीन नहीं दे सकते। आप हर जगह पैसे की बात करेंगे। यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट तभी आएंगे जब उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इंडस्ट्री तब आई थी जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, इंसेंटिव दिए थे। उस समय ही यहां इंडस्ट्रीज आई थी। लेकिन डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने वह पैकेज वापिस ले लिया था, उसकी समय- सीमा कम की थी। आज जो उद्योगपति यहां आ रहे हैं उनको इंसेंटिव ही नहीं दे रहे हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

24.03.2026/1255/वाई.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा..... जारी

जो पिछली सरकार ने दिए, उनको भी छीन रहे हैं तो क्यों आएगा इंडस्ट्रियलिस्ट? हिमाचल में जो बिजली सस्ती होने का एक इंसेंटिव था, उसको भी आपकी सरकार ने 20 प्रतिशत बढ़ाकर महंगा कर दिया। नई इंडस्ट्रीज़ आनी तो दूर की बात है परंतु पुरानी इंडस्ट्रीज़ भी छोड़कर जा रही हैं। इसलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आपकी सरकार नए शहर भी डवलप नहीं कर रही है और इसके बारे में अब जाकर सोचने लगे हैं, जब समय विदाई का आ गया। अब कब शहर बनेंगे, कब नहीं परंतु हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान होना था, वह हो गया। राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कम होना बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। राजकोषीय घाटा जो है, वह राज्य सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत ही होना चाहिए लेकिन आज चार प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गया है और यह इससे भी बड़ा चिंता का विषय है इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, हमें इस बजट से एक और उम्मीद थी कि आप आर0डी0जी0 बंद होने का बहाना बनाकर ही कुछ करेंगे, हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा ग्रांट बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश को कंपेन्सेट किया गया है।...(घण्टी)... सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही हुआ हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, 20 मिनट हो गए हैं।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने ग्रांट्स बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश को कंपेन्सेट किया है परंतु फिर भी हम इस बजट में अपनी कमिटिड लायबिलिटीज़ को कम कर सकते थे परंतु प्रदेश सरकार ने वह रास्ता नहीं चुना और जो हिमाचल प्रदेश की कमिटिड लायबिलिटीज़ हैं, वे पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब कमिटिड लायबिलिटीज़ क्या हैं? प्रदेश सरकार ने वेतन व पेंशन देनी है, ब्याज व ऋण की अदायगी करनी है और स्वायत्त संस्थाओं को एड देनी है। ये सभी कमिटिड लायबिलिटीज़ हैं।

24.03.2026/1255/वाई.के.-एन.जी./2

पूर्व में जब श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तब कमिटिड लायबिलिटीज़ 71 प्रतिशत थीं। मतलब यदि 100 रुपये आते थे तो 21 रुपये वेतन पर, 15 रुपये पेंशन पर, 10 रुपये ब्याज पर, 11 रुपये ऋण अदायगी पर और 9 रुपये स्वायत्त संस्थाओं को दिए जाते थे। इसके अलावा 29 प्रतिशत कैपिटल आउटले बचता था यानी पूंजीगत कार्यों के लिए बचता था जिससे डवलपमैंट कार्य किए जाते थे। आज क्या हालात हो गए हैं? वर्तमान प्रदेश सरकार ने धीरे-धीरे कमिटिड लायबिलिटीज़ को बढ़ाया और कैपिटल आउटले को कम किया। आज हालात यह हो गए हैं कि कमिटिड लायबिलिटीज़ 71 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई हैं और कैपिटल आउटले 29 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत रह गया। इसका सीधा असर विकास पर पड़ेगा। हमारे टाइम में 29 प्रतिशत था और आपके टाइम में पहले 28 प्रतिशत हुआ तथा उसके बाद 24 प्रतिशत आया और अब 20 प्रतिशत पर आ गया। अब 20 प्रतिशत आने से विकास कार्य कितने कम होंगे, इसका अंदाज़ा स्वयं लगाइए

और उधर से बजट का आकार भी कम है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो विकास कार्यों के लिए केवल 10,985 करोड़ रुपये बनते हैं और इसी अमाउंट से हिमाचल प्रदेश में डवलपमैंट होनी है। हमारे माननीय सदस्य जब उप-मुख्य मंत्री जी से पैसे मांगते हैं कि पीने के पानी की स्कीम को कंप्लीट करो तो उप-मुख्य मंत्री जी बोलते हैं कि मुख्य मंत्री जी से पूछो और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि केंद्र सरकार से लेकर आओ। तीन-तीन लाख की स्कीमों को पूरा करने के लिए भी प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बजट में रखा ही नहीं है। यह जो आपने प्रदेश का नुकसान किया है, इसके दूरगामी नतीजे होंगे और हिमाचल को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह एक काम आप कर सकते थे और जब समय था करने का, वह आपने किया नहीं और आज उसका नुकसान हिमाचल प्रदेश को होने वाला है। जहां तक कर्जों का विवरण है तो पिछले कल श्री जय राम ठाकुर जी ने उस पर विस्तृत चर्चा की है इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस मामले में रिकॉर्ड बना लिया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है?

24.03.2026/1255/वाई.के.-एन.जी./3

पिछले कल मुख्य मंत्री जी श्री जय राम ठाकुर जी से कह रहे थे कि आपके समय में 19,800 करोड़ रुपये का नहीं बल्कि 27000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। मतलब कुल 68000 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 76000 करोड़ रुपये का कर्ज था। आप जो मर्जी आंकड़ा ले लो परंतु पिछली सरकारों के पांच साल के आंकड़ों से आपकी सरकार के तीन साल के कर्ज का आंकड़ा ज्यादा है। आपने तीन साल में ही इतना कर्ज उठा लिया जितना पिछली सरकारों ने पांच साल में भी नहीं उठाया था। यह रिकॉर्ड सुक्खु सरकार ने तीन साल में बना लिया है। दूसरा रिकॉर्ड यह बनाया कि 1 लाख करोड़ रुपये की सीमा को पार करने का श्रेय भी श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नाम पर है।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1300/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

अब हिमाचल प्रदेश में एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है। यहां तक कर्जे को पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सभापति महोदय, जहां तक बजट की बात है, बजट को अनेक संज्ञाएं दी जाती रही हैं। कभी किसी बजट को दिशाहीन, कभी किसी बजट को आंकड़ों का मायाजाल, किसी को घोषणाओं का बजट बोलते हैं। परंतु मैं कहता हूं कि इस बजट के लिए सारी संज्ञाएं फिट बैठ रही हैं। इस बजट की कोई दिशा नहीं है, इस बजट से प्रदेश का कोई हित नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि केंद्र ने बजट प्रस्तुत किया, जिससे एक लक्ष्य रखा कि विकसित भारत वर्ष 2047 में करना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बजट में कोई भी लोक-लुभाने वाली घोषणा नहीं की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया, युवाओं को रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियां बनाई और इस तरह से हिंदुस्तान के बजट को पारित किया। परंतु हमारे प्रदेश के बजट में क्या है? जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर इस बजट में तो कोई प्रयास ही नहीं है। जो घोषणाएं हैं, वो अजीबो-गरीब घोषणाएं हैं। मैं तो इस बजट को ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बजट है जिसमें घोषणाएं तो अनेक हैं, परंतु वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पिछले बजटों की बात करे तो आपने वर्ष 2023-24 के पहले बजट में घोषणा की थी कि हम वर्ष 2026 तक प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बना देंगे। वर्ष 2026 आ चुका है। कहां है आपका ग्रीन एनर्जी स्टेट? (लोक निर्माण मंत्री की ओर इशारा करते हुए।) आपने वर्ष 2023 के बजट में कहा था। आप ही बताओ कि कौन करेगा आपके बजट भाषण पर विश्वास। जब आपके ऐसे-ऐसे वादे होंगे? ग्रीन एनर्जी स्टेट तो छोड़ो आप तो स्टेट को ग्रीन भी नहीं रहने दे रहे हैं। इतना वनों का कटान हो रहा है कि जंगलों-के-जंगल साफ कर दिये गये हैं। आपने हिमाचल प्रदेश की ग्रीनरी को तबाह कर रहे हैं। आपसे क्या उम्मीद की जाए?

आपने वर्ष 2023-24 में कहा कि कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश की दूसरी राजधानी बना देंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी

24.03.2026/1300/ए0जी0/ए0पी0/-02

कर दी गई है। आप बताओ कि आपने क्या किया कांगड़ा के लिए? एक चिड़ियाघर तो आपसे तीन साल में बना नहीं। एक चिड़ियाघर वर्ष 2023 से हर बजट में सुनते हैं, अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ है। आप बताए कि आप टूरिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? आप नशा मुक्ति केंद्र कि बात वर्ष 2023 के बजट में की थी कि नशे की इतनी बड़ी समस्या है। मुख्य मंत्री जी बच्चों के साथ दौड़ते हैं, अभियान चलाते हैं, न जाने क्या-क्या करते हैं। वर्ष 2023 में घोषणा की थी कि कंडाघाट में नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल कह दिया कि सिरमौर में भी नशा मुक्ति केन्द्र खोलेंगे, अभी वहां भी कुछ नहीं हुआ है। इस तरह की आपके बजट की घोषणाएं है। आपने तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का नाम बदनाम कर दिया है। आपने तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से योजना चला दी, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। इस योजना से क्या हुआ? कितने बच्चों को आपने इस योजना से रोजगार दिया? आपकी यह योजना वर्ष 2023 की है। इस बार आपने नई योजना शुरू कर दी, राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर उर्जा योजना। आप बताओ कि इन दोनों योजनाओं में क्या अंतर है? आप किसका मजाक बना रहे हो? वर्ष 2023 में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना और अब कह रहे हैं कि राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर उर्जा योजना, आप बताओं कि यह क्या है? युवाओं के साथ तो यह मजाक ही है। माननीय श्री भवानी सिंह पठानिया जी यह तो आपने राजीव गांधी जी के नाम का भी मजाक बना कर रख दिया है। उनकी आत्मा स्वर्ग से क्या कहती होगी कि यह मेरे चेले क्या कर रहे है। मेरे नाम का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में कुछ हुआ और न ही राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर उर्जा योजना में कुछ होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास बजट ही नहीं है। आपने अनेक योजनाओं की घोषणा की है।

Chairman: Please wind-up.

24.03.2026/1300/ए0जी0/ए0पी0/-03

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, कर्मचारियों के बारे में जो भी बजट में आपने घोषणाएं की है चाहे वे एरियर की बात हो या अन्य मुद्दे हो आपने कभी भी यह घोषणाएं समय पर पूरी नहीं की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार बाकी वर्गों के तो विरोध में है ही लेकिन कर्मचारियों के विशेष रूप से विरोधी है। प्रदेश सरकार हर बार कर्मचारियों को आश्वासन देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम करते है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट गुमराह करने वाला बजट है और गुमराह आप उनको करते हैं जो आम आदमी हैं। इस बजट में भी आपने उन एक लाख अति गरीब परिवारों को गुमराह किया है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1305/AT/AG/01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। ...(व्यवधान) सहारा क्या दे रहे है, मैं बता रहा हूं, आपने कहा कि हम आपके परिवार को सुखी परिवार बनाएंगे और उसके लिए हम आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन-सा गरीब परिवार 300 यूनिट बिजली खर्च करता है? क्या 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाला गरीब हो सकता है? वास्तव में, वे 100 यूनिट तक भी नहीं पहुंचते जबकि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहले श्री जय राम ठाकुर जी दे रहे थे। आपने उनकी गरीबी का मजाक बनाया है। आपने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये देने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं संजय अवसथी जी ...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb.

श्री रणधीर शर्मा: मैं पूछना चाहता हूं कि जो अति गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपये ले रही हैं, क्या उन्हें वही मिलेगा या इस

योजना के तहत 1500 रुपये अलग से भी मिलेगा? कृपया स्पष्ट करें। अगर अलग से मिलेगा तो योजना का स्वागत है लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो आप उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं।

Chairman: Please wind-up.

श्री रणधीर शर्मा : यह भी बताएं कि एक परिवार की कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, एक, दो या तीन? यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है और फिर आप कहते हैं कि हम पक्के मकान बनाकर देंगे, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। पक्के मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले ही बन रहे हैं, आधे बन चुके हैं और बाकी के लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं। आप बिना कुछ किए उसका श्रेय ले रहे हैं। करना कुछ नहीं हैं और एक लाख परिवारों को चिन्हित करके हमने आपके लिए कर दिया है और बल्ले-बल्ले लेने का यह काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका

24.03.2026/1305/AT/AG/2

यह बजट गुमराह करने वाला है। प्रदेश के भेड़-पालकों के लिए 100 रुपये का समर्थन मूल्य बताया जा रहा है। 100 रुपये का रेट आता ही कब है? उनका 100 रुपये से ज्यादा ही रहता है? मछली का समर्थन मूल्य 100 रुपये बताया गया है जबकि मछली 150-200 रुपये से कम नहीं बिकती। आप सिर्फ समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं लेकिन देना तो कुछ नहीं है, क्योंकि बाजार में रेट उससे नीचे आता ही नहीं। इसी तरह अदरक का रेट 30 रुपये बताया जा रहा है जबकि अदरक कभी 30 रुपये में नहीं बिकती। आप किस को गुमराह कर रहे हैं? समर्थन मूल्य का फायदा है अगर मछली का रेट 100 से कम हो जाए तब सरकार 100 रुपये लेगी तो 100 रुपये से कम रेट तो आता ही नहीं है इसलिए ...(व्यवधान)

Chairman: Please wind-up.

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय , 2-3 मिनट लगेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार केंद्र की योजनाओं के सहारे चल रही है। कल माननीय विक्रमादित्य सिंह जी

कह रहे थे कि हमने सड़कों के लिए 4580 करोड़ रुपये केंद्र से लाए। उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किए, डीपीआर दी, और प्रदेश सरकार ने कोशिश की, यह ठीक है। लेकिन फिर RDG के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर आपकी कोशिश से PMGSY, CRIF और जल जीवन मिशन का पैसा आया, तो RDG क्यों नहीं आई? ...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb.

श्री रणधीर शर्मा : आप यह कहना चाह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी ने प्रयास नहीं किया, इसलिए RDG नहीं आई। आपका निशाना हम नहीं थे, बल्कि मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। इसलिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं आप कल भाषण ही उनके लिए दे रहे थे। एक शेर भी हेलीकॉप्टर वाला उनके लिए पड़ा आपने ...(व्यवधान)

Chairman: Please wind-up.

24.03.2026/1305/AT/AG/3

श्री रणधीर शर्मा : मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन पर चर्चा कर रहे थे और नेशनल हेल्थ मिशन में डॉक्टरों से लेकर फार्मासिस्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों तक की सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर रहे थे। हमारे साथी मेज थपथपाते रहे, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? वह पैसा केंद्र से आ रहा है। जब पैसा केंद्र से आ रहा है, तो फिर आप घोषणा क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, तो यह भी लिखें कि यह पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

Chairman: Please wind-up.

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2026/1310/केएस/एएस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी ---

सभापति महोदय, जो विधायक क्षेत्र विकास निधि कम हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। इस निधि के कम होने का नुकसान हमें नहीं है। इससे गांव में जो छोटे-छोटे विकास कार्य होते हैं, छोटी सम्पर्क सड़कें, कम्युनिटी सैंटर, महिला मण्डल व युवक मण्डल भवन आदि बनने का कार्य प्रभावित होता है।

सभापति : माननीय सदस्य, निंदा करने की बजाय आप रिक्वेस्ट कर लो कि उसको रीस्टोर कर दिया जाए।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपसे भी एक कदम आगे बढ़कर कह रहा हूं। आपने वेतन कटौती की, हमने कुछ नहीं कहा। आपने और करनी है, कर लो परंतु विधायक क्षेत्र विकास निधि मत बंद करो। इसको कम मत करो। कम से कम इसको उतना ही रखा जाए और समय पर जारी किया जाए। इस साल की जो एक किश्त नहीं दी है उसको 31 मार्च से पहले दिया जाए क्योंकि वह बजट की अनाउंसमैंट है। बजट की अनाउंसमैंट 4 किस्तों की है जिनमें से 3 ही दी हैं। सभापति महोदय, आप भी बोलिए। आप तो विधायकों की वकालत करते हैं। 31 मार्च से पहले विधायकों को चौथी किस्त मिलनी चाहिए। वैसे तो यह निधि 2.20 करोड़ रुपये है लेकिन मैं कहता हूं कि सवा का आकड़ा लगा दो, सवा दो करोड़ कर दो, हम सनातनी हैं, कुछ आपके नाम लग जाएगा कोई बात नहीं । ना भी बढ़ानी है, ना बढ़ाओ परंतु इसको कम मत करो, यह मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है।

सभापति महोदय, रास्ते बनने कितने ज़रूरी हैं, मैं आपको अपने विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। आपकी जो योजनाएं हैं कुछ ठीक नहीं हैं। हमारे एक कामधेनु संस्था है जो गांव-गांव से, हर घर से दूध खरीदती है। उनकी गाड़ी तब गांव-गांव पहुंचती है जब वहां के लिए विधायक निधि से, सांसद निधि से सड़कें बनी हैं। आप मिल्क फेडरेशन से दूध खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे? कोई दूध देने वाला 5 किलोमीटर दूर पैदल नहीं आएगा। उनके गांव, उनकी पालंगरी को जीपेबल रोड बना होगा तो दूध आएगा। आप रोबोटिक सर्जरी ला रहे हो, वह तो छोड़ो, मरीज हॉस्पिटल भी तब पहुंच पाएगा अगर उसके घर नहीं तो गांव तक तो ज़रूर सड़क जाती होगी।

24.03.2026/1310/केएस/एएस/2

वरना आजकल पालकी उठाने वाले भी नहीं मिलते। इसलिए विधायक क्षेत्र विकास निधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यथावत रखा जाए, यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कल कहा कि मैंने यह बजट खुद बनाया, अधिकारियों ने नहीं बनाया। जो यह ख्याली पुलाव वाला बजट है, जिस तरह का यह बजट है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसे अधिकारी बनाते तो कुछ तो यथार्थ स्थिति रखते। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं रात को सोचता था और सवेरे अधिकारियों को निर्देश देता था। रात को तो सोचने का समय नहीं होता। रात को कौन सोचता है? रात को तो सपने देखे जाते हैं इसलिए यह यथार्थ वाला बजट नहीं है, सपनों का बजट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का बजट है और ऐसे सपने हैं जो कभी साकार नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए पैसा ही नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, यह बजट दिशाहीन भी है, कोरी घोषणाओं वाला बजट भी है, आंकड़ों का मायाजाल भी है, जनता को गुमराह करने वाला भी है और माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का बजट है, यथार्थ में कुछ नहीं है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

24.03.2026/1315/av/dc/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.15 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी भाग लेंगे।

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने दिनांक 21 मार्च, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान प्रस्तुत किए हैं, मैं उसको अपना समर्थन देते हुए इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह चौथा बजट प्रस्तुत किया गया है। पिछले तीन वर्षों में जिस तरह से प्रदेश सरकार का कार्यकाल बीता वह किसी से छिपा नहीं है। यहां पर भयंकर आपदाएं आईं जिसमें राजनैतिक और प्राकृतिक आपदाएं; दोनों शामिल थीं। उसके बावजूद केंद्र सरकार से जो हमें आर्थिक सहायता अपेक्षित थी, वह हमें प्राप्त नहीं हुई। केंद्र सरकार ने जो आर0डी0जी0 का कट लगाया है उसका असर भी कहीं-न-कहीं इस बजट अनुमान में देखने को मिला है। किसी भी प्रदेश सरकार का बजट वहां की अर्थ-व्यवस्थाओं, सरकार की प्राथमिकताओं और सरकार की सोच का एक प्रतिबिम्ब होता है। यहां माननीय मुख्य मंत्री की सोच एक इतिहास बनी है और कहा भी जाता है कि पूत के पांव पालने में नज़र आ जाते हैं। यह इसलिए एक इतिहास बना क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ लेने के तुरंत बाद परम्परा को तोड़कर एक मानवता का संदेश हमारे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे विश्व को दिया। उसी दिन यह

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1420/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री संजय अवस्थी.... जारी

जाहिर हो गया था कि इनकी मंशा कुछ अलग करने की है और ये प्रदेश को किस दिशा में ले जाएंगे, उसी दिन उसका आभास हो गया था। इनका तीन वर्षों का कार्यकाल रहा है और आज जिस बजट अनुमान पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि सीमित साधनों में इससे बेहतर बजट अनुमान पेश नहीं किया जा सकता। भले ही बजट का आकार इस बार घटा है लेकिन उसके कारण हैं। सबसे बड़ा कारण आर0डी0जी0 है। माननीय सदस्य श्री रणधीर जी जो हमारे विपक्ष के साथी है उन्होंने टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि पिता कब तक अपने बेटे का सहारा बनकर उसको आगे बढ़ाता रहेगा, उसके खर्चे पूरे करता रहेगा, लेकिन उनकी बात अधूरी थी और मैंने बीच में वक्तव्य भी दिया था।

अब मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पिता और पुत्र का रिश्ता बड़ा अहम होता है। पिता का यह फर्ज है कि वह बेटे की देखभाल करे और एक समय सीमा के

बाद जब वह बालिग होता है, अपने आजीविका के साधन तलाशते हुए अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। यह सही है कि वह तब आत्मनिर्भर हो जाता है। लेकिन पैतृक संपत्ति पर उस पुत्र का अधिकार हमेशा रहता है और वह संविधान ने हमें दिया है। जिस तरह से केन्द्र ने आघात किया है क्योंकि आर0डी0जी0 हमारी पैतृक संपत्ति है। आर0डी0जी0 क्यों लागू की गई थी, इस पर मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले बहुत से वक्ताओं ने इस पर चर्चा की है लेकिन यह बोलना जरूरी है क्योंकि यह इस बजट का जो 3,586 करोड़ रुपये का आकार घटा है, उसकी सबसे बड़ी वजह आर0डी0जी0 का कट लगना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई बार आपदा आई और आपदा के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो विशेष पैकेज दिया, वह अपने सीमित साधनों से दिया। ये सब कारण थे और इसमें विपक्ष का क्या योगदान था, यह किसी से छुपा नहीं है। जब प्रभावित परिवारों को जरूरत थी तो वे टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रहे थे। सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग विपक्ष भी है । जब हमने इस सदन में यह मांग रखी थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए तो उस समय इन्होंने यहां से वॉकआउट किया। यह इनका असली चेहरा है। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं जिन्होंने इस पर चर्चा में भाग लिया, बड़ी-बड़ी बातें की । जब पूर्व के तीन वर्षों में सरकार की योजनाओं

को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए हमने इनसे साथ मांगा तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए इनका यह कहना कि पिता कब तक बेटे की देखभाल करेगा, यह गलत है। हम हिमाचल प्रदेश की तुलना बाकी राज्यों नहीं कर सकते, चाहे वह उत्तराखंड या असम है क्योंकि उनका 50 प्रतिशत इलाका मैदानी है and they are also consumer states. हमारा 80 प्रतिशत क्षेत्र लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। इसलिए हमारी तुलना उत्तराखंड और असम वगैरह से नहीं की जा सकती। हमारे मुख्य रिसोर्सिज का दोहन और उपयोग बाकी राज्य भी कर रहे हैं, चाहे वह पानी है, चाहे वह वन है। हिमाचल प्रदेश 90 हजार करोड़ रुपये की इकोलॉजिकल सर्विस देता है। यह आकलन मेरा नहीं

एन0एस0 द्वारा ... जारी

24-3-2026/1425/एन0एस0-एच0के0/1

श्री संजय अवस्थी-----जारी

है, यह Indian Institute of Forest Managment ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार हमारा इकोलॉजिकल सर्विसीज में जो योगदान है उन्होंने उसकी वैल्यू 90,000 करोड़ रुपये लगाई है। हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था लेकिन हमारी आर0डी0जी0 खत्म कर दी गई। मैं कहना चाहूंगा कि आज मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित की योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। पूर्व सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों को बेचा है। प्रदेश में लगभग 13,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और हमें 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली भी नहीं मिल रही है। पूर्व सरकार द्वारा किए गए एग्रीमैंट्स के नुकसान की भरपाई प्रदेश को करनी पड़ रही है। बी0बी0एम0बी0 के 14 वर्षों से लगभग 7,000 करोड़ रुपये पेंडिंग है। इसके लिए पूर्व सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास रहे हैं कि रुके हुए धन की वापसी हो और इसका एरियर भी हमें मिले। आज प्राकृतिक आपदा आकलन का पैसा पेंडिंग है और उसको लाने में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही है। देश के प्रधानमंत्री जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए और उन्होंने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की तो उसका अभी तक एक रुपया भी नहीं आया है। उसको लाने के लिए विपक्ष के क्या प्रयास हैं? आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

जी0एस0टी0 लगने से प्रदेश को घाटा हुआ है क्योंकि यह कंज्यूमर स्टेट नहीं है। हमें जी0एस0टी0 कंपनसेशन पूरा नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट प्रदेश के विकास की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता भी दिखाता है। इतने कठिन समय में कड़े फैसले लिए गए हैं,यह मुख्य मंत्री जी की हिम्मत व ताकत को दिखाता है और यह प्रतिबिंब है। वर्तमान बजट ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का एक प्रयास है। आपको इसे एप्रिशिएट करना चाहिए। पिछली बार पूर्व सरकार को इतना ज्यादा पैसा मिला और उसके बारे में यहां विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है। पूर्व सरकार को लगभग

70,000 करोड़ रुपये की राशि मिली है। यदि आप चाहते तो प्रदेश के कर्ज को कम कर सकते थे। कर्मचारियों का लगभग 13,000 करोड़ रुपये का एरियर देने को था और आप उसको दे सकते थे लेकिन आपने नहीं दिया तथा आपने पैसे का

24-3-2026/1425/एन0एस0-एच0के0/2

दुरुपयोग किया। पूर्व सरकार ने हजारों-करोड़ों रुपये के भवन बनाए थे जिनकी कोई योजना ही नहीं थी। हम योजनाएं बना रहे हैं और आपने बिना योजनाओं के ही उस पैसे का दुरुपयोग किया जो आपको मिला था। आज वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमैंट की वजह से किसानों व बागवानों को नुकसान हुआ है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था को बागवान प्रभावित करता है। जिस तरह आयात शुल्क केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान हुआ है। इसके बारे में पूर्व सरकार ने कभी चर्चा नहीं की।

सभापति महोदय, वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025-26 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत अनुमानित है। यह हमारे तीन वर्षों के कार्यकाल का परिणाम है। आप इस बात की सराहना क्यों नहीं करते हैं? देश में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,19,575 रुपये है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,83,626 रुपये अनुमानित है। इस बात की आप सराहना क्यों नहीं करते? आज प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर एम0एस0पी0 दिया गया है ताकि

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1430/RKS/HK-1

श्री संजय अवस्थी... जारी

हमारे किसानों की जेब में पैसा आए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्राकृतिक खेती से पैदा मक्की का रेट 50 रुपये प्रति किलो, गेहूं का 80 रुपये प्रति किलो और हल्दी का रेट जो पहले 90 रुपये प्रति किलो था उसे बढ़ाकर 150 रुपये

प्रति किलो किया है। मैं समझता हूं कि पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने प्राकृतिक उत्पादों पर इतने अधिक रेट फिक्स किए हैं। आज इस चर्चा में नशामुक्त हिमाचल की बात की गई है। यह सही है कि आज हमारे युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आए दिन पुलिस विभाग द्वारा चिट्टे के काफी केसिज पकड़े जा रहे हैं। इस नशे की चपेट में आकर कई नौजवानों ने अपनी जिंदगी खो दी है। हमारे युवा नशे से दूर रहें इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है। युवा सशक्तिकरण एवं खेल विकास योजनाओं में खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त अभियान को स्थान दिया गया है जोकि एक सकारात्मक पहल है। मैं समझता हूं कि खेल-कूद और शारीरिक विकास के प्रति यदि हमारे युवा आगे आएंगे तो यही एकमात्र विकल्प है कि वे नशे से दूर रहेंगे। हमने इसके लिए 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है और इस बात के लिए हमारे विपक्ष के साथियों को भी मुख्य मंत्री की सराहना करनी चाहिए। हमारी सरकार ने लंबित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। जो पूर्व सरकार के लंबित कार्य थे हमने उनका निष्पादन किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने लम्बित राजस्व मामलों को निपटाने के लिए तहसील स्तर पर लोक अदालतों की शुरुआत की है जोकि एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसका परिणाम यह निकला कि जो हजारे म्यूटेशन और डिमार्केशन के काफी समय से लंबित मामले थे उनका समाधान होना शुरू हो गया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो इस सरकार ने 150 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के अंडर लाया है जोकि अपने आप में एक सकारात्मक परिणाम है। हमने रेवेन्यू जनरेशन की ओर भी फोक्स किया है। मुख्य मंत्री जी की जो नई टाउनशिप स्टार्ट करने की सोच थी वह अपने आपमें एक सकारात्मक कदम है। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में हिम चण्डीगढ़, हिम पंचकुला और कांगड़ा वैली

24.03.2026/1430/RKS/HK-2

टाउनशिप की बात की है। इस सोच से न सिर्फ हमारे राजस्व में बढ़ोतरी होगी बल्कि एक क्षेत्र विकसित होकर वहां नई टाउनशिप स्थापित होगी जिसका लाभ पूरे हिमाचल प्रदेश को होगा। अगर हम कर्मचारी कल्याण की बात करें तो हमारे पास कर्मचारियों की पूर्व

सरकार के समय की 13 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया थीं। इसके बावजूद भी हमने अपने ओ0पी0एस0 के वायदे को पूरा किया। हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्ज, आशा वर्कर्ज, सिलाई शिक्षक, पैरा-फिटर्ज, मल्टी टास्क वर्कर्ज और एस0एम0सी0 विधायकों सहित कई वर्गों के मानदेय में बढ़ोतरी की है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह दर्शाता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच सभी वर्गों के लिए काम करने की है और यह बजट इस बात का प्रतिविम्ब है। अगर हम वित्तीय अनुशासन की बात करें तो मुख्य मंत्री जी ने अपने वेतन कट से शुरू करके सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का कुछ भाग काटने का जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि हम सब इस कठिन घड़ी में मुख्य मंत्री जी के साथ हैं। आपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो सपना संजोया है उसमें हम कंधे-से-कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और उस सपने को साकार करेंगे। श्री रणधीर शर्मा जी ने यहां पर एक सपने की बात की कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी को रात में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद आती हैं तो वे उसे लिख लेते हैं और अगले दिन अधिकारियों से उन पर चर्चा करते हैं। इन्होंने यह एक तंज कसा था।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1435/बी.एस./एच.के.-1

श्री संजय अवस्थी जारी...

इन्होंने एक तंज कसा था। आदरणीय रणधीर जी, मैं यह कहना चाहूंगा-

आंखों में सपने हों और मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल खुद-ब-खुद आपके कदम चूमती है।

इस बात का आप ध्यान रखें। मुख्य मंत्री जी के सपने आज साकार होने जा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सपना था कि हिमाचल प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और आज का यह बजट हमारी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रतिबिंब है। चाहे वह किसान हों, चाहे महिलाएं हों। आज जिस तरह की योजनाएं इसमें लाई गई हैं और प्रावधान रखा गया है उससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आपको इस बात को मानना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री संजय अवस्थी : सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में बहुत लंबित मांग को पूरा किया है। हमारे जो सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, वह काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पैरा मिलिट्री वेलफेयर बोर्ड का गठन हो और इन्होंने इस बात को स्वीकृति दी है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक चीज मैं और सांझा करना चाहूंगा कि यदि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो एजुकेशन के लिए केंद्रीय बजट में 14 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है और हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एजुकेशन पर 19.6 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।

ऐसे ही हेल्थ में 6.4 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। जोकि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक है। यह अपने आप में दर्शाता है कि मुख्य मंत्री जी मूलभूत सुविधाओं का ढांचा मजबूत करना चाहते हैं। हमारा प्रदेश शिक्षित हो और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। रोबोटिक सर्जरी तक यहां आ गई है और वह समय था जब आदरणीय विपिन सिंह परमार जी स्वास्थ्य मंत्री थे और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री

थे इनके समय में सिर्फ दो नेफ्रोलॉजिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट को एन0ओ0सी0 देकर प्रदेश से बाहर भेज दिया। ऐसी इनकी सोच थी और हमारी सरकार की सोच यह है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना प्राथमिकता है और आदरणीय रणधीर जी ने कमिटेड लायबिलिटी की बात की। कमिटेड लायबिलिटी जो है यह आपकी देनदारियां हैं

जो पहले से बनी हैं। उसमें हम ब्याज भी चुका रहे हैं और मूलधन भी चुका रहे हैं। यह कमिटेड लायबिलिटी में आती हैं। जो कर्ज आपने लिया है उसे हम चुका रहे हैं। यह वर्तमान सरकार के समय में नहीं बनी है। यह पहले की सरकारों की देन है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री संजय अवस्थी : आपने न्यूनतम मूल्य की बात की। आपने 100 और 30 रुपये की बात की। आपने अदरक की बात की। आपने कहा कि मार्केट में रेट तो बहुत ज्यादा है। यह मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। न्यूनतम मूल्य इसलिए दिया जाता है ताकि किसान का खर्चा पूरा हो सके और उसे नुकसान न सहना पड़े। सरकार ने किसानों को इसकी गारंटी दी है। ...(घंटी)... तो यह बात आपको समझनी चाहिए।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो बजट यहां पर पेश किया गया यह मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह प्रदेश के हित का बजट है। इसमें हर वर्ग को स्थान दिया गया है। हर वर्ग के विकास के लिए प्रावधान रखा गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

24.03.2025/1435/बी.एस./एच.के.-3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर जो चर्चा चल रही है, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो अपना चौथा बजट इस माननीय सदन में पेश किया।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1440/DT/YK-1

श्री प्रकाश राणा जारी

हमेशा यही देखा गया है कि मुख्य मंत्री चाहे, वह किसी भी प्रदेश का हो, जब वह अपने कार्यकाल के दौरान बजट प्रस्तुत करते हैं तो ज्यों-ज्यों वे बजट प्रस्तुत करते हैं त्यों-त्यों उनके बजट में उन्नति होती है और वह कुछ-न-कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। लेकिन मुझे यह दुःखी होकर कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश में ही ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ है। इस तरह का बजट अगर किसी अन्य प्रदेश में पहले कभी प्रस्तुत हुआ हो तो मुझे बता दो? अगर है तो पूरे भारत वर्ष में एक भी प्रदेश ऐसा बता दो जिसके मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया हो?

सभापति महोदय, मैं बजट बुक को देख रहा था। पिछले दो-तीन साल से यही बात करता आया हूं और मैंने पहले भी मुख्य मंत्री व अन्य मंत्रियों से आग्रह किया था कि ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें प्रदेश के इंकम सोर्सिस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है-उन पर विचार किया जाए। लेकिन जब मैं यह बात बोलता था तो मेरी बात का मजाक उड़ाया जाता था। देखिए आज वह दिन आ गया। मुख्य मंत्री जी द्वारा ऐसा बजट पेश किया गया जो पिछले बजट से भी काफी कम है। दुःख तो इस बात का है कि मुख्य मंत्री जी द्वारा बहुत सी चीजों में कट लगा दिया गया है। विधायक निधि को आधा कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इससे विधायकों को फर्क पड़ेगा लेकिन ऐसा करने से प्रदेश की 75 लाख जनता सफर होगी। हमारे प्रदेश के 90 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं और गांव के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि घर-घर रोड पहुंचाई जाए। विधायक निधि से गांव की रोडज को पक्का किया जा रहा है या जहां रोड नहीं है वहां रोड बनाई जा रही है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि विधायक निधि में कट लगाना अच्छी बात नहीं है। इससे प्रदेश की जनता सफर हुई है। मुख्य मंत्री जी द्वारा यह फैसला कैसे लिया गया, इस बारे में तो मैं नहीं जानता।

दूसरा, सरकारी अधिकारियों की सैलरी में कट लगा दिया गया है। जब एक बार किसी को भी कुछ दिया जाता है, जैसे सैलरी ही दे दी या कोई पैकेज दे दिया या कोई अन्य भत्ता दे दिया फिर उस फिर कट नहीं लगाना चाहिए। किसी को अगर आप रोटी दे देते हैं तो उससे फिर उस रोटी को छिनने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए-यह गलत है। आय बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। जो प्रदेश के कर्मचारियों और

अधिकारियों की देनदारियां है वे तो आपसे दी नहीं जा रही। पेंशन और एरियर जिस की देनदारी लगभग 8500 करोड़ के लगभग है, वह आपसे नहीं दिया जा रहा। डी0ए0 का

24.03.2026/1440/DT/YK-2

एरियर ही अब 5000 करोड़ रुपये हो गया है वह भी प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा। इसके अतिरिक्त बहुत सी देनदारियों और भी हैं। लेकिन जब पहले के ड्यूज सरकार नहीं दे पा रही तो आप उनकी सैलरी में कट क्यों लगा रहे हो? अगर आपने कट ही लगाना है तो कम-से-कम उनसे पूछ लो। कई लोग आपके कहने पर अपने ड्यूज छोड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रजातंत्र के लिए यह एक बहुत ही दुःख का विषय है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि आप अधिकारियों की सैलरी में एकदम कट लगा दो। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसके लिए सरकार बात करे। हम कई सालों से देख रहे हैं कि यह भी मिलेगा-वह भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो कब मिलेगा? जब मिलेगा तब बात करेंगे। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए। ..(व्यवधान) देखिये ऐसा बोलना बहुत आसान है। हर अधिकारी और कर्मचारी अपनी सैलरी से ही अपना जीवन यापन करता है। उसे पता है कि मैंने अपनी सैलरी को कहां और कैसे खर्च करना है। इसलिए ऐसी चीजों में एकदम कट लगाना अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र में तानाशाही वाला रूल नहीं चलता और हम इसे मानना भी नहीं चाहते
एन0जी0द्वारा जारी...

24.03.2026/1445/ए.जी.-एन.जी./1

श्री प्रकाश राणा..... जारी

जब आपके पास तीन साल थे तो आप कहां थे? बस आप बार-बार उसी बात पर आएंगे कि उसने ये कर दिया, इसने वह कर दिया। सबसे बड़ी समस्या आर0डी0जी0 की भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो कर्ज की है, जो 13-14 हजार करोड़ रुपये हर साल भरना है, वही समस्या है। अगर यह समस्या नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अपने विकास पर हम कितना खर्चा करते हैं? विकास के लिए हमारे पास बड़ी मुश्किल से 5-6 हजार करोड़

रुपये ही हैं। मुख्य मंत्री जी ने हमारी व कर्मचारियों/अधिकारियों की सैलरी काट दी, वह तो ठीक है लेकिन अपने खर्चे कितने कम किए? अपने प्रोग्राम कितने कम कर दिए? अपने खर्चों को कितना कम किया? वह तो इसमें दिखाया ही नहीं गया है। इसमें काटी गई सैलरी दिखाई गई और बस हो गया। प्रदेश सरकार को अपने खर्चे भी तो कम करने होंगे।...(व्यवधान) भाई साहब, अपनी सैलरी काटना तो एक दिखावा है क्योंकि 50-60 हजार रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। महीने के जो खर्चे करोड़ों रुपये के हैं, उनको कम करो।...(व्यवधान) खिचड़ी क्या खाते हैं? आपके जो करोड़ों के खर्चे हैं, आप उसको क्यों नहीं कम कर रहे? ...(व्यवधान) देखिए, अभी इस बजट की प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही दिखाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी बनाई है, अच्छा है, बनाना भी चाहिए। बताना व दिखाना इतना चाहिए था कि हम सबको पहले यह अंदर दिखा देते। इसको एकदम से वार्स्ट लेवल में उठा देना भी हमारे लिए शर्म की बात है। ये गलत हो गया है और इसका दिखावा नहीं करना चाहिए था। ये चीजें दिखाई नहीं जाती हैं। इसके लिए साधन जुटाने चाहिएं थे। पूरे हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू लगभग 18,000 करोड़ रुपये है लेकिन बजट बुक में देखें तो इसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इसके अलावा 13,950 करोड़ रुपये हमें केंद्र सरकार से मिलना है। वह भी अच्छा है क्योंकि पहले लगभग 11,000 करोड़ रुपये आता था लेकिन अभी 2,000 करोड़ रुपये बढ़ा है।

24.03.2026/1445/ए.जी.-एन.जी./2

मैं कहूंगा कि इसको भी तो कुछ मान देना चाहिए। केन्द्र सरकार से 13,950 करोड़ रुपये मिलेंगे और लगभग 19,000 करोड़ रुपये अपना रेवेन्यू है। मैं अगर इसको टोटल करूं तो यह 32,950 करोड़ रुपये बनता है। बजट बुक में लिखा गया है कि वर्ष 2026-27 में कितना पैसा किस-किस को दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि इस वक्त प्रदेश में 1,85,988 कर्मचारी/अधिकारी हैं। जिनको एक साल में 14,830 करोड़ रुपये सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा 11,534 करोड़ रुपये पेंशन दी जा रही है । ब्याज पर जो 1 लाख करोड़ से

ऊपर पैसा लिया गया है, उसके ब्याज के रूप में 7,140 करोड़ रुपये भरने हैं। रीपेमेंट के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपये देने हैं। यानि इन चार आइटम्स का टोटल 39,760 करोड़ रुपये बन रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बजट बुक में लिखा है। 39,760 करोड़ रुपये देना तो फिक्स है और उसमें सिर्फ सैलरी, पेंशन, कर्ज का ब्याज व रीपेमेंट— ये चार चीजें ही शामिल है। यहां बजट बुक में दिखा रहे हैं कि हमारे पास 40,000 करोड़ रुपये के करीब रेवेन्यू आ जाएगा। मेरा मानना है कि यह 40 करोड़ रुपये नहीं आएगा और आएगा भी तो कैसे आएगा, ये तो प्रदेश सरकार ही जाने कि कैसे आएगा। इनके अलावा सब्सिडी के बारे में लिख रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1627 करोड़ रुपये है। इसके बाद सब्सिडी देनी है, ग्रांट-इन-एड, जनरल सैलरी है, इन जनरल लोन सैलरी है, ग्रांट-इन-एड फॉर कैपिटल है। यह पैसा कहां से आएगा? उसका तो कुछ बताओ। अगर आपका खर्चा 39 हज़ार करोड़ रुपये है...(व्यवधान) आप ही तो इसमें दिखा रहे हैं कि 39,760 रुपये खर्चा है, यह आपने ही लिखा है। यह तो आपने देना ही है, तो बाकी कहां से आएगा?...(व्यवधान) हां, एक बात है कि आप कर्ज लेंगे। इसके अलावा कोई पैसा है तो बता दीजिए। अगर कर्ज भी लेंगे तो 10,000 करोड़ रुपये ले लेंगे, उससे ज्यादा क्या लेंगे? पहले ही 1,08,000 करोड़ रुपये लोन क्रॉस कर गया है तो उसमें 10,000 करोड़ रुपये और जोड़ लीजिए। उसके बाद फिर कहां पहुंच जाएंगे? क्या आपके पास कोई साधन है?

सभापति महोदय, अब समय आ गया है कि यहां पर ऐसा कोई एक कानून बनाना

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1450/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री प्रकाश राणा जारी.....

बनाया जाए। इस सब खर्चे के अलावा घोषणाएं भी हैं, उनका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। प्रदेश सरकार कहती है कि वे घोषणाओं को शत-प्रतिशत पूरा करेंगी। अगर 22 लाख

महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देनी पड़े तो हर साल 4 हजार करोड़ से 4.50 हजार करोड़ रुपये चाहिए। आप बताइए कि इतने पैसे कहां से लाएंगे? यहां आपके पास सैलरी और पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। सैलरी और पेंशन पर तो आप कट लगाकर दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कर्ज कौन ज्यादा कर गया? सभापति, मेरी एक बात है कि आप तो समझदार हैं, विधान सभा में कर्ज का एक चार्ट लगा दिया जाए ताकि पता लग सके कि किसने कितना कर्ज लिया? किसने मना किया है, लगाइए एक चार्ट। हम सब देख लेंगे और इसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि पक्ष वालों ने ज्यादा कर्ज कर दिया, पक्ष वाले कहते हैं कि विपक्ष ने अपने समय पर ज्यादा कर्ज लिया है। पूरा समय इसी में बर्बाद हो रहा है। इस बात को खत्म कीजिए। मैंने पहले भी विनती की थी कि विधान सभा में एक चार्ट लगाया जाए कि किसने कितना खर्च किया है। विधान सभा में हमारे फोटो तो बढ़िया लगे हैं, एक कर्ज का चार्ट भी लगा दीजिए कि किस सरकार ने कितना कर्ज लिया है। मैं चाहता हूं कि हम फालतू समय की बर्बादी न करें और आगे का रास्ता सोचें कि क्या करना है? अब वह समय आ गया है कि हमें हिमाचल की अगली पीढ़ी को मजबूत बनाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिमाचल को मजबूत करने के लिए कोई कानून बनाया जाए। यह जो झूठी घोषणाएं करते हैं, अगर वे पूरी नहीं हुई तो उसकी भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो वे अगली बार चुनाव न लड़ें। दूसरी बात यह कि जो सरकार जितना कर्ज लेगी उसे 5 वर्षों में भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेंगे तो उसकी भरपाई जनता नहीं करेगी। हिम्मत है तो बनाइए कानून। अब हिमाचल खत्म हो रहा है तो कम से कम कोई कानून तो बना लीजिए, क्योंकि इस समय इसकी जरूरत है। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान लेते हैं तो क्या उसके पैसे हम नहीं देते? प्रदेश का मुखिया पूरे हिमाचल प्रदेश का मुखिया है। वे हम सबके मुखिया हैं। आप ही बताइए कि जब आप कर्ज लेते हैं तो क्या वह कर्ज आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाते हैं? अगर आप प्रदेश को परिवार समझते हैं तो ऐसा क्यों है कि प्रदेश को कर्ज में

24.03.2026/1450/ए0जी0/ए0पी0/-02

छोड़कर जा रहे हैं। यह पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। क्या इसमें भी कोई दोराय है?

Chairman: Please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : पहले इस तरह से समय नहीं आया था कि किसी कर्मचारी की सेलरी कटी हो। ...(व्यवधान)

Chairman: Please don't disturb.

श्री प्रकाश राणा : मान लो अगर कटौती भी हुई थी, तो उस समय कोविड पूरी दुनिया में आया था। इसलिए सैलरी काटी गई होगी। उस समय कोविड पूरी दुनिया का मामला था। लेकिन आज जो प्रदेश में हुआ है, क्या पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है? उस समय सैलरी नहीं काटी थी, हो सकता है कि हमारी विधायक निधि काटी गई थी। मैं बार-बार कहता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र की अपनी-अपनी स्थिति है। पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन मुख्य मंत्री जी का काम है कि सबको बराबर लेकर चलें, चाहे कोई भी विधान सभा क्षेत्र हो। अगर आप हिमाचल में एक ही क्षेत्र में विकास करेंगे और दूसरे में नहीं करेंगे तो उससे हिमाचल का विकास नहीं होगा और न ही हिमाचल ऊपर उठेगा। अगर विकास करना है तो पूरे विधान सभा क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जाए। आप ही बताइए कि माननीय मुख्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र अधिकतम 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मुझे लगता है कि पूरा हमीरपुर जिला 1100 या 1200 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन मंडी में सिर्फ एक जोगिंदरनगर विधान सभा क्षेत्र 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आप ही बताइए कि आप किस हिसाब से सबको बराबर बांट रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने किलोमीटर सड़कें हैं। माननीय जय राम ठाकुर जी के समय मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए पैसे मिले हैं। मैं सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा बल्कि आपके विधान सभा क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं। शिलाई विधान सभा क्षेत्र भी लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1455/AT/AS/01

श्री प्रकाश राणा जारी...

शिलाई और जोगिंदर नगर ...(व्यवधान) मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारी जोगिन्द्रनगर की सड़कें कच्ची-पक्की मिलाकर लगभग 540 किलोमीटर की हैं। यह सर्वे पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमेंट ने दिया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, आपके अपनी तरफ से इंक्वायरी भी करवाई गई, तो उस XEN का कुछ हुआ क्या? जो 18 करोड़ रुपये का मामला था। अगर कार्रवाई करवा दी तो मुझे उसके पेपर ही दे देते आप, तो मैं फिर कोर्ट चला जाता हूं। अगर आप कहते हैं कि वह सही है, तो मैं कोर्ट जाता हूं और अगर गलत है तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मंत्री जी, हमें ये तो बता दो। आप पर जनता की बहुत उम्मीदें हैं। आपको एक्शन और डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर एक XEN कोई भ्रष्टाचार करता है और आप चुप बैठे हुए हैं, तो यह गलत है। ऐसा क्यों है? सर, यह 18 करोड़ रुपये का मामला मेरे चुनाव क्षेत्र का है। हमारे 85 किलोमीटर रोड को खोद दिया गया, नालियां बनाई गईं और फिर पूरा रोड भारी बरसात के कारण गिर गए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक बार इस रोड का दौरा कर लो। चलो अगर इंक्वायरी हुई है तो आप अपनी आंखों से भी इसे देख लो। अगर इस तरह के काम होंगे तो कैसे चलेगा? आप कहते हैं कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते, तो यहां क्या हो रहा है? यह गलत हो रहा है। इसमें अब समय आ गया है कि कोई ठोस डिसीजन लिया जाए। हम न आपके ऊपर बोल रहे हैं और न ही हम किसी और के ऊपर बोल रहे हैं। हमें किसी के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कम-से-कम सही है उसको तो सही करो।

Chairman : Please wind-up.

श्री प्रकाश राणा : अगर कर्ज पर लगाम नहीं लगी, तो आगे और भी हमारे हालात खराब होने वाली है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारे ऐसे हालात हैं। जनता आपसे क्या चाहती है? जनता आपसे चाहती है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो, हेल्थ सिस्टम सही कर दो, सड़कों को ठीक कर दो और पीने के लिए स्वच्छ पानी दे दो। इसके अलावा क्या और क्या चाहती है जनता? जनता आपसे कुछ फ्री नहीं मांग रही है। आपने

1500 रुपये की घोषणाएं खुद कर दी, किसी ने मांगा था आपसे 1500 रुपये क्या? 300 यूनिट फ्री बिजली किसने मांगी थी क्या? बोलो भाई, क्या जरूरत पड़ गई? हम सब नेता इसके गुनाहगार हैं, जो चुनाव के समय लोगों को झूठ बोलते हैं और फिर आगे चल पड़ो भाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कानून बनाओ, यहां कानून की जरूरत है ...(व्यवधान) चाचा जी, let me complete please, its my turn. Let me complete. ...(Interruption)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं और न ही आपको बोल रहा हूं। कानून बनाने की आवश्यकता है और कानून हमें ही बनाना है। आप इतने नए-नए कानून यहां पर बना रहे हैं। तो बनाओ नए 2-4 कानून, जो कर्ज लेगा उसको भर के जाना पड़ेगा 5 साल के अंदर। ऐसे कैसा चलेगा प्रदेश। अगर फिर से भी प्रदेश आपसे नहीं चलता है, (***) हम चलाकर बताते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो हम भी (***)करो कुछ तो करो। ...(व्यवधान) यह सारे क्या बोलते हैं। मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। गुरु जी, हम क्यों बोलेंगे? आप प्रदेश को अच्छे से चलाइए। मैंने बोला था, देखो आप इसके साक्षी गवाह हैं। मैंने कहा था कि आप एक कमेटी बनाओ 4 साल हम मिलकर काम करेंगे ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up.

श्री प्रकाश राणाः हम मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पांचवें साल हम चुनाव में जाएंगे। प्रदेश को उठाने का काम आपने किया, नहीं किया। मैंने तो आपको अच्छी सलाह दी थी, हम मिलकर काम करना चाहते थे ...(व्यवधान) नहीं मुझे क्या मौका देगा, किसी को भी मौका दे दो BJP यह चला देगी। नहीं चलाएगी तो देख लेंगे, लेकिन मौका तो दे दो अब इनको। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि 70,000 करोड़ रुपये आया है। गुरु जी, एक बात और है, चलो अब मैं अपने क्षेत्र की बात रख लूं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

24.03.2026/1455/AT/AS/03

मैंने मुख्य मंत्री को प्लानिंग मीटिंग में कहा था कि आप गलत कर रहे हैं। जिस विधान सभा का क्षेत्र बड़ा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा बजट देना पड़ेगा। मैंने सही बात रखी थी और ऐसा करना भी चाहिए था ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। अब अस्पताल की बात करूं आप कहते हैं कि हमने रोबोटिक सर्जरी लाई। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सिविल अस्पताल हैं, एक जोगिंदर नगर और एक लडभड़ोल में। अब बताओ कि सिविल अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर डेपुटेशन पर आया हुआ है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। जनता हमारे घर आती है, लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं है।

राकेश कालिया जी, आप सुन रहे हैं। आप तो स्पष्ट आदमी हैं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या, आप समर्थन तो करो, एक भी डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर डेपुटेशन पर

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1500/केएस/एएस/1

श्री प्रकाश राणा जारी ---

डैपुटेशन पर एक डॉक्टर है। अच्छा हुआ शिक्षा मंत्री जी आ गए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री प्रकाश राणा : शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। मगर गुरुजी हमारे 7 सीनियर सैकडरी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं हैं। ...(व्यवधान) चलो, मैं धन्यवाद करता हूं अगर आप स्टैप ले रहे हैं। अगर पहले इन्होंने शिक्षा का स्तर उठाया होता तो हमारे 11-12 लाख बच्चे जो बेरोज़गार हैं, वे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी ही मिले लेकिन अगर उनको सही एजुकेशन मिली हो, संस्कार सही मिले हो तो पूरी दुनिया पड़ी है। जॉब खुद आती है लेकिन हमें अपने बच्चों को उसके काबिल बनाना पड़ता है।

सभापति महोदय, अगर मैं पानी की बात करुं तो पानी की स्कीमें बंद पड़ी हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

श्री प्रकाश राणा : गुरुजी, पीने को पानी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि वाइंड अप करिए। जनता हमारी परेशान है। पीने को पानी नहीं है। ये स्वच्छ पानी की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मगर इनको पूछो कि क्या आप इस जनता को फिल्टर्ड वाटर पिला रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्ज़ बीमार लोगों से क्यों भरे पड़े हैं? उनको गंदा पानी मिल रहा है। अगर लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो हमारे अस्पतालों में मरीजों की संख्या आधी हो जाएगी।

सभापति : माननीय सदस्य, अगर किसी पर्टिकुलर जगह का पानी गंदा है तो आप उसका नाम बता दो। ऐसा नहीं है कि हर जगह का पानी गंदा ही है।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, सारा ही पानी गंदा है। मैं विधान सभा के अंदर यह बात रख रहा हूं, आप बताएं कि मेरे चुनाव क्षेत्र जोगिन्द्रनगर में कहां फिल्टर लगा है? टैंकों की सफाई भी नहीं होती। ठीक कहा हमारे एक भाई ने कि उनमें बंदर नहाते रहते हैं। यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) मैं कहता हूं कि पीने को स्वच्छ पानी दे दो।

24.03.2026/1500/केएस/एएस/2

सभापति : माननीय सदस्य, वाइंड अप करिए। आपको बोलते हुए 22 मिनट का समय हो गया है और (***)शब्द बोले गए हैं इनको कार्यवाही से हटा दिया जाए।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, हमें कुछ ना कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। इस प्रदेश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कोई ना कोई स्टेप लें। पहले इस कर्ज को रोको। हम डवलपमेंट के लिए देते ही कितने पैसे हैं, 5-6 हजार करोड़ रुपये पूरे साल में देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई स्टैप लें। सभापति जी, एक तो पता नहीं हमारा टाइम पहले कैसे हो जाता है? कई मित्रों ने 35-40 मिनट बोला है और हमें केवल इतना ही समय मिला लेकिन सभापति महोदय, हम आपका मान-सम्मान करते हैं। जो बजट है हम इसका क्या समर्थन करें? यह बजट पहले ही पीछे की तरफ जा

रहा है, हमने पहले बार देखा है कि बजट उल्टा जा रहा है, वैस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। यह सबसे बड़ी खतरे की घंटी है और अगर हम इससे भी नहीं सीखेंगे तो मैं कहता हूं कि हिमाचल आगे और भी बर्बादी की ओर चला जाएगा, इसे संभाल लो। यह मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और लोक निर्माण मंत्री जी थोड़ा हमें एक्शन का आश्वासन दे दीजिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : (***) शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, माननीय राणा जी ने बहुत अच्छे और सकारात्मक विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने हमारे विभाग केऊपर भी कुछ टीका-टिप्पणी की है। मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन को साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि there is zero percent tolerance against any kind of corruption in the Department और जिस विषय के बारे में आप प्रत्येक सत्र में चर्चा करते हैं, मैं उसके बारे में अभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहता। आप हमसे चैम्बर में आ कर मिल सकते हैं और उस पर हमने क्या कार्रवाई की है या विभागीय तौर पर हम क्या विचार रखते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। मैंने कल भी अपने भाषण में कहा था कि जो भी रिसोर्सिज़ हमें मिल रहे हैं वे प्रदेश के लोगों के हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसका अपना एक प्रोसैस है। हम ना उसको पुश करना

24.03.2026/1500/केएस/एएस/3

चाहते हैं और ना उसमें अपना कोई व्यू रखना चाहते हैं। Whatever is brought to our knowledge हमें उसमें कुछ लगेगा तो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, सभापति महोदय, एक छोटा भाई होने के नाते मेरा माननीय सदस्य से यह भी निवेदन रहेगा कि हर चीज़ में आप सनसनी ना फैलाएं। Sensationalism is not going to lead us anywhere, whether it is people from the Opposition or from the treasury benches, we are here for constructive thoughts. आपने बहुत अच्छे विचार दिए।

अ0व0 द्वारा जारी..

24.03.2026/1505/av/dc/1

लोक निर्माण मंत्री--------जारी

आपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और मैं उस संदर्भ में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। लेकिन आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं और आपकी आवाज में एक वज़ूद है। अगर आप हर चीज में सनसनी पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि वह प्रदेश हित में ठीक नहीं है। आपने कई बार ये चीजें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, we are going through a difficult phase लेकिन हिमाचल उससे बाहर निकलेगा और बहुत जल्दी निकलेगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी उस बारे में अपने प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको उस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके सकारात्मक सुझावों को ऑनबोर्ड लेते हैं। उसमें अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उसके संदर्भ में निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।

24.03.2026/1505/av/dc/2

कृषि मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

सभापति : अब माननीय कृषि मंत्री स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा ने जो विधायक निधि के बारे में बात की है, पहले इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं था। जब स्व0 श्री नरसिम्हा राव हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री थे तो उनसे सांसदों का एक डेलीगेशन मिला। उन्होंने कहा कि हम जब अपने संसदीय क्षेत्रों में एक सांसद बनकर जाते हैं तो हमें जनता पूछती है कि आपके पास हमें देने के लिए क्या है? उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने हरेक सांसद को प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपये के हिसाब से 5 वर्षों में 5-5 करोड़ रुपये देने शुरू किए थे। मेरे संसदीय क्षेत्र में उस वक्त 17 विधान सभा क्षेत्र थे। फिर पैसा मिलने के बाद सांसद अपने-अपने हिसाब से काम करवाने हेतु पैसा देने लगे। उसके बाद भी केंद्र में हमारी ही पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एम0पी0 लैड को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया। यानी एक लोक सभा सांसद को पांच वर्षों में 25 करोड़ रुपये और राज्य

सभा सांसद को 30 करोड़ रुपये की राशि मिलने लगी। इस तरह से उसके उपरांत यह प्रथा हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हुई कि विधायक विकास निधि होनी चाहिए और यह कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है, यह तो एक किस्म से ग्रेस है कि सरकार बजट में से कुछ पैसा आप लोगों को देती है। वर्तमान में आपके चार निर्वाचित सांसद हैं और उन सांसदों को सौ करोड़ रुपये मिलते हैं। राज्य सभा के सांसदों को 90 करोड़ रुपये मिलते हैं। विपक्ष में इस समय 29 विधायक बैठे हुए हैं और इनके सांसदों को कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपये मिलते हैं। वे हमें तो कुछ नहीं देंगे क्योंकि हम तो विरोधी पार्टी से हैं। परंतु यदि आप लोग अपनी प्राथमिकता बनाकर उन सांसदों को देंगे तो वे आपको तो दे सकते हैं। इसलिए आप उससे अपनी खाना-पूर्ति कीजिए।

दूसरी बात, यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा कर रहे थे कि यह डिस्क्रिशनरी ग्रांट नहीं है, यह तो डवलपमैंटल फण्ड है। आपने 800-800 महिला मण्डल बना दिए और विधायक विकास निधि को आप उन महिला मण्डलों को बांट रहे हैं। आप किसी को 50 हजार रुपये की राशि दे देते हैं, वह आप उन्हें किस चीज के लिए देते हैं?

24.03.2026/1505/av/dc/3

यह राशि कोई खाने-पीने के लिए थोड़ी न रखी है। आप उससे कोई परमानैंट स्ट्रक्चर बनाइए। आप उस राशि से कोई महिला मण्डल भवन बनवा दीजिए या रास्ता पक्का करवा दीजिए या फिर कोई और सुविधा तैयार कर दीजिए। आप अपने महिला मण्डलों को 10 प्रतिशत से ज्यादा राशि नहीं दे सकते। इसलिए at least we should adhere to the Law. आपको यह जो पैसा मिल रहा है, यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी ने इस पर थोड़ा अंकुश लगाकर यह राशि इस बार कम दी है। लेकिन आने वाले समय में वे इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए आपको इस बारे में निश्चय करना चाहिए और जो सांसदों को इतना पैसा मिल रहा है, आप उसका तो सदुपयोग कीजिए। आप उनसे मांगिए जो विकास कार्यों हेतु इतना पैसा आ रहा है। कई सांसद तो उस राशि को खर्च ही नहीं करते इसलिए वह राशि अनस्पैंट पड़ी रहती है। मैं आपको इस बारे में अवगत करवाना चाहता था।

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.03.2026/1505/av/dc/4

सभापति : अभी 18 लोग बोलने वाले हैं और मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। अपनी-अपनी बात 10-12 मिनट्स में समाप्त करने की कोशिश करें और बजट पर ही फोकस रखें।

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो दिनांक 21 मार्च, 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए, उस पर पिछले कल से चर्चा शुरू हुई है। मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन भी करता हूं।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1510/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री मोहल लाल ब्राक्टा... जारी

और इस बजट का भरपूर समर्थन भी करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि इस बजट को मुख्य मंत्री जी ने लगभग 4 घंटे 10 मिनट तक पढ़ा। हम सभी लोगों ने इसमें वर्णित बहुत सारी बातों को सुना और यहां पर मेरे से पूर्व विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी काफी चर्चा की । इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरे से पूर्व में माननीय सदस्य राणा जी ने यहां अपनी बात रखी। राणा जी बीच में कुछ बातें अच्छी बोलते हैं फिर अंत में इनको वही भाषा बोलनी पड़ती है जो ओपोजीशन द्वारा बोली जाती है। मेरे ख्याल से राणा जी दूसरी बार विधान सभा के सदस्य बने हैं। मेरा यह तीसरा टर्म है। पहली बार जब राणा जी इस सदन में आए थे तब ये इंडिपेंडेंट थे। जय राम ठाकुर की सरकार थी। उस समय इनका समर्थन इधर था इसलिए उस वक्त इनकी भाषा कुछ और थी, इस बार भाषा कुछ और हो गई है। अच्छी बात है, कई बार आप अच्छा बोलते हैं फिर आखिर में आपको निचोड़ तो वही ओपोजीशन वाला देना पड़ता है। राणा जी, ठीक बात है जो बातें आपने आज यहां कही, यह बातें आप अपनी पार्टी के माननीय

सदस्यों से भी कहें कि आप भी सरकार का साथ दो ताकि हमारा प्रदेश जो इस समय संकट में है, वह इससे उबर सके। बाकी यहां पर जो ओपोजीशन के माननीय सदस्य हैं, वे तो बस यह कहेंगे कि हमारा एम0एल0ए0 फंड बंद कर दिया, सैलरी कम कर दी। लेकिन जो इसमें अच्छी बातें हैं, उनको भी बताया करें और उनके लिए धन्यवाद भी जरूर करना चाहिए। आपका नाबार्ड के तहत 25 करोड़ रुपये बढ़ाया है और 200 से बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये किया गया। उसके लिए आपको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। आपकी जो डी0जी0 बढ़ाई गई है उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं। यहां जल जीवन मिशन की बात आई और राणा जी ने जनरलाइज कर दिया कि पूरे प्रदेश में पानी बेकार है, बुरे हाल हैं लेकिन इनका यह तर्क ठीक नहीं है। आपकी कांस्टीट्यूएंसी में कुछ समस्या हो सकती है क्योंकि आप जिला मण्डी से हैं। पूर्व में पिछली बार आपकी सरकार थी यानी बीजेपी की सरकार थी। श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे और जल शक्ति मंत्री भी आपके ही थे। मैंने आज जल जीवन मिशन का प्रश्न भी लगाया था और उप-मुख्य मंत्री जी ने उसका

जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जो एक स्कीम थी, वह केवल जल के लिए थी। आप लोगों ने मण्डी में पता नहीं उस पैसे से कितने रैस्ट हाउस बना दिए और सारा पैसा उन पर खर्च कर दिया। इसलिए मैं पहले भी सभी माननीय सदस्यों से कहता आया हूं कि हम एक-दूसरे पर छींटाकशी करते रहते हैं कि आपने यह नहीं किया, मैंने वह नहीं किया। कल भवानी जी भी कह रहे थे, उन्होंने अच्छा तर्क दिया कि विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि 28 राज्यों में से कांग्रेस सरकार सिर्फ 2 या 3 राज्यों में हैं बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों रिपीट नहीं हुई?

मैं मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। जिन परिस्थितियों में उन्होंने शपथ ली, उसके बाद त्रासदी आई और त्रासदी के कारण प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई। केंद्र सरकार से कितनी सहायता आई, कितनी नहीं

आई, यह सब आपके सामने है। इन्होंने उन परिस्थितियों में भी सरकार चलाई। जिस समय प्रदेश में त्रासदी आई, मैं शिमला जिला से संबंध रखता हूं और हमारा शिमला जिला बागवानी का क्षेत्र है। उस समय सेब सीजन अपने पिक पर था। मुख्य मंत्री दौरे पर रोहडू आए और

एन0एस0 द्वारा ... जारी

24-3-2026/1515/एन0एस0-एच0के0/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा-----जारी

उनके साथ लोक निर्माण मंत्री भी साथ आए, तब मुख्य मंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि यहां पर सेब सीजन बढ़िया चलना चाहिए और सेब सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे भी दिए ताकि वहां की सड़कों का सुधार हो सके जहां सेब सीजन चलना था। जब मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि आपने लोक निर्माण विभाग को पैसे दिए लेकिन विभाग इस पैसे को वहीं खर्च करेगाा जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं। यहां पर कई सड़कें ऐसी हैं जो हमने एम0एल0ए0 फंड या डी0सी0 फंड या पंचायतों से बनी हुई हैं और लोक निर्माण विभाग उन सड़कों का रख-रखाव नहीं करेगा। मुख्य मंत्री जी ने मेरे दो ब्लॉक्स को पैसे दिए। इन्होंने चुहारा ब्लॉक को 40 लाख रुपये और रोहडू ब्लॉक को भी 40 लाख रुपये दिए। इन्होंने एस0डी0एम और बी0डी0ओज0 को निर्देश दिए कि बागवानों का सेब पिकअप में मंडियों तक पहुंचना चाहिए। लोगों का सेब मंडियों तक पहुंचा और उसके बावजूद इन्होंने आपदा के दौरान सेब का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एम0आई0एस0 के तहत 170 करोड़ रुपये की पेमैंट्स क्लीयर कीं जिसमें 90 करोड़ रुपये पूर्व सरकार के समय के थे। इसके लिए 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से मिलती थी लेकिन अब उसको भी बंद कर दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी व राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यूनिवर्सल कार्टन की कई वर्षों से डिमांड थी और उसको इन्होंने उपलब्ध करवाया। आज हमारी केंद्र सरकार

बागवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आयात शुल्क घटा दिया है जिससे हमारी आर्थिकी पर फर्क पड़ेगा। बागवानी से हमारी आर्थिकी 5,000 करोड़ रुपये की है। इससे बागवानों की आय में भी फर्क पड़ेगा। बागवानी के साथ सैंकड़ों लोग दिल्ली व मुम्बई से भी जुड़े हुए हैं। वर्ष 2014 में मोदी जी ने सोलन में या अन्य स्थानों पर जनसभाएं की थीं। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सोच गांव के लोगों के लिए है। यहां पर कहा गया है कि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। अगर मैं दूध की बात करूं तो 31.80 रुपये दूध का रेट था जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी। हमारी सरकार ने गाय के

24-3-2026/1515/एन0एस0-एच0के0/2

दूध का रेट 51 रुपये और भैंस के दूध का रेट 61 रुपये किया था जिससे गांव की महिलाओं की आमदनी बढ़ी। गांव की महिलाओं के हाथ में पैसा गया और आज इस बजट में फिर रेट बढ़ाए गए। आज गाय के दूध का रेट 61 रुपये प्रतिलीटर और भैंस के दूध का रेट 71 रुपये प्रतिलीटर है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपको यह छोटी बात इसलिए लगती होगी कि हम आज तक बड़े-बड़े उद्योगपतियों की ही बात करते रहे हैं। उद्योगपतियों का अपना स्थान है लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि गांव की गरीब महिलाओं तक पैसा पहुंचे और उनकी आर्थिकी अच्छी हो। आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परसों मैं रोहड़ू गया था और वहां पर मेरे पास 2-3 लोग आए और कहने लगे कि गाय की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मुख्य मंत्री जी ने जब से दूध के रेट बढ़ाएं हैं तो रोहड़ू में एक चिलिंग प्लांट हैं और वहां पर पहले 5000 लीटर दूध प्रतिदिन आता था लेकिन आज 13 से 14,000 लीटर दूध प्रतिदिन आ रहा है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी से मांग रखी कि दूध के रेट बढ़ने से यहां पर दूध की केपेस्टिी बढ़ गई है तो उन्होंने 20,000 लीटर का चिलिंग प्लांट लगाने का निर्णय लिया। मैं इस सदन में माध्यम से मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस चिलिंग प्लांट की केपेस्टिी 20,000 से बढ़ा कर 50,000 लीटर की जाए और चिलिंग प्लांट के साथ-साथ प्रोसैसिंग प्लांट भी रोहड़ू में लगा दिया जाए ताकि सिराज और चौपाल के विधान सभा क्षेत्रों का दूध भी वहीं आए।

सभापति महोदय, भेड़पालक भेड़-बकरियों का व्यापार करते हैं और उनका समर्थन मूल्य पहली बार तय हुआ है। अगर उनके बारे में सोचा तो केवल मुख्य मंत्री

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1520/RKS/HK-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

ने यह पहली बार सोचा है। हमने हल्दी, अदरक और अन्य प्राकृतिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इससे हमारे गरीब वर्ग की आमदनी में इज़ाफा होगा। इस बजट में स्थाई नौकरियां देने की भी बात की गई है लेकिन आप तो हमेशा हम पर दोषारोपण ही करते रहते हैं। श्री जय राम ठाकुर की सरकार में मैं रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र से विधायक था। मेरे विधान सभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्ज हैं उन्होंने उस क्षेत्र की किसी भी डिमांड को श्री जय राम ठाकुर जी के सामने नहीं रखा। पूर्व सरकार के समय श्री जय राम ठाकुर जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ एक शिलान्यास किया था। यह ठीक है कि जो योजनाएं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय क्रियान्वित हुई थीं उनके उद्घाटन श्री जय राम ठाकुर जी ने किए। इन्होंने सब-तहसील, जांगला का शिलान्यास किया और यह शिलान्यास भी बिना बजट के ही कर दिया था। मेरे विधान सभा की सड़कों, जिनमें चाहे डोडरा-क्वार क्षेत्र की सड़कों की बात हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन बनाने की बात हो, डॉक्टर्ज रेजिडेंस या फिर अन्य योजनाओं की बात हों, ये सब कार्य पूर्व सरकार के समय ठप हो गए थे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई मेरे चुनाव क्षेत्र के जितने भी कार्य लंबित थे उनका कार्य प्रारंभ हो गया। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और लोक निर्माण मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन के लिए बजट मुहैया करवाया। आज मेरे चुनाव क्षेत्र में तकरीबन सारे काम चले हुए हैं। डोडरा-क्वार के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 के फेस-1 में 45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। वह

पैसा लैप्स हो गया था। मैंने इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह किया और इन्होंने दिल्ली जाकर उस पैसे को जारी करके इस योजना की एक्सटेंशन ली। अब वह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर जो सरकारी भवन और सड़कें निर्मित होनी हैं उनका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। ...(घंटी) सभापति

24.03.2026/1520/RKS/HK-2

महोदय, आपने घंटी बजानी शुरू कर दी है। अगर आप मुझे 2-3 मिनट का और समय देंगे तो मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप मेरा यह भी रिकॉर्ड निकाल लेना कि मैंने हमेशा निर्धारित समय में अपनी बात पूरी की है। कभी भी मेरे लिए घंटी बजाने की नोबत नहीं आई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार के समय मेरे चुनाव क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये के करीब एक पावर चैनेलाइजेशन प्रोजैक्ट का कार्य होना था। इस योजना में श्री रोहित ठाकुर जी के क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी कवर होता था लेकिन ये उस प्रोजैक्ट को भी वापिस ले गए। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है वहां के लोगों की डिमांड थी कि वहां पर एक रेस्ट हाउस स्थापित किया जाए। जब वहां पर राजा वीरभद्र सिंह जी का दौरा था तो मैंने उनके सामने इस डिमांड को रखा। उन्होंने इसके लिए घोषणा की और 1.20 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए। लेकिन जैसे ही श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार सत्ता में आई इन्होंने उस पैसे को वापिस ले लिया। सिसारा में पुल स्थापित करने के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, आपने उस राशि को भी वापिस ले लिया। इन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए दिया तो कुछ नहीं उल्टा लेने का काम किया है। यह बात सही है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो इन्होंने शाम को मेरे चुनाव क्षेत्र में दो सब-तहसीलें जिनमें एक समरकोट और दूसरी धमवाड़ी में खोलने की घोषणा कर दी। जैसे ही हमारी सरकार बनीं इन संस्थानों को भी डिनोटिफाई कर दिया गया। मेरा जन्म स्थान कुटाड़ा नामक स्थान पर हुआ है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1525/बी.एस./एच.के.-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

मैंने मुख्य मंत्री का धन्यवाद किया कि हमारी धमवाड़ी की सब-तहसील खुल गई है। मैं आज मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि समरकोट की सब-तहसील को भी जल्दी-जल्दी खोलने की कृपा करें। इसके अलावा हमारा राहड़ू-शिमला रोड है। वैसे तो अब बर्फ कम पड़ती है, लेकिन खड़ा पत्थर में कई बार बर्फ पड़ने से रोड बंद हो जाता है। पहले भी इसके लिए टनल का प्रावधान था। अब इसकी कंसलटेशन भी हो गई है। अगर खड़ा पत्थर में सुरंग बन जाए तो हमारा 13-14 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा।

इसके अलावा हमारा डोडराक्वार 6 महीने कट रहता है। वहां के लिए भी मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि टनल और स्योहडोगरी-उत्तराखंड रोड खोला जाए, ताकि वहां के लोगों का 12 महीने संपर्क बना रहे। इसके अलावा कहने को बहुत सारी बातें हैं। मेरा चुहारा ब्लॉक सारा बैकवर्ड एरिया है। वहां पर मेरी सी0एच0सी0 है, जो 32 पंचायतों का क्षेत्र कवर करती है। मैं मुख्य मंत्री का और पंचायती राज मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी अभी 7 नई पंचायतें बनाई गई हैं। इसके अलावा 4 पंचाायतें हमारी चुहारा ब्लॉक की बनी हैं इस प्रकार वहां 32 से 36 पंचायतें हो गई है। वहां पर मेरी सी0एच0सी0 है उसे अपग्रेड करके सिविल अस्पताल बनाने की आवश्यकता है और वहां पर डिविजन खोलने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कहने को बहुत सारी बातें हैं। जहां तक बजट की बात है, विपक्ष के साथी कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने इसे 4 घंटे पढ़ा है। मान लिया कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि बजट बिल्कुल खराब है। मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं, बावजूद इन परिस्थितियों के वर्ष 2023 में त्रासदी आई, वर्ष 2025 में भी कठिन परिस्थितियां आईं। परंतु केंद्र से कोई कोई मदद नहीं मिली। फिर भी इतना अच्छा बजट पेश किया गया कि विपक्ष के साथियों ने

कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना अच्छा बजट आ सकता है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मछुआरों के लिए जो प्रावधान रखा गया है यह भी पहली बार रखा गया है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें भेड़ पालकों का भी ध्यान रखा गया है।

24.03.2025/1525/बी.एस./एच.के.-2

मैं अपने कार्यकाल में तीसरा मुख्य मंत्री देखा रहा हूं, हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह चौथा बजट पेश किया है। मैं यह नहीं कहता कि पिछले मुख्य मंत्रियों ने अच्छे बजट पेश नहीं किए लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इस बजट की कुछ और ही दिशा है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। जहां तक एम0एल0ए0 फंड की बात आती है आपने तो कोविड के दौरान विपक्ष को तो कभी पूछा तक नहीं। आपने कितनी मनमानी की? हमारे को दूसरे दिन पता लगता था कि एम0एल0ए0 फंड बंद कर दिया हमारी सैलरी बंद कर दी। आपने तो डिक्टेटर वाला महौल तैयार किया था।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है परंतु समय का अभाव है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं और साथ ही साथ आदरणीय राणा जी से कहूंगा कि आप जो माननीय सदन में उपदेश देते हैं अपने साथियों को भी दिया करो। आपकी करनी और कथनी में अंतर होना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : जो कटऑफ हुआ यह कोई विधायक का है न सरकार का है प्रदेश की 75 लाख जनता का फैसला है और उनके हित का फैसला है। मुख्य मंत्री ने पूरे प्रदेश का ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसका धन्यवाद, जय हिंद।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1530/DT/YK-1

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, 21 मार्च, 2026 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री सुखविंद्र सिंह सक्खू जी ने अपनी सरकार का यह चौथा बजट यानी अपनी सरकार का सैकंड-लास्ट बजट भी प्रस्तुत किया है। मैं भी इस चर्चा में खुद को शामिल करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभपति महोदय, पिछले कल माननीय लोक निर्माण मंत्री जी चर्चा में भाग ले रहे थे। जब वह बोल रहे थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क में सी0आर0आई0एफ0 यानी Centre Road Infrastructure Fund में व अन्य मदों में हिमाचल प्रदेश को 4480 करोड़ रुपये सड़क के निर्माण कार्य व उनके रख-रखाव के लिए दिया गया है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों से संबंधित कार्य चला है इसी धनराशि से सड़कों का काम किया जा रहा है। उन्होंने एक और बात का जिक्र भी किया के आज से पहले हिमाचल प्रदेश को केंद्र से इतना बजट कभी नहीं मिला। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम में दम था और हमनें हिमाचल का पक्ष दमदार तरीके से केंद्र के सामने रखा जिसके कारण प्रदेश को 4480 करोड़ रुपया का बजट सड़कों के लिए केंद्र सरकार से आया। हिमाचल प्रदेश की सड़कों के लिए यह जो बजट केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है वहां तो एन0डी0ए0 गठबंधन की सरकार है और लोक निर्माण मंत्री द्वारा इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री व माननीय प्रधान मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने यह भी कहा कि मैंने दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा- मैंने दम भी दिखाया। मैं बजट बुक देख रहा था मैंने कहा कि माननीय लोक निर्माण मंत्री ने बड़े दम की बात की है और जब बजट बुक देखी तो उस बजट बुक के अंदर मैंने पाया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का स्टेट बजट शून्य है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो दम आपने दिल्ली में प्रधान मंत्री जी के पास जाकर या नितिन गडकरी जी के पास जाकर दिखाया, क्या वह दम आप हिमाचल प्रदेश की सड़कों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने नहीं दिखा सके? अगर इन्होंने यह दम यहां भी दिखाया होता तो आज

24.03.2026/1530/DT/YK-2

इस बात को कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में जो इस बार का बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट में स्टेट हैड में हमने लोक निर्माण विभाग के लिए इतना बजट लिया है- लेकिन उसमें आप कहीं-न-कहीं (***) पाए गये हैं।

सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी भी इस समय इस मान्य सदन में बैठे हैं और मुझे आज भी ध्यान में है कि जब इसी सदन में इस सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ हमने कहा कि

.---

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

श्री ए0जी0द्वारा जारी..

24.03.2026/1535/ए.जी.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार..... जारी

आपने अटल आदर्श विद्यालय बंद कर दिए। इन्होंने कहा कि उसका विकल्प ढूंढा जा रहा है और जो चल रहे हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा और नई योजना लेकर आएंगे। प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की घोषणा की कि हम हर विधान सभा क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि इनमें इनडोर व आउटडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह भी कहा गया कि वहां पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्कूलों में कमरे नहीं हैं और यहां पर स्विमिंग पूल की बात की जा रही है और लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस पहले बजट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की बात यहां पर की गई थी कि 300 करोड़ रुपये का बजट इन स्कूलों के लिए रख दिया गया है। उसके बाद अगले साल भी बजट

प्रस्तुत हुआ और उसमें भी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए और बजट रखा गया है। मैं देख रहा था कि वर्ष 2025–26 के बजट में भी आपने 31 करोड़ रुपये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए अनाउंस किया है। इस बार की बजट बुक में भी 99 करोड़ रुपये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए रखने की बात कही गई है।

सभापति महोदय, मैंने जैसे कहा कि यह सरकार का सेकंड लास्ट बजट है और अगली बार लास्ट बजट होने वाला है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) क्योंकि शायद जब यह योजना शुरू की गई तो इनको (माननीय शिक्षा मंत्री के लिए कहा) भी नहीं पूछा गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री को पूछना चाहता हूं कि तीन साल व तीन महीने आपकी सरकार को हो गए हैं और आपने कितने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए हैं?

24.03.2026/1535/ए.जी.-एन.जी./2

लेकिन सरकार नहीं बता पाएगी क्योंकि एक भी स्कूल शुरू नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए थे। मुख्य मंत्री जी ने वहां पर घोषणा की कि नाचन विधान सभा क्षेत्र की छात्तर पंचायत के अंदर हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। लेकिन वहां पर जगह है या नहीं? मैंने उनसे कहा कि जब जगह का प्रोसेस चला था तो फर्स्ट राउंड में ही मैंने कागज दे दिए थे। आपने 50 बीघा जमीन मांगी थी और हमने 55 बीघा सरकारी जमीन दी है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन रहेगा कि बजट में जो 99 करोड़ रुपये की बात की गई है, उसमें से थोड़ा बजट हमारे यहां भी दिया जाए ताकि छात्तर के स्कूल का कार्य शुरू हो सके। सभापति महोदय, यहां पर अभी बात की गई...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : माननीय सदस्य, आप यह बताइए कि श्री जय राम ठाकुर जी आज दिल्ली गए हैं तो क्यों गए और अब रुकवाने के लिए क्या बचा है?

श्री विनोद कुमार : उप-मुख्य मंत्री जी, आप चिंता मत करें क्योंकि श्री जय राम ठाकुर जी केंद्र सरकार का धन्यवाद करने गए हैं। क्योंकि पिछले कल श्री विक्रमादित्य सिंह जी (माननीय लोक निर्माण मंत्री) ने कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा इतना ज्यादा बजट यहां पर दिया गया है और इसके लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद तो करना चाहिए। आपने तो धन्यवाद किया नहीं, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया जाए। इसीलिए श्री जय राम ठाकुर जी प्रदेश सरकार व प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करने गए हैं और आने वाले समय में प्रदेश के लिए और वित्तीय सहायता की जाए, उसके लिए भी श्री जय राम ठाकुर जी दिल्ली गए हैं। आप चिंता मत करें।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ यहां पर उप-मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1540/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री विनोद कुमार जारी .....

सभापति महोदय, मैं बजट बुक पढ़ रहा था और उसमें लिखा है। मुझे यह नहीं मालूम कि उप-मुख्य मंत्री जी से पूछा गया या नहीं पूछा गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें लिखा है कि हमारे पर्वतीय झरने, नदियां और जल स्रोत हिमाचल को और पूरे उत्तर भारत को जीवन का अमृत, शुद्ध जल प्रदान करते हैं। अब इनको पूछा गया कि नहीं पूछा गया, मुझे नहीं पता। आपने तो बात पूरे उत्तर भारत की कर दी। मैंने सुबह भी शून्यकाल में कहा था। मैंने कहा सर, नाचन विधान सभा क्षेत्र का हमारा सब-डिवीजन गोहर, जहां पर लगभग 250 व्यक्तियों को पीलिया हो गया है और मैंने यह भी कहा कि दो नौजवान बच्चों की मृत्यु हो गई है। जब पीलिया फर्स्ट स्टेज में था तो सरकार कहां सोई थी? विभाग कहां सोया था? जब आपको कहा गया कि उस क्षेत्र में पीलिया फैल रहा है। उस समय सरकार की जिम्मेदारी थी कि किन कारणों से पीलिया फैला रहा है, किन कारणों से जॉन्डिस हो रहा है। यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन मैं आज जलशक्ति विभाग के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जिन दो नौजवान बच्चों की मृत्यु

हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? एक परिवार का जिक्र करना चाहता हूं। उदित शर्मा, सुपुत्र श्री दीपक शर्मा, गांव दाड़ी। सभापति महोदय, परिवार का एक ही बेटा था। 29 वर्ष की आयु में पीलिया के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हम यहां पर अभी भी सुधार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सानिया वाईफ ऑफ श्री सौरभ, गांव रॉडी, 19 साल की एक बेटी जिसने पीलिया के कारण अपनी जान गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं जलशक्ति विभाग से पूछना चाहता हूँ, मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि मैंने सुबह भी इनको कहा था कि आपको इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी सुन रहा था माननीय मोहन लाल ब्राक्टा जी कहा रहे थे कि जल जीवन मिशन पिछली सरकार लेकर आई और यह भी कह रहे थे कि जो जल जीवन मिशन को लेकर आए वे मंत्री आदरणीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी मण्डी से है। मैं आज भी इस बात को दावे से कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि जो काम जल शक्ति विभाग में माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार

24.03.2026/1540/ए0जी0/ए0पी0/-02

में माननीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने किया है वैसा काम कोई नहीं कर पाएगा, इस बात को मैं स्पष्टतौर पर कहना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर विधान सभा क्षेत्र को अनेक स्कीमें केंद्र सरकार की ओर से दी गई हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की समस्या को खत्म किया जा सके। ये बात ठीक है कि हमारी सरकार के समय सब ठीक था। लेकिन अगर इस सरकार के समय कुछ गलत हो रहा है, अगर इस सरकार के समय जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया फैल रहा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये मेरा निवेदन रहेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के तहत 1292 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे इस परियोजना में 7 जिलों के 52 विकास खंडों में काम किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि 6 हजार हेक्टेयर भूमि पर 400 क्लस्टर बनाए जायेंगे जिससे 15 हजार किसानों को इसका लाभ होगा। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन 400 क्लस्टरों का जिक्र यहां किया गया है, उनमें कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जहां अभी तक बाड़बंदी नहीं हो पाई है। उन 400

क्लस्टरों में ऐसे भी हैं जहां पर सिंचाई का पानी अभी तक पहुंच नहीं पाया है। इन 400 क्लस्टरों में कुछ क्लस्टर ऐसे भी हैं जहां पर खराब पौधे दिये गये थे। उन खराब पौधों के कारण बहुत सारे पौधे खराब हो गये और सुख गये। हमने विभाग को इस बारे में अनेक बार कहा भी कि जिन क्लस्टरों में पौधे सुख गये हैं,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1545/AT/AS/01

श्री विनोद कुमार जारी ...

उन क्लस्टरों में सरकार अच्छी किस्म के नए पौधे लगाए ताकि हमारे बागवानों का भला हो सके। लेकिन अभी तक उन्हें पौधे नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पलोटा विधान सभा क्षेत्र में मुसम्मी तैयार हो गई है लेकिन इस बार उसे खरीदने कोई नहीं आया। बागवानों को अपनी मुसम्मी चंडीगढ़ ले जानी पड़ी जहां उन्हें 10 से 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचनी पड़ी।

मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बागवानों को उनके फलों का उचित दाम मिल सके। यह मेरा सरकार से निवेदन रहेगा और जहां तक क्लस्टर की बात है, मैं कृषि मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत पलोटा में हमारे दो क्लस्टर हैं। दोनों क्लस्टरों में मुसम्मी तैयार हो चुकी है और पिछले 2 सालों से वहां फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कृपया उनकी भी चिंता करें। इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, यहां नौजवानों और बच्चों के लिए भी बात की गई। मैंने देखा कि प्रदेश सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए ‘खेलो हिमाचल और चिट्टा मुक्त अभियान’ शुरू करने जा रही है, जिस पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी और इसमें कहा गया कि वॉलीबॉल, कबड्डी और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। इसमें 15 से 30 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रतियोगिताओं के लिए तो पैसा देना शुरू कर दिया, पर बच्चे अभ्यास कहां करेंगे? जब ग्राउंड ही नहीं होंगे,

तो बच्चे प्रैक्टिस करने कहां जाएंगे? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय जो ‘मुख्य मंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ चलती थी, इस योजना के तहत हर विधान सभा क्षेत्र को हर साल 15 लाख रुपए प्लेग्राउंड बनाने के लिए दिए जाते थे। इसे दोबारा शुरू किया जाए, ताकि हम अपनी विधान सभा के स्कूलों में अच्छे खेल मैदान बन सकें और बच्चे वहां अभ्यास कर सकें। यह मेरा सरकार से निवेदन रहेगा।

24.03.2026/1545/AT/AS/02

माननीय सभापति महोदय, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ...(व्यवधान) सर, नहीं दिये जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी हो सकता है कि कांग्रेस के विधायकों को यह सुविधाएं दी जा रही हो और बीजेपी वालों की बंद कर दी गई हो। माननीय सभापति जी, अभी माननीय ब्राक्टा जी कह रहे थे कि गाय का दूध 61 रुपए और भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार लेगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि कांगड़ा में 1,50,000 लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात कही है और नाहन, ऊना तथा हमीरपुर में मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग प्लांट लगाने की भी बात इस बजट में की है। लेकिन मैं आपको कहना चहता हूं कि मंडी के चक्कर में जो मिल्क प्लांट है, वहां वर्तमान में लगभग 1 लाख लीटर दूध आ रहा है जबकि उसकी क्षमता केवल 50,000 लीटर है। अब आप बताइए कि 50,000 लीटर की क्षमता वाले प्लांट में 1 लाख लीटर से ज्यादा दूध आ रहा तथा और कई किसान अपने पशुओं का दूध वहां देना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि एक दिन एक क्षेत्र का दूध लिया जाता है, दूसरे दिन दूसरे क्षेत्र का और तीसरे दिन तीसरे क्षेत्र का दूध लेंगे। इससे कई किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि चक्कर के मिल्क प्लांट की प्रोसेसिंग क्षमता 50,000 लीटर से बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों का दूध वहां पहुंच सके।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1550/केएस/एएस/1

श्री विनोद कुमार जारी ..

उस क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों का दूध मिल्क प्लांट तक पहुंच पाए। इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं , हमने देखा है कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनको समय पर दूध का पैसा नहीं मिलता। अनेकों बार हमें लोगों की ओर से फोन आते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि किसानों को दूध के पैसे समय पर दिए जाएं, इस बात को भी सरकार सुनिश्चित करें। सभापति महोदय, मैं देख रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने बजट बुक में कहा है कि कई चरणों में चर्चा के बाद अधूरे 300 कार्यों की सूची तय की गई है। अब यह चर्चा पता नहीं किसके साथ हुई। ऐसे 300 कार्य जिनका काम पैंडिंग है, उनकी चर्चा अनेकों चरणों में करने के बाद उन 300 कार्यों के लिए सरकार ने कहा है कि 500 करोड़ रुपये हमने इस बजट में रखा है। विधान सभा में तो हमसे इन्होंने कभी चर्चा नहीं की, उधर के साथियों से की या नहीं, यह पता नहीं है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की जो बात कही है तो नाचन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा इंडोर स्टेडियम का काम रुका पड़ा है, अटल आदर्श विद्यालय का काम रुका पड़ा है और लगभग 5 ऐसी साइंस लैब्ज़ हैं जिनका काम रुका पड़ा है। मेरा निवेदन है कि उनको भी आप इसमें शामिल करें ताकि उनके लिए भी पैसा आ सके।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, बस मेरा लास्ट प्वाइंट है। सरकार की तरफ से हैल्थ को ले कर बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं। मुझे आज भी याद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला बजट पेश किया था तो कहा था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैडिकल कॉलेज हैं उन सभी के अंदर पैट स्कैन की सुविधा दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे मैडिकल कॉलेज हैं जहां पर पैट स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है? इनके पास उत्तर नहीं होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक भी मैडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर यह सुविधा सरकार की ओर से शुरू की गई है। सरकार ने यह भी कहा था कि हम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान देंगे और उनमें

अच्छे डॉक्टर तथा 134 तरह के टैस्ट करवाए जाएंगे। साथ में यह भी कहा था कि एम0आर0आई0, सीटी स्कैन तथा

24.03.2026/1550/केएस/एएस/2

अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि 68 के 68 विधान सभा क्षेत्रों में ये खोल दिए जाएंगे लेकिन कितने विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ना पूरे डॉक्टर हैं, ना एम0आर0आई0, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड की सुविधा अभी तक सरकार की ओर से शुरू की गई है। सरकार ने सिर्फ झूठी घोषणा करने की बात की है, इस बात को भी मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सहारा योजना का जिक्र नहीं किया, हिमकेयर जैसी योजना जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति का उपचार होता है, उसका जिक्र नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को ले कर सरकार ने सिर्फ बातें ही की हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित होगा। अब 31 मार्च तो आने वाला है, आज 24 तारीख हो गई, 7 दिन शेष बचे हैं तो यह कब होगा? उन्होंने यह भी कहा था कि हम इतनी इलैक्ट्रिकल बसें खरीदेंगे, 1500 डीजल की बसों को इलैक्ट्रिकल बसें करेंगे। कितनी हुईं कोई पता नहीं। इसके अलावा यह भी कहा था कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ...

24.03.2026/1555/av/dc/1

श्री विनोद कुमार--------जारी

हिमाचल प्रदेश वर्ष 2027 में आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है? लोग आत्मनिर्भर कर दिए और प्रदेश जहां खड़ा था वहां से भी दस कदम पीछे कर दिया और मैं इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है, इसमें प्रदेश की जनता के हित में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

24.03.2026/1555/av/dc/2

सभापति : माननीय सदस्य ने जो (***) शब्द का इस्तेमाल किया है उसको एक्सपंज किया जाए।

अब माननीय उप-मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे।

उप-मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

उप-मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, देखने वाले की नज़र चाहिए और इन्होंने यहां पर जल जीवन मिशन के बारे में बात की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल जीवन मिशन को भारत सरकार ने प्लान किया है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को भी 6300-6400 करोड़ रुपये देने का फैसला हुआ था। लेकिन पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जाते हुए यह लिखकर दे दिया कि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन पूरा हो गया है। उसका नुकसान यह हुआ कि उस समय तक हमें जो पैसा आया था और उसके बाद जो पैसा प्लानिंग में था जिससे कि काम हो चुके थे या फिर कार्य पूरे होने थे, भारत सरकार ने यह कह दिया कि आपकी सरकार ने लिखकर दे दिया है कि आपका जल जीवन मिशन पूरा हो गया है। जब आपका जल जीवन मिशन पूरा हो चुका है तो आपको पैसा किस चीज के लिए दिया जाए। उसी बारे में अब एक लड़ाई व संघर्ष चल रहा है। हम दिल्ली लगातार जा रहे हैं कि आपने 5100 करोड़ रुपये दिए जबकि आपने वायदा लगभग 6400 करोड़ रुपये देने का किया था। वह शेष राशि जो नहीं आ रही है और जिसके बारे में माननीय सदस्य लगातार बात कर रहे हैं कि स्कीम्ज पूरी नहीं हो रही है तो उसकी मुख्य वजह यही है। चुनाव आने के कारण सरकार को यह घोषित करना था कि राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए कागजों में घोषित कर दिया गया।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे हिमाचल का संतुलित विकास करने का एक मौका मिला था। लेकिन वह सारा पैसा केवल 8-10 निर्वाचन क्षेत्रों को बांट दिया गया जबकि बाकी सारे निर्वाचन क्षेत्र केवल नलकों तक सीमित होकर रह गए जैसे कहा जाता है कि 9 लाख नलके लगा दिए गए। नलके तो लगा दिए परंतु वह जो स्कीम्ज थीं वे केवल 8-10 विधान सभा क्षेत्रों तक गईं जबकि वह पैसा पूरे हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए था। अब तो भारत सरकार इस बारे में जांच भी कर रही है और इस बारे में कई एफ0आई0आर्ज0 भी दर्ज कर दी गई हैं। कई लोग तो

24.03.2026/1555/av/dc/3

जेलों में भी भेज दिए गए हैं। लेकिन हिमाचल का पैसा रुका हुआ है और पिछले वर्ष इसमें शून्य बजट आया है। हम इस संदर्भ में बहुत बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से भी मिले और इस बारे में भारत सरकार से पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि रुकी हुई है, वह पैसा अभी तक नहीं आया है। उस बारे में एक संघर्ष चल रहा है। यह सही है कि यह पैसा लगभग 5100 करोड़ रुपये के करीब आया और उसकी यूटिलाईजेशन हुई परंतु उसके बाद भारत सरकार से पैसा ही नहीं आया तो स्कीम्ज को पूरा कैसे किया जा सकता है?

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा भाग लेंगे।

अगला वक्ता टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1600/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री विवेक शर्मा (बिक्कू) : आदरणीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी द्वारा बजट अनुमान पेश किया गया है, मैं उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। सरकार का यह चौथा साल है। हमारा देश और प्रदेश एक कृषि प्रधान है और यहां पर बजट में सबसे ज्यादा महत्व ग्रामीण वर्ग को दिया जाता है यानी यानी यह देखा जाता है

कि उस वर्ग को बजट में क्या दिया गया? जब हम इस बजट बुक को देखते हैं तो शुरुआती तौर से लेकर अंत तक एक ही चीज सबसे ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। यह ठीक है कि बजट में पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ा अंतर नजर आ रहा है और उसके संदर्भ में लगातार इस सदन में चर्चा भी हो रही है। हमारी जो ग्रांट बंद कर दी गई है उसका असर बजट में भी दिखाई दे रहा है लेकिन जब हम इस बजट को गहराई से देखते हैं तो इस बजट में किसान और बागवान वर्ग को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस वर्ग के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारा किसान फसलों के साथ-साथ दूध बेचता था लेकिन दूध का न्यूनतम मूल्य तय नहीं था। आज उस वर्ग को दूसरी बार दूध के रेट में 10 रुपये की वृद्धि दी गई है और 6 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बढ़ाए गए हैं। इससे उनकी आजीविका मजबूत होगी। इसी तरह गेहूं और मक्की के रेट में भी बढ़ौतरी हुई है। इससे साफ दिखाई देता है कि किसान की अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है।

सभापति महोदय, पहले जब भी विधान सभा का सत्र शुरू होता था तो चौड़ा मैदान से लेकर यहां तक विभिन्न वर्गों के लोग झण्डे उठाकर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहते थे लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज चौड़ा मैदान से लेकर विधान सभा तक ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपनी मांगों को लेकर यहां बैठा हो क्योंकि हर वर्ग की मांगों को इस बजट में कहीं-न-कहीं पूरा किया गया है, चाहे वह मल्टी टास्क हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या आंगनबाड़ी सहायिका हो, इस बजट में जो वर्ग पहले उपेक्षित था, उसका ध्यान में रखा गया है।

24.03.2026/1600/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

अगर हम मल्टी टास्क वर्कर्ज की बात करें तो पहले उनके लिए बहुत कम राशि तय थी और उनको 3000 या 3500 रुपये दिए जाते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने लगातार उनकी सैलरी बढ़ाई है। विपक्ष यह कह रहा है कि हैल्थ सैक्टर में कुछ नहीं हुआ, शिक्षा सैक्टर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या तीन वर्ष पहले स्कूलों में हर जगह अध्यापक थे, क्या हर

हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध थे, क्या हर हॉस्पिटल में एक्स-रे मशीनें और अल्ट्रासाउंड की सुविधा थीं? विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर विपक्ष सरकार के साथ मिलकर काम करता और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाता तो इस बजट में और भी अधिक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल सकती थीं।

इसके बावजूद मुख्य मंत्री ने इस बजट को दूरदर्शिता के साथ तैयार किया है जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। विशेष रूप से तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को इस बजट में लाभ मिला है। नर्सिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ाकर 25000 रुपये की गई है। इसी प्रकार अन्य वर्गों के लिए भी वेतन में वृद्धि की गई है। इसके साथ-साथ यह भी देखा गया है कि पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदाएं आईं। इन आपदाओं के दौरान केंद्र सरकार की टीमों ने दौरा किया, आंकलन किया और कहा कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ह। लेकिन वह राशि प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

24-3-2026/1605/एन0एस0-एच0के0/1

श्री विवके शर्मा (विक्कू)-----जारी

उसके बाद प्रधानमंत्री जी यहां दौरे पर आए और उन्होंने भी घोषणा की कि प्रदेश को पैसा दिया जाएगा लेकिन वह पैसा भी आज तक नहीं मिला। जब ये पैसे नहीं मिले तो मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट से 4500 करोड़ रुपये की राशि आपदा पीड़ितों को दी। मैं इसका सबूत आपको दे सकता हूं। जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारिश से नुकसान हुआ, जिनके मकान गिरे, चाहे उनका आंशिक नुकसान हुआ या भारी नुकसान हुआ तो हमने लगभग 3.50 करोड़ रुपये उनको दिए। वहां पर समय रहते हर वर्ग का ध्यान रखा गया और जो भी वायदा उनके साथ किया गया था उसको पूरा किया गया। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं तो कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार का लगातार दबाव बना रहा लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने ओ0पी0एस0 दी।

सभापति महोदय, इस माननीय सदन में हर बार गौ संरक्षण की बात की जाती थी और पूर्व सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया था। मुख्य मंत्री जी ने हर बार बजट में गौ सेवा के लिए पैसे का प्रावधान कर राशि बढ़ाई है। इस बार बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि कुछ ऐसे लोग या संस्थाएं जो गौशाला को अडॉप्ट करके सेवा करना चाहती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मछली पालकों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मेरे क्षेत्र में 2400 परिवार ऐसे हैं जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं। आज उनके लिए इस बजट में डीप-फ्रीज का प्रावधान किया गया है क्योंकि मछली को 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। इससे उन लोगों को फायदा हुआ क्योंकि उनको आज इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी, उनके जाल के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उनके लिए मोटर साइकिल का प्रावधान भी किया गया है। आज से पहले इन चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा गया था। मेरे क्षेत्र में 2400 परिवार गोबिंद सागर डैम के साथ जुड़े हैं और उनको इससे फायदा होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों की राशि 1700 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई है। आज से पहले इस वर्ग के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया था। जब वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने पहली बार शपथ ली और इन्होंने उस दिन से ही एक नई प्रक्रिया शुरू की कि वे शपथ लेने के बाद सबसे पहले ऐसे

24-3-2026/1605/एन0एस0-एच0के0/2

आश्रम में गए जिन बच्चों के माता-पिता नहीं थे। इन्होंने प्रदेश में 'मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना' चलाई। ऐसे बच्चों को 'Children of the State' का दर्जा दिया गया। आज उन बच्चों को पढ़ाया-लिखाया जा रहा है और विदेश यात्रा पर भी भेजा जा रहा है जिन बच्चों के बारे में शायद परिवार के लोग भी असमर्थ हो जाते थे कि ऐसे बच्चों का पालन-पोषण कैसे किया जाए? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया और उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। यह अपने आपमें एक बहुत अच्छी सोच है ताकि हमारा ग्रामीण परिवेश और ज्यादा मजबूत हो सके। अगर हमारी ग्रामीण आर्थिकी मजबूत होती है तो प्रदेश अपने आप मजबूत होगा।

सभापति महोदय, बी0पी0एल0 से संबंधित जो 1 लाख परिवार हैं उनको मकान तो दिए जाएंगे और मकान बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा तथा 1500 रुपये भी दिए जाएंगे। आज से पहले यह कभी नहीं हुआ। बी0पी0एल0 परिवारों की बेटियों की शादियों के लिए राशि 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये की गई है। इससे ग्रामीण परिवेश के लोगों को फायदा होगा और यह बजट में सराहनीय बात है। अभी हाल ही में कमीशन की तरफ से स्टाफ नर्सिज की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उससे पहले लगभग 6,000 रोजगार शिक्षा विभाग में दिए गए हैं। आज स्कूलों में स्टाफ की बढ़ोतरी हो रही है। दिन-प्रतिदिन किसी-न-किसी क्षेत्र में रोजगार का प्रावधान किया जा रहा है। पिछले समय में

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1610/RKS/HK-1

श्री विवेक शर्मा (विक्कू)... जारी

अगर पूर्व सरकार के समय यह नियुक्तियां हुई होती तो शायद आज यह जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी स्कूल में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं था लेकिन वर्तमान सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य चयन आयोग और आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों की भर्तियां की। जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्राइवेट स्कूलों के साथ शिक्षा की तुलना करने लगे तो सरकार ने कुछ सरकारी स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 करने का बड़ा फैसला लिया। जो लोग अपने बच्चों को सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम से पढ़ाना चाहते हैं उन्हें आने वाले समय में यह सुविधा मिलेगी। इस सरकार के बनने के बाद बच्चों को खेलों में भी काफी प्रोत्साहित किया गया। हिमाचल प्रदेश में पहले बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेते हुए नहीं देखा जाता था। अम्ब से जिस लड़के ने ओलम्पिक खेल में भाग लिया उसे सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। हमारी जिस बहन ने महिला क्रिकेट टीम में भाग लिया था उसे भी 3 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। आज से पहले कभी भी स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा

देने के लिए पुरस्कार के रूप में इतनी राशि नहीं दी जाती थी। सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिन कॉलेजों में बच्चों की स्ट्रेंथ कम है उन्हें दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने पर 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे जोकि सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। जब हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात नहीं कर रहे थे तो आप इसका विरोध कर रहे थे और अब हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप यह कैसे करेंगे। आपको पहले यह समझ लेना चाहिए कि हमें किस बात का विरोध करना है और किस बात के पक्ष में बोलना है। जब हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इतनी बिजली कहां खर्च होगी? आपको यह समझना होगा कि आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है? रोबोटिक सर्जरी की हिमाचल में कभी कल्पना नहीं की गई थी लेकिन आज इस सर्जरी की शुरूआत हो गई है जोकि बहुत बड़ी सोच है। आने वाले समय में और भी मेडिकल कॉलेजिज में रोबोटिक सर्जरी को लाया जा रहा है जोकि मुख्य मंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। जो चीजें हमें एम्स,

24.03.2026/1610/RKS/HK-2

दिल्ली में जाकर मिलती थी आज वे चीजें हमें हिमाचल प्रदेश में ही उपलब्ध हो रही हैं। इस बजट में हमारे युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रावधान किया गया है। बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे हमारे प्रदेश का भविष्य नशे से दूर रहेगा। जिन लोगों के मकान प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गए थे उन्हें मुख्य मंत्री जी ने 7-7 लाख रुपये देने का प्रावधान किया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे चुनाव क्षेत्र में जिन लोगों के मकान पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें इसका मुआवज़ा मिल गया है। इस बजट में जो चीजें कही गई हैं, मैं उन सब चीजों का समर्थन करता हूं। यह बजट हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के हित में है और इससे उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। आज हल्दी का रेट 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। जो लोग किसानी के साथ जुड़े हैं उनको इस बात का जरूर अंदेशा होगा कि इस बजट से किसानों को क्या फायदा होगा। मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन

करता हूं। हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में हिमालच प्रदेश और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय कुटलैहड़।

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज इस चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट अनुमान वर्ष 2026-27 की सामान्य चर्चा पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं आज हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट वित्तीय संकट, आर्थिक कुप्रबंधन और अंधकारमय भविष्य का प्रशस्ति पत्र है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1615/बी.एस./ एच.के.-1

डॉ0 जनक राज जारी...

सभापति महोदय, मैं एक बात कहूंगा-

बोली मीठी है सरकार की, भीतर कड़वा जाल,
जनता पूछे आज यह, कहां गया खुशहाल।
सत्ता में जो बैठे हैं, गाते अपने गीत,
जन-जन रोवे हाल पर, किससे कहे वह अपनी पीर।

सभापति महोदय, हमने राज्यपाल जी के भाषण की चर्चा में भी कहा था कि यह सरकार जनजातीय लोगों की अनदेखी कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकार के जनजातीय मंत्री बहुत तेज-तर्रार हैं। सरकार के पक्ष के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र को तो छोड़ो लेकिन इस बजट ने तो जनजातीय मंत्री को अपने चुनाव क्षेत्र में जाने लायक भी नहीं छोड़ा है। इसमें ट्राइबल क्षेत्र के लिए एक भी ठोस योजना नहीं है। एक "पहल योजना" का जिक्र है। मैं उस पर कैसे विश्वास करूं। क्योंकि पिछले बजट में जो कहा गया था जब वह ही पूरा नहीं हुआ तो इस बजट में जो कहा गया उस पर मैं कैसे विश्वास करूं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं गद्दी समुदाय से आता हूं। क्या गद्दी

समुदाय केवल भेड़-बकरी पालन तक सीमित है? आज गद्दी समुदाय के लोग देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपने हिमाचल और अपने समुदाय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में गद्दी समुदाय के लिए केवल एक पहल योजना का नाम देकर एक तरह से लॉलीपॉप दिया गया है। जब वह वास्तविकता में उतरेगा, तब की बात तब देखी जाएगी।

सभापति महोदय, अब मैं इस बजट के एनालिसिस पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। वर्ष 2026-27 की नेट रिसीट 40,379 करोड़ रुपया की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 16 प्रतिशत कम है। इसका मतलब यह है कि हिमाचल और गरीब होगा और यह बजट अनुमान में जो आपने दर्शाया है। यह आपके पिछले बजट के आकलन के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर 12 प्रतिशत अधिक खर्च किया है और कैपिटल आउटले के लिए इस बार

390 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 70 प्रतिशत कम है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हिमाचल में विकास रुक जाएगा। जो सड़क टूटी है, वह टूटी रहेगी। जो बिजली का पोल टेढ़ा है, वह टेढ़ा रहेगा। जो असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, लोग उन्हीं में जीने को मजबूर होंगे। आपने सैलरी के लिए पिछले वर्ष 16,635 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। लेकिन रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर 42,170 करोड़ रुपये हो गया जो लगभग 153 प्रतिशत अधिक है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनके आकलन इतने गलत हैं। 5-10 प्रतिशत का अंतर समझ में आता है, लेकिन 153 प्रतिशत का अंतर और अभी कहा गया कि हिमाचल ग्रामीण प्रदेश है। लेकिन इस बार आपने ग्रामीण विकास के लिए बजट कम कर दिया और बार-बार कहा जाता है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा। जबकि बजट में ही लिखा है कि 48 प्रतिशत रेवेन्यू हिमाचल अपने संसाधनों से जुटाएगा और 52 प्रतिशत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आएगा।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की स्थिति बताना चाहता हूं। मेरे वहां एक सी0एच0सी0 चुड़ी है। जिसका भवन जर्जर हो चुका है। वहां केवल एक चिकित्सक है और कई वर्षों से दंत चिकित्सक का पद खाली हैं। सी0एच0सी0 होली में डॉक्टरों के अधिकतर

पद खाली हैं। स्टाफ नर्स के पद खाली हैं। सी0एच0सी0 भरमौर में डॉक्टरों के 10 पद खाली हैं। पांगी में इससे भी बद्दतर हालात है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1620/DT/YK-1

डॉ0 जनक राज जारी..

पी0एच0सी0 जगत मांदा में स्टॉफ की कमी है। हालात यह है कि गर्भवति महिलाओं या बीमार व्यक्तियों को एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है या 150 किलोमीटर दूर कुल्लू, मंडी या नेरचोक जाना पड़ता है। भरमौर में परिस्थितियां यह हैं कि महिलाओं और बीमार लोगों को एक अल्ट्रसाउंड करवाने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का ट्रेवल करना पड़ता है।

सभापति महोदय, कुछ बातें मैं पिछले बजट के बारे में भी करना चाहुंगा क्योंकि जो इस बजट में कहा गया है वह पूरा होगा या नहीं होगा वे बातें तब मैं मानूंगा जब पिछले बजट की कुछ बातें जो कही गई थी उनके बारे में सरकार से पूछ लूं।

इस बजट में मत्स्य पालन को केवल देहरा और नदौन तक सीमित कर दिया। क्या मछलियां पकड़ने के लिए पूरा हिमाचल अब देहरा या नदौन जायेगा? क्या प्रदेश के अन्य भागों के लोग मत्स्य पालन नहीं करते? जनजातिय लोगों को आपने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना का कोई लाभ नहीं दिया। मेरे विधान सभा के लोग भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपने उनसे राजीव गांधी का नाम छुपा कर रखा है? वहां पर भी किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ दें। मैं सरकार और सरकार के सभी प्रतिनिधियों से पूछुंगा कि इन तीन वर्ष और तीन माह के कार्यकाल में आपने कितनी डी0पी0आर्ज0, कितने प्रोजैक्टस केंद्र सरकार के पास भेजे जो स्वीकृत नहीं हुए? आरोप लगाना तो बहुत आसान है, सदन में बैठकर चर्चा करना बहुत आसान है, परंतु हिमाचल के हित में कितने प्रोजैक्टस प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गये? मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर दें तो वे इस बात की जानकारी भी सदन को दें या उसका उल्लेख जरूर करें।

सभापति महोदय, पिछले बजट में प्वाइंट नम्बर 21 पर लिखा है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश ग्रीन स्टेट होगा। अभी 31 मार्च के लिए सात दिन हैं हो सकता है कि इन सात दिनों में काया-पलट हो जाए। प्वाइंट नम्बर 31 में कहा था कि भेड़ पालकों के माइग्रेटरी रूट्स को जी0पी0एस0 से टेग किया जायेगा, जो इस बात की बजट बुक में भी कहा गया है। जब मैंने इन बजट बुक्स को पढ़ा तो मुझे काफी कुछ चीजे ऐसी लगी जो पिछली बार के बजट से ही कट-कॉपी एंड पेस्ट की गई हैं। जो पिछली बार कहा गया था वही इस बार भी कहा गया है। वूल फेडरेशन के लिए 50 लाख रुपये

24.03.2026/1620/DT/YK-2

देने की घोषणा की गई थी। मैं चाहूंगा कि जब बजट में हो रही चर्चा का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी दें तो इस बात का उल्लेख भी जरूर करें। प्वाइंट नम्बर 64 में कहा गया था कि निवेशकों को बुलाया जायेगा और प्रदेश में थ्री-स्टार, फोर-स्टार होटल्ज खोले जाएंगे। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि कितने निवेशक आए? बल्कि जितने निवेशक हिमाचल में थे वे भी यहां से भागने लग गये। फिर कहा गया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम प्रथम चरण में चिंतपूर्णी और दियोटसिद्ध शक्ति पीठों के परिसरों का सौंदर्यकरण करेंगे। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर सरकार ने अपना पहला चरण पूरा कर लिया है तो दूसरे चरण में भरमौर के चौरासी मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर और ब्रिजेश्वरी मंदिर के परिसरों में सुधार करने का जो वायदा आपने किया था उसे पूरा करने का कार्य करें।

सभापति महोदय, हमने अनेकों बार व अनेक बैठकों में मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में डालने के लिए आग्रह किया। अभी चार महिने बाद मणिमहेश की यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। पिछले वर्ष के अनुभवों से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा क्योंकि इस बार भी सरकार ने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है और न ही इसके संबंध में कोई उल्लेख इस बजट में किया गया है। मैंने पहले भी कहा कि मणिमहेश हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है जो शार्ट डयूरेशन में चलती है। उस यात्रा के लिए बजट बुक में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं सरकार और सरकार के अन्य प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं कि वे सभी चौरासी मंदिर आएं, वहां पर दर्शन करें-भोले नाथ का अशीर्वाद लें और नवाला में लगा दूंगा।

सभापति महोदय, यहां बार-बार एक बात कही जाती थी कि Article 275 Constitution of India and Revenue Deficit Grant. मुझे लगता है कि इन लोगों ने इसे

गलत तरीके से पढ़ लिया है। क्योंकि जो आर्टिकल 275 है उसमें विशेष तौर पर-उसकी दो लाइनें में पढ़ना चाहूंगा "The State with the approval of the Government of India for the purpose of promoting the welfare of the Scheduled Tribes in that State or raising the level of administration of the Scheduled Areas therein to that of the administration of the rest of the areas of that State." क्या यह संतुलन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है? मैं प्रत्येक बैठक में कहता आया हूं कि अधिकारियों के पद खाली हैं। ये विकास की बातें कर रहे हैं, किसानों के सुविधा की बातें कर रहे हैं, परंतु लोग अपनी समस्याओं को लेकर या सरकार की किसी योजना का लाभ लेने के लिए जाएं तो जाएं किसके पास?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.03.2026/1625/ए.जी.-एन.जी./1

डॉ0 जनक राज..... जारी

क्या वे कुर्सी-टेबल के पास जाएं?

सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि किसी भी सरकार की—चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकारें हों, चाहे केंद्र की हों या किसी भी राज्य की सरकार हो— जब भी सरकार कोई अव्यावहारिक चुनावी लोक-लुभावनी घोषणाएं करती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान हम जैसे पिछड़े चुनाव क्षेत्रों के लोगों को उठाना पड़ता है। उसमें चाहे भरमौर है, चाहे पांगी है, चाहे किन्नौर है या चाहे लाहौल-स्पीति हो, क्योंकि विकास के लिए पैसा नहीं बचता है। कैपिटल आउटले के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं बचता, जोकि आज हमारे साथ हो रहा है। जो परिस्थितियां स्वास्थ्य विभाग में आज हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज हिमाचल का एक गरीब आदमी अपना जेवर, घर व अपनी जमीन गिरवी रखकर इलाज करवा रहा है। आप परिस्थितियां पता करें कि पिछले डेढ़ साल से आई0जी0एम0सी0 शिमला में कार्डियक सर्जरी बंद है। कभी किसी ने पूछा कि यह क्यों बंद है? मैं इस माननीय सदन के माध्यम से अपने चुनाव क्षेत्र के एलमी, क्लौंस, गिरड़, ग्रोंडी, कैला, ज्योटी, धार, गरोड़ा की ग्वार,

कुंडी, अंदरौंद, पियूरा, मंढ़ारा, समोट, सिरना, दाड़वीं, लकड़ा, कीड़ा, रामबो, कुलाल और चस्क-बटोरी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको सड़क की सुविधा नहीं मिलने वाली है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा है। सरकार बजट में खुद स्वीकार कर रही है कि जितना हमारे पास पैसा है या जितना हम पैसा कर्ज से और अन्य संसाधनों से जुटा रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा हमें अपना कर्ज चुकाने के लिए चाहिए।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य का यह हाल है कि बड़ी-बड़ी मशीनें खरीदने पर जोर दिया जा रहा है लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अस्पतालों की भीड़ कैसे कम हो, मरीजों की प्रतीक्षा सूची कैसे कम हो, मरीजों को सम्मानजनक तरीके से और निजता के अधिकार का हनन हुए बिना इलाज कैसे मिले, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार रोबोटिक सर्जरी की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश में

24.03.2026/1625/ए.जी.-एन.जी./2

रोबोटिक सर्जरी की बार-बार व हर सत्र और हर जगह चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, पेशे से चिकित्सक होने के कारण मुझे इस विषय पर अधिक जानकारी है। एम्स दिल्ली, जोकि देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, जिसका वार्षिक बजट लगभग 5500 करोड़ रुपये है, इतना बजट तो पूरे राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भी नहीं है और इस बार प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट 2,861 करोड़ रुपये है। हमारे राज्य के स्वास्थ्य बजट से लगभग दो गुना बजट एम्स दिल्ली का है। एम्स दिल्ली ने भी नवंबर-2024 में एक रोबोट खरीदा था और वह भी ट्रेनिंग के उद्देश्य से खरीदा था। यहां पर बात की जा रही है कि हम जिला स्तर तक रोबोटिक सर्जरी को लेकर जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है, यह सब जानते हैं। इसके बाद मैं पी0जी0आई0 चंडीगढ़ की बात करूंगा। वहां पर कुछ माह पहले ही यूरोलॉजी सर्जरी के लिए एक रोबोट लिया गया है और पी0जी0आई0 ने एक नीति बनाई कि हम "मेक इन इंडिया" का उत्पाद लेंगे। सरकार कोई भी हो, किसी भी विचारधारा की हो परंतु कोई भी सरकार भारत के संविधान से ऊपर नहीं

है। जब तक हम "मेक इन इंडिया" यानी के भारत की आत्मा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यहां पर बार-बार "जय हिंद" कहने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हमारी कथनी और करनी में क्या अंतर है, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि :-

कागज ऊपर राज है, नीचे सूखा गांव।
कागज ऊपर राज है, नीचे सूखा गांव।
कबीर कहें सरकार से — कहां गया वो ठांओ?

आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के जाल में फंस गया है। यहां पर विकास के लिए कोई पैसा नहीं है और विकास से तो सरकार को इतनी नफरत हो गई है कि "विकास" नाम के लोगों को भी धक्के लगाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकार को धक्का दे

24.03.2026/1625/ए.जी.-एन.जी./3

दिया गया था। आज सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है और यह बात मैंने पहले भी कही है कि हमारी आमदनी से ज्यादा पैसा हमें कर्ज के मूलधन और ब्याज चुकाने में लगेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी हालत में कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे विकास होगा, कैसे अस्पताल सुधरेंगे और स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? मेरे से पूर्व के एक वक्ता ने कल कहा और इस तरफ ध्यान गया तो मुझे बात याद आई कि कोरोना काल में डॉक्टर्स मरीजों को ऐसे फेंकेते थे, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर आज हम लोग जिंदा हैं तो उन्हीं डॉक्टर्स की वजह से जिंदा हैं। डॉक्टर्स के प्रति

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1630/ए0जी0/ए0पी0/-01

डॉ0 जनक राज जारी .....

ऐसी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड में संशोधन कर लिया जाए। सभापति महोदय, आज की परिस्थितियों में हिमाचल सरकार के पास दो रास्ते हैं। पहला आर्थिक अनुशासन और दूसरा राजनीति। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल सरकार ने ऐसे संकट के समय में भी राजनीति को चुना और हिमाचल के भविष्य को अंधकार में धकेलने का प्रयास किया। इतिहास के कंधों पर सवार होकर आप हिमाचल के उज्जवल भविष्य, युवाओं के उज्जवल भविष्य की चिता जो जला रहे हैं, उसके लिए हिमाचल आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगा। तीन वर्षों से अधिक समय से युवा नौकरी के इंतज़ार में आयु सीमा को पार कर रहे हैं। एक अन्य चीज़ मुझे इस बजट में नई पढ़ने को मिली वह है अतिगरीब। मैं सरकार से विशेष तौर पर, जब सरकार जवाब देगी, मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये अतिगरीब की परिभाषा क्या है? क्या सरकार ने गरीब और अतिगरीब में कोई मानदंड तय किए हैं? अगर वो तय किए हैं तो वो सार्वजनिक किए जाएं। क्या वहां पर गरीबों में भी पिक एंड चूज़ किया जाएगा, सरकार अपने जवाब में इसे स्पष्ट करे। सभापति महोदय, एक यहां पर बात हुई कि सेलरी को काट दिया जाएगा। किसी की सेलरी का 30 प्रतिशत तो किसी की सेलरी का 50 प्रतिशत काटा जायेगा। बहुत वाह-वाही हुई, कई लोगों ने धन्यवाद किया, कई लोगों ने बड़ा अच्छा-अच्छा बोला। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि दिनांक 28 फरवरी, 2021 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में गाइडलाइन आ चुकी हैं कि "Supreme Court reiterates salaries & pensions are rightful entitlements of government employees; appropriate interest must be paid for delayed payment" यहां पर मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि सेलरी को रोका नहीं है, काटा नहीं है, थोड़ी देर के लिए डिले किया है। मैं यह भी पूछना चाहूंगा क्योंकि सारे लोग इतने अमीर नहीं हैं। कर्मचारियों को इंतज़ार रहता है कि छह महीने बाद मेरा डी0ए0 बढ़ेगा। किसी ने लोन की किस्तें देनी हैं, किसी ने बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी है। छह महीने बाद जब सरकार कर्मचारियों के पैसे को पे करेगी तो क्या इस पैसे को इंटरेस्ट के

24.03.2026/1630/ए0जी0/ए0पी0/-02

साथ पे करेगी, मैं यह पूछना चाहूंगा। क्यों आपकी ऐसी लोक-लुभावनी, अव्यावहारिक चुनावी घोषणाओं का कर्ज हिमाचल के कर्मचारी और अधिकारी उठाएं? क्या आपने जो

घोषणाएं की थीं इनके लिए हिमाचल के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहमति ली थी? यह तो बहुत आसान होता है कि इनकी सैलरी काट दो, उनकी सैलरी काट दो। उनका घर कैसे चलता है गरीब लोगों को कैसे दिक्कत हो रही है, उन सब बातों पर आपने चिंता नहीं की। सभापति महोदय,रहिमन कहत मुख्य मंत्री से :

सुन लीजो सरकार, बिना ज़मीनी काम के झूठे सब प्रचार।

बातें तो बहुत सारी हैं। एक बहुत बड़ा बजट यहां पर पेश किया गया है जिसमें बार-बार कहा गया कि इतने पेज का है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक बात ने मुझे बड़ा अचम्भित किया कि हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि हिमाचल के लोग अमीर हो रहे हैं।

Chairman: Please wind-up.

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, लेकिन हिमाचल गरीब होता जा रहा है। मैं इसका कारण जानना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आखिरी पृष्ठ पर आ रहा हूं। रहीम जी कहते हैं-

अपनी पहुँच विचारी के, कर्तव्य करिए दौर;

देते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर।

आपने इस चादर से अपने मित्रों को तो ढक लिया और पूरे हिमाचल को इस चादर से बाहर कर दिया। सभापति महोदय, एक कहावत है जो हमारे हिमाचल में कही जाती है "पल्ले नी धेला, तां चढ़ना रेला। इसका मतलब है कि पैसे हैं नहीं हमारे पास, फिर हम बात कर रहे हैं कि हम यह भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे। सभापति महोदय, जब जेब खाली हो तो अपनी घोषणाओं का बोझ जनता पर नहीं लादना चाहिए। पहले व्यवस्था संभालें फिर हम विकास की बात करें। सत्ता पक्ष की ओर से जो यह बजट का समर्थन करने के भाषण दिए जा रहे हैं यह बजट का समर्थन

24.03.2026/1630/ए0जी0/ए0पी0/-03

नहीं है, यह इनकी राजनीतिक विवशता है और जो तालियां बजा रहे हैं, यह इनकी वफादारी की तालियां हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर सत्ता पक्ष को आप यह अनुमति दें, इनको बोलने की आज़ादी दें, तो इस बजट की खामियां सबसे पहले यही लोग गिनाने वाले हैं।

Chairman: Please wind-up.

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, परन्तु इनको तो समर्थन करना है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1635/AT/AS/01

डॉ0 जनक राज जारी...

इनको तो समर्थन करना है, क्योंकि अगर आज भी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में इतिहास लिखेगा कि आपने अपनी सत्ता के प्रति वफादारी साबित करने के लिए हिमाचल के भविष्य को (***) दिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

24.03.2026/1635/AT/AS/02

सभापतिः अब इस चर्चा में भाग लेंगे सुरेश कुमार जी।

श्री सुरेश कुमारः सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गत 21 मार्च को इस प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। मैं मानता हूं कि यह प्रदेश का पहला बजट है जो ऐसी परिस्थितियों में पेश किया गया है जब हिमाचल प्रदेश एक वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। आज हिमाचल

प्रदेश कई मुश्किलों का सामना कर रहा है चाहे आरडीजी कट की बात हो, लोन की कैपिंग की बात हो, केंद्रीय ग्रांट्स के बंद होने की बात हो, या वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध के प्रभावों की बात हो। ऐसे समय में इस तरह का बेहतर और लोक-भावना वाला बजट पेश करना माननीय मुख्य मंत्री जी की कार्यकुशलता और कार्यशैली को दर्शाता है।

सभापति महोदय, इस बजट की खूबसूरती इस बात में है कि इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है और इस बजट में भी आपको व्यवस्था परिवर्तन के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।

सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जी का बजट पर भाषण हमने सुना। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जब माननीय मुख्य मंत्री जी बजट पढ़ने आते थे तो ऑटो से आते थे, लेकिन इस बार वह इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए। यह भी व्यवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण है और यह दर्शाता है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है।

इस बजट में दूसरा बदलाव यह देखने को मिला कि इस बार 54,928 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत हुआ। यह पहली बार हुआ कि बजट बढ़ने के बजाय कम हुआ। पिछली बार यह 58,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार लगभग 3,500 करोड़ रुपए की कटौती की गई। इसके कारणों को प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने साहस दिखाते हुए आंकड़ों को छिपाने के बजाय प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जनता के सामने रखा। यह भी इस बजट के अंदर देखने को मिली।

24.03.2026/1635/AT/AS/03

तीसरी बात, सभापति महोदय, जब मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय एक शब्द आया कि हमें अपराधी कहा गया। बजट के शब्दों को किसी भी सूरत में हटाया नहीं जाता क्योंकि

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1640/केएस/एएस/1

श्री सुरेश कुमारी जारी ---

यह एक संवैधानिक डॉक्युमैंट होता है। हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं था कि अपराधी कौन है। उसमें मात्र यह कहा गया था कि जो इस आर0डी0जी0 के विरोध में हैं, वे हिमाचल प्रदेश के अपराधी हैं लेकिन कहावत है कि चोर की दाड़ी में तिनका, अपोजीशन की तरफ से हो-हल्ला हुआ। सभापति महोदय, इतिहास में यह भी पहली बार देखने को मिला और मैं सदन के माध्यम से निंदा करना चाहता हूं कि पहली बार विपक्ष की तरफ से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए टिप्पणियां की गईं और चोर तथा भ्रष्टाचारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं हद तो इन्होंने उस वक्त पार की जब वे अध्यक्ष महोदय, के आसन के सामने खड़े हो कर उंगली दिखाते हुए अध्यक्ष महोदय को इशारा करने लगे। क्या वह संवैधानिक था, क्या वह मर्यादाओं के अनुरूप था या क्या विपक्ष से ऐसी मर्यादाएं अपेक्षित थीं? आज ये सारी बातें इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता देख रही है।

सभापति महोदय, ये अपराधी नहीं लेकिन अपराधबोध से अवश्य ग्रस्त हैं। इनको पता है कि हमने अन्याय किया है। इन्होंने आर0डी0जी0 का विरोध किया। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर जब हमने आर्थिक पैकेज के लिए यहां पर विशेष सत्र बुलाया था, इन्होंने उस वक्त भी वॉकआउट किया। ये तरह-तरह से हिमाचल प्रदेश के हितों को रोकने की बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। सभापति महोदय, आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि विपक्ष के नेता आदरणीय जय राम ठाकुर जी यहां पर नहीं हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि आज वे माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने दिल्ली गए हैं और इससे पहले भी वे केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली गए थे। हम जानना चाहते हैं कि क्या विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ जो उन्होंने 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, उसके बारे में वहां बात की? क्या जो हमारी आर0डी0जी0 बंद हुई है, क्या उन्होंने प्रधान मंत्री जी से उसके

बारे में बात की? ये बातें सार्वजनिक होनी चाहिए। ...(व्यवधान) आप लोगों से यही अपेक्षा थी, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कीं। हमारी शंका है कि वे इन बातों को करने के लिए गए भी नहीं थे। हिमाचल प्रदेश की आर0डी0जी0 को रुकवाने और हिमाचल प्रदेश को जो 1500 करोड़ रुपये की

24.03.2026/1640/केएस/एएस/2

घोषणा आदरणीय प्रधान मंत्री ने की थी, उसको रुकवाने के लिए गए थे। अगर वे हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं और हिमाचल प्रदेश के हित की बात उन्होंने वहां रखी है तो विपक्ष के नेता होने के नाते उनको सारी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए और मीडिया में बताना चाहिए। जो पत्र उन्होंने वहां पर दिया है, उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए अन्यथा हिमाचल प्रदेश की जनता यही समझेगी कि वे हिमाचल प्रदेश केहितों को रुकवाने के लिए वहां गए हैं, हिमाचल प्रदेश की ग्रांट को रुकवाने के लिए गए हैं और इस तरीके से वे हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसीलिए हमने कहा था कि वे इस हिमाचल प्रदेश के अपराधी हैं और अपराधबोध से ग्रस्त हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने विपरीत परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश का बजट रखा और उसमें उन तमाम वर्गों को समेटा जो हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं, जो हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की सोचते हैं, जिनसे हिमाचल प्रदेश बनता है। इस बजट का आकार बेशक हमने घटाया लेकिन विकास के आकार को इस बजट के माध्यम से घटने नहीं दिया। आप देखेंगे कि आज जो हमारा बजट है इसमें सबसे पहला कार्य हमारी सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय प्रबन्धन का किया

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

24.03.2026/1645/av/dc/1

श्री सुरेश कुमार--------जारी

और पहली बार पूरे हिमाचल प्रदेश से सहयोग मांगते हुए तथा अपने से शुरुआत करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वेतन में 50 प्रतिशत कटौती की है। इसी तरह से सभी मंत्रियों,

विधायकों, निगमों व बोर्डों के चेयरमैन्ज, प्रशासनिक अधिकारियों, क्लास-i और क्लास-ii ऑफिसर्ज के वेतन में से कटौती की है। परंतु अगर हम दूसरी तरफ क्लास-iii की ओर देखें; जिनकी विपक्ष के साथी दुहाई दे रहे हैं। इस बजट में क्लास-iii और क्लास-iv कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की गई है। अगर हम इससे आगे देखें तो हमारे दिहाड़ीदार मजदूर, आशा वर्कर्ज, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मल्टी टास्क वर्कर्ज, चौकीदार या आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में इस बजट में बढ़ोतरी की गई है। यह इस बजट की खूबसूरती है और यह बजट हमारी सरकार के अच्छे प्रबंधन को दर्शाता है।

सभापति महोदय, 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था' वह शब्द है जिसके तहत ग्राम के गरीब व्यक्ति के हाथ में सीधा पैसा दिया जाता है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेरे विपक्ष के साथी जिस तरह से यहां पर बातें कर रहे हैं उससे यह जाहिर होता है कि उनके लिए दूध, गेहूं या मक्की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो किसान व गरीब व्यक्ति गांवों में रहते हैं और जिनका गुजारा इसी से चलता है उनके लिए यह बहुत बड़ी बात होती है। हमारी सरकार ने गाय के दूध पर 51 रुपये से 61 रुपये प्रति लीटर एम0एस0पी0 किया और भैंस के दूध पर 61 रुपये से 71 रुपये प्रति लीटर किया। इसके अतिरिक्त किसान जो गेहूं उगाता है उसको 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया, मक्की को 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलोग्राम किया तथा जौ को 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया। यहां अभी माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज नहीं बैठे हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह विशेष रूप से किया गया है कि वहां से जो जौ आएगा उसको सरकार 80 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बढ़ोतरी किसान द्वारा उगाई जाने वाली हल्दी के ऊपर की गई है। पिछले वर्ष हल्दी को 90 रुपये प्रति किलोग्राम किया था परंतु अब उसको 150 रुपये प्रति

किलोग्राम कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है और यह किसान के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। इस बार के बजट में अदरक पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम एम0एस0पी0 दी गई है।

यहां पर कल माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल कह रहे थे कि हल्दी तो लगा देंगे परंतु पानी कहां से आएगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसमें पानी देना नहीं पड़ता अपितु उसमें से पानी निकालना पड़ता है और उसके लिए कूहल बनानी पड़ती है। इसलिए आप हल्दी के बारे में इस प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, उसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। इसके अतिरिक्त आपने एक और बात की कि हल्दी को कहां बेचा जाएगा। ...(व्यवधान) यही तो कहा जा रहा है कि सरकार खरीदेगी, आप लाइए। ...(व्यवधान) हल्दी में से पानी निकालना पड़ता है और आप कह रहे थे कि उसकी सिंचाई कैसे करेंगे। इसलिए आपको ये तथ्य जानने चाहिए कि हल्दी को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह बरसात में उगाई जाती है और उसको पानी से बचाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने किसान आयोग गठित करने की बात भी की है तथा यह किसानों के हित में एक और बहुत बड़ी बात की गई है। जिसमें किसानों की बातों को रखा जाएगा तथा उनके हितों के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। यह पहली सरकार है जिसने किसानों के बारे में इतना आगे बढ़कर सोचा है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और बजट में इसका प्रावधान किया गया है।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1650/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री सुरेश कुमार .... जारी

कल कहा जा रहा था कि जितनी कीमत बीड़ी के बंडल की होती है यानी 10 रुपये, उतने में ऊन खरीदी जाती है लेकिन इस बजट को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि इस बार सरकार ने भेड़ की ऊन का क्रय मूल्य 100 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया है।

यदि आप बजट को ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें किसान की बात मिलेगी, भेड़ पालक की बात मिलेगी, पशुपालन की बात मिलेगी लेकिन केवल आलोचना करने और तथ्यहीन तक देने से इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मनरेगा के विषय में आता हूं। मनरेगा वह महत्वकांक्षी योजना है जिसे कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार लेकर आई थी और जिसकी वजह से गांवों में विकास हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आज मनरेगा का नाम बदला गया और नाम बदलने के साथ-साथ इस योजना की मूल भावना को भी बदला गया है। इस योजना को कमजोर करके इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है। अब इसका नया नाम "बी0बी0जी0 राम0 जी0" रखा गया है। इसमें ऐसे शब्द जोड़े गए हैं ताकि किसी तरीके से भगवान राम जी का नाम इसमें शामिल हो जाए और इसके माध्यम से राजनीति की जा रही है। यदि इसके पूरे शब्दों को देखें तो यह 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण' है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के शब्दों का मिश्रण किया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, रोजगार और आजीविका क्या अलग-अलग हैं? रोजगार का अर्थ भी वही है, आजीविका का अर्थ भी वही है। इसलिए यह केवल शब्दों का खेल है। जिसने भी इन शब्दों को बनाया है उसने इसको भगवान राम जी के नाम को शामिल करने के लिए बनाया है। उनका मकसद इस योजना को चलाने का नहीं था। आप कह रहे हैं कि इसमें 125 दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है लेकिन आपने यह भी कहा कि जब फसल का कार्य होगा तब यह योजना नहीं चलेगी।

24.03.2026/1650/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

यदि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अप्रैल से कनक (गेहूं) की कटाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रैल से यह योजना बंद हो जाएगी। इसके बाद थ्रेसिंग होगी, फिर मक्की की बुवाई होगी, फिर गुड़ाई होगी। यह सब कार्य अक्टूबर तक चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अप्रैल से अक्टूबर तक यह योजना बंद रहेगी। इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने बचते हैं जिनमें सर्दी अधिक होती है। ऊपरी क्षेत्रों में

बर्फबारी होती है, लोग बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रकार आपके पास केवल 2-3 महीने ही बचते हैं जिनमें काम हो सकता है। यानी कि आप केवल 2-3 महीने के काम की गारंटी दे रहे हैं। इस तरह से आप मनरेगा को समाप्त करने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने भी सुना होगा कि मुख्य मंत्री जी ने बजट में कहा कि पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया जाएगा। यह कोई नई बात नहीं है। हर सरकार सेस लगाती है और सेस कलेक्शन जनता के हित में किया जाता है। कल माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी भी कह रहे थे कि यदि सेस लगाएंगे तो इससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा । आज केंद्र सरकार भी 27 रुपये तक का टैक्स लगा रही है। यदि आप सच में जनता को राहत देना चाहते हैं तो केंद्र सरकार से कहिए कि वह अपना टैक्स कम करे जिससे तेल की कीमत कम हो जाएगी ।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

24-3-2026/1655/एन0एस0-एच0के0/1

श्री सुरेश कुमार-----जारी

हमारी सरकार ने 5 रुपये सैस लगाने की बात की है और आप उसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सैस को हम विधवाओं व अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए लगा रहे हैं, जो बेसहारा हैं और उन अनाथ बच्चों के लिए लगा रहे हैं जिनके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अगर हम 5 रुपये सैस लगाते हैं तब भी हमारे पेट्रोल व डीजल के रेट पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि पंजाब में पेट्रोल का रेट 98 रुपये है और डीजल का रेट 88 रुपये है। हरियाणा में पेट्रोल का रेट 96 रुपये और डीजल का रेट 88 रुपये है। जम्मू-कश्मीर में पेट्रोल का रेट 97 रुपये और डीजल का 86 रुपये रेट है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 93 रुपये और डीजल का रेट 85 रुपये है। हमारे रेट अभी भी उनसे कम हैं। अगर हम 1 या 2 रुपये सैस लगाएंगे तो लोक-हित में है। अगर विपक्ष इतना हितैषी है कि पेट्रोल व डीजल के रेट कम होने चाहिए तो आपको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए जिन्होंने 27 रुपये सैस लगा रखा है और टैक्स अलग से ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर गौवंश संरक्षण की बात की जा रही थी। हमने बजट में रजिस्टर्ड मंदिरों की कुल आमदनी का 15 प्रतिशत पैसा गौवंश के संरक्षण के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है। हमारी सरकार की यह सोच है क्योंकि आज हम देखते हैं कि देश व प्रदेश में गाय की हालत ठीक नहीं है। उनको खुला छोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। गाय के संरक्षण के लिए मंदिरों के पैसे से 15 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया गया है और आप इसका भी विरोध कर रहे हैं यानी आप गौ माता का भी विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गाय आस्था का केंद्र है और विपक्ष के लिए गाय वोट बटोरने का माध्यम है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट में रोजगार सृजन के लिए कार्य किया गया है। इस बजट में बहुत विस्तृत प्रोग्राम दिया गया है। इस बजट में सीमित संसाधनों के बावजूद हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अगर ढंग से इस बजट को पढ़ेंगे तो यह बजट लोक-हित का बजट है और इसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है।

24-3-2026/1655/एन0एस0-एच0के0/2

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बजट हिमाचल प्रदेश की दिशा को तय करने वाला बजट है और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। धन्यवाद, जय हिंद।

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य को चर्चा के लिए आमंत्रित करूं, अभी लगभग 12 माननीय सदस्यों के सूचियों में नाम हैं। आज के 5.00 बज चुके हैं। अगर 12 माननीय सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे और 10-10 मिनट्स में अपनी बात रखेंगे तो 2 घंटे का समय हो गया।

अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 6.30 बजे तक बढ़ाई जाती है।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपनी बात 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करें। अब श्री सुख राम चौधरी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुख राम चौधरी ------आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1700/RKS/HK-1

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 मार्च, 2026 को इस सरकार का चौथा बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट में लिखा है कि जो हमारी दस गारंटियां हैं, वह हमारा सरकारी दस्तावेज है और हम इन्हें शत-प्रतिशत पूरा करेंगे। अब सरकार को सत्ता में आए हुए लगभग सवा तीन साल हो गए हैं लेकिन इन सवा तीन सालों में कितनी गारंटिया पूरी हुई इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह जो अनुमानित बजट पेश किया गया है इसमें गारंटियों को छोड़कर केवल केंद्र प्रायोजित स्कीमों का ही ज्यादातर उल्लेख किया गया है। जब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ने गई तो उस समय भी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये गारंटियां कैसे पूरी होंगी? उस समय कांग्रेस के नेताओं ने मंदिरों में जाकर अपनी वीडियो वायरल की कि हम फलां देवी की कसम खाते हैं कि हम पहली कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की 28 लाख महिलाओं को मासिक पंद्रह सौ रुपये देंगे। हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। उस समय बहुत-सी गारंटीयां दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के लोग इनके भ्रमजाल में फंस गए और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आज सरकार के सवा तीन साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना चौथा बजट पेश किया है और उनका अगला बजट अंतिम बजट होगा। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा गया है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछले सवा तीन साल में 35,687 महिलाओं को राशि वितरित की गई है। लगभग 28 लाख महिलाओं में से 35,687 महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई है। पिछले बजट में भी यह घोषणा की गई थी कि हम इस राशि को चरणबद्ध तरीके से देंगे। जब प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार सत्ता में थी तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लोगों को लुभाने के लिए कोई लोक-लुभावन घोषणाएं नही की गई थी।

हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 80 साल की उम्र को घटाकर 60 साल किया था और उसके लिए कोई आमदनी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त हमारी सरकार ने 3,90,000 पेंशने लगाई थी। आज इस सरकार को सत्ता में आए हुए सवा तीन साल हो गए हैं और अब हिमाचल प्रदेश

24.03.2026/1700/RKS/HK-2

के बेरोजगार युवा सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने एक साल में कितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं? 15 अगस्त, 2025 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने 32 हज़ार बेरोजगार युवाओं को सरकारी सैक्टर में रोजगार दिया है। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्स आधार पर रखे गए कर्मचारियों का भी उल्लेख किया था। जब मॉनसून सत्र आया तो उसमें एक प्रश्न के जवाब में यह कहा गया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 24 हज़ार युवाओं को रोजगार दिया है। आप 15 अगस्त को 32 हज़ार और मॉनसून सत्र में 24 हज़ार नौकरियां देने की बात कर रहे हैं जो मुख्य मंत्री द्वारा दोनों समय में की गई घोषणाओं का अंतर दर्शाता है। यह बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं बना। आपने कहा कि हम घर-घर जाकर पशुओं की ट्रीटमेंट और X-ray करवाएंगे। अब गांवों में मोबाइल वैन जाएगी और लोगों को पशु औषधालयों में नहीं जाना पड़ेगा लेकिन इस घोषणा का भी अभी तक कुछ नहीं बना। आपने कहा था कि बागवान अपनी फसल का मूल्य स्वयं निर्धारित करेंगे लेकिन इस घोषणा पर भी कुछ नहीं हुआ।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1705/बी.एस./एच.के.-1

श्री सुख राम चौधरी जारी...

बागवान तय करेंगे अपनी फसल का मूल्य। उसका कुछ नहीं बना। इसके अलावा हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह सारी घोषणाएं धरातल पर नहीं हैं। यह धरातल से परे की बातें हैं। समय आने पर हिमाचल प्रदेश के लोग वर्तमान सरकार को आईना दिखाएंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात इस बजट में कही गई है। हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। अधिकतर लोग खेती करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सैकड़ों, हजारों नदियां-नाले हैं। यही नदियां पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जाकर उनकी जमीन की प्यास बुझाती हैं। उनकी जमीन की सिंचाई करती हैं। हिमाचल प्रदेश की उपजाऊ भूमि नीचे बह कर जाती है। हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी सिंचाई की योजनाएं बनी हैं? अगर हम एक योजना बनाते तो हमारे किसानों को इसका कितना लाभ होता। यह कीमती पानी नीचे बह कर जाता है वहां पर उन्होंने स्कीमें बनाई और आज उनकी जमीन की सिंचाई होती है। आज भी हिमाचल प्रदेश के किसानों की 50 प्रतिशत जमीन की सिंचाई नहीं हो रही है। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अगर हम अच्छी फसल लगाना चाहते हैं, उसके लिए महंगा बीज डालते हैं, ट्रैक्टर से बुवाई करते हैं, वह महंगी है और खाद महंगी है तथा गर्मियों के दिनों में हमारे जैसे क्षेत्रों में अगर 15 दिन के अंदर पानी न लगे, तो फसल का पता नहीं चलता कि फसल बीजी है या नहीं बीजी है। सरकार के इस बजट में सिंचाई के लिए एक भी ठोस योजना नहीं है। इतनी बड़ी नदियां और नाले हमारी उपजाऊ जमीन को बहा कर ले जाते हैं। सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे दोगुनी होगी? जब किसानों के लिए कोई ठोस योजना ही नहीं बनेगी तो यह कैसे संभव होगा? कसानों के लिए सिंचाई सबसे बड़ी जरूरत है, योजना बना कर किसानों की जमीन की सिंचाई होनी चाहिए। लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

इसी तरह हम परोपर तरीके से खनन के क्षेत्र में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा को देखिए। हमारे साथ लगता प्रदेश है। वहां हमारी सीमा में लगभग 300 के करीब स्टोन क्रशर लगे हैं। उन्होंने एक व्यवस्थित वितरण प्रणाली बनाई है। बरसात में 15 दिन एक क्षेत्र में पानी छोड़ते हैं, 15 दिन दूसरे में और 15 दिन तीसरे में छोड़ते हैं और

24.03.2025/1705/बी.एस./एच.के.-2

हरियाणा सरकार को कम से कम 200-250 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है और हमारे यहां क्या स्थिति है? जो व्यक्ति परमिशन लेकर भी खनन करता है उस पर भी शक किया जाता है। हमारी नीति और हमारी सोच ऐसी बन गई है। लेकिन हम सही तरीके से खनन करें तो हिमाचल प्रदेश की आय में इस सेक्टर से बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन हमारी सोच ही नहीं है। हमने एकदूसरे पर दोषारोपण ही करना है। आज गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के लिए अपनी जमीन से मिट्टी लाना चाहते हैं तब भी 25-25 हजार रुपये के चालान होते हैं। सड़क पर आए नहीं कि चालान हो गया। हर दिन पुलिस के जवान खड़े रहेंगे। खनन के अधकारी खड़े रहेंगे। आपने लोक निर्माण के एक्सियन को पावर दे रखी है, जल शक्ति के एक्सियन को पावर दे रखी है। इसके अलावा फोरेस्ट वालों को पावर दे रखी है। इसलिए हिमाचल प्रदेश का आम व्यक्ति दुःखी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के हित में योजनाएं बननी चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को उसका लाभ मिल सके।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मेरा दिनांक 18.03.2026 को एक प्रश्न संख्याः 3901 लगा था। मैंने आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी से पूछा और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जल शक्ति विभाग द्वारा

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1710/DT/YK-1

श्री सुख राम चौधरी जारी...

पावंटा साहिब में हिमकैड के अंतर्गत पाँच योजनाओं के तहत सात इंच के बोर वाले 160 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 133 सिंचाई के ट्यूबवेल स्थापित किए जा चुके हैं। यह भी कहा गया कि ट्यूबवेल में बजट के अभाव के कारण पंपिंग मशीनें स्थापित नहीं की जा सकती तथा ट्यूबवेल यथास्थिति में हैं, वे कार्यशील नहीं हैं।

(सभापति श्री संजय रत्न जी पदासीन हुए)

सभापति महोदय सरकार बने हुए सवा तीन साल का समय हो गया है। सरकार कहती आई है कि हमनें प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है। ये जो सात इंच के बोर वाले ट्यूबवेल लगेंगे उसके उपयोग के उपरांत जो बिजली का बिल उसकी अदायगी किसान को करनी है। यदि आने वाले समय में मोटर खराब हो जाती है, तो उसकी मरम्मत भी किसान ने ही करवानी है, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगी? मैं इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि जहां पर विपक्ष के विधायक हैं, उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। सरकार को बने सवा तीन साल हो गये हैं लेकिन इन 133 ट्यूबवेलों में आज तक मोटर नहीं डाली गई। मैंने कई बार मंत्री जी को कहा कि आप हमारी नई स्कीम्ज के लिए फंड न दो पर इन्हें तो कंपलीट कर दो। ऐसे तो जो ट्यूबवेल किसी स्कीम के अंतर्गत लगें हैं वे तो कल को बंद हो जाएंगे। अगर वे इस प्रकार धन के अभावा से बंद हो जाएंगे तो इनको लगाने का क्या फायदा हुआ जबकि इन ट्यूबवेल्स के लिए हिमकैड से इतने पैसे खर्च किए जा चुके हैं। परंतु अभी तक भी सरकार के द्वारा ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की गई। अभी भी ठेकेदारों की दो करोड़ चार लाख रुपये की पेमेंट पेंडिंग है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष का विधायक है इसलिए वहां पर विकास का कोई काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिस विधान सभा क्षेत्र के लिए केवल दो-तीन करोड़ का इंतजाम सरकार सवा तीन साल में नहीं कर पाई तो उस क्षेत्र का क्या

24.03.2026/1710/DT/YK-2

होगा? मैं इस सदन में यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार की वचन बद्धता भी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बरसात में बहुत अधिक नुकसान हुआ। माननीय जल शक्ति मंत्री जी पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र में आए थे और मैं तो चाहता था कि वे इस क्षेत्र को देखकर आएं। वहां जाने के लिए केवल पांच ममनट ही लगने थे। मैं यह बात इस लिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर सैकड़ों बीघे जमीन बह गई। वहाँ पर बहुत से लोगों के घर बह गए। परंतु प्लानिंग की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि इसकी चैनलाइजेशन के लिए हम जरूर पैसे देंगे। इसके लिए मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से ही बात की और आदरणीय उप-मुख्यमंत्री जी से भी बात की। अगस्त महीने में यह हादसा हुआ था और आज सात महीने हो गए हैं। पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे

हैं कि कब पैसा स्वीकृत होगा, कब वहां का चैनलाइजेशन होगा- ताकि लोगों अगली बरसात में तो चैन से रह सकें। नहीं तो फिर से बाढ़ आयेगी और सैकड़ों घर नीचे गिरेंगे, सैकड़ों बीघे जमीन का नुकसान होगा। मैंने प्लानिंग की बैठक में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी, अभी तो आप पैसे नहीं देंगे, लेकिन जब लोगों का नुकसान होगा, परंतु मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन अगर हादसा हो गया तो फिर पीड़ितों की खबर लेने आप बाई एयर जाएंगे। उनको मुआवजा देने की बात करेंगे। यह कैसी असंवेदनशील सरकार है। एक पैसा भी आज तक वहाँ के लिए सरकार ने जारी नहीं किया। सिंचाई की हमारी इतनी बड़ी स्कीम बह गई, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी नहरें हैं, उनके रखरखाव के लिए आज तक सरकार से कोई पैसा नहीं मिला, उनकी हालत जर्जर हो गई है लेकिन उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

अगर हम बिजली की बात करें, तो बिजली में भी यदि 4100 करोड़ रुपये की आरडीएसएस की स्कीम नहीं होती तो वर्तमान सरकार के पास तो पोल लगाने के लिए, बिजली के मीटर व कंडक्टर लगाने के लिए भी धनराशि नहीं थी। यह प्रदेश सरकार की हालत है लेकिन उस स्कीम के अंतर्गत आज हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है आज फील्ड में जो काम चल रहा है यह उसी से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आज बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं हैं। जिस दिन मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रदेश की जनता पर वाटर सैस लगाया जा रहा था उस दिन मैंने इसी सदन में कहा था कि जिस दिन हिमाचल प्रदेश में वाटर सैस लग जायेगा उस दिन हम आपको

24.03.2026/1710/DT/YK-3

बधाई देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहुंगा कि उस वाटर सैस का क्या हुआ? न तो वाटर सैस लगा क्योंकि कि कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, न ही जो छोटी स्कीम्ज थी जिन स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लोग पॉवर सैक्टर में राशि लगा रहे थे न वे प्रोजैक्ट लगे वे भी यथावत खड़े हैं। क्योंकि सरकार ने कहीं पी0पी0ए0 बढ़ा दिया वे

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.03.2026/1715/ए.जी.-एन.जी./1

श्री सुख राम चौधरी..... जारी

भी लोगों ने नहीं दिया तथा वे भी कोर्ट में चले गए। हिमाचल प्रदेश में तीन साल पहले की स्थिति बनी हुई है यानी कि पावर सेक्टर में यथास्थिति बनी हुई है। यह स्थिति कैसे बनी? यह हमारी गलत नीतियों के कारण बनी है, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। हम चाहते हैं कि अण्डा नहीं खाना लेकिन मुर्गी को मारकर खा लो, यह वर्तमान सरकार की स्थिति है। आज लगभग 3000 करोड़ रुपये की लागत से 100 मेगावॉट का कुहल थर्ड स्टेज पावर हाउस बना है। उसकी स्थिति क्या है? वह 3000 करोड़ रुपये की लागत से 100 मेगावॉट का पावर हाउस बना है। उसका बिजली का रेट 5 रुपये प्रति यूनिट है, ढाई रुपये एम्प्लॉयी की कॉस्ट है, जो फाइनैंस लिया है उसका 1 रुपया इंटरेस्ट है और उसमें 10 प्रतिशत लॉस होते हैं। वहां पर 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ रही है और यदि 9 रुपये प्रति यूनिट बिजली बेचेंगे भी तब भी साल के 180 करोड़ रुपये बनते हैं। जो 3000 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट है, 10 या 12 प्रतिशत, वह भी 360 करोड़ रुपये बनता है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि उनका पैसा इस हैड में जा रहा है। यह बिजली बोर्ड के द्वारा लगाया हुआ प्रोजैक्ट है। ऐसी ही हालत सांवड़ा कुंडू प्रोजैक्ट की है। वहां पर भी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहां पर बिजली महंगी है और उसका भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी बैंक से ग्रांट मिली थी, तब जाकर वह वायबल बना है। इसलिए मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि जब हम कोई नया विचार लेकर आते हैं तो उसके बारे में यहां पर चिंतन होना चाहिए। अगर लुहरी प्रोजैक्ट को बंद करना था, तीन प्रोजैक्टों की बात आपने की है— सैंज, लुहरी और धौलासिद्ध, इस विधान सभा में उन पर चर्चा की जानी चाहिए थी। हमें पता तो लगता कि कितनी कॉस्ट में प्रोजैक्ट तैयार हो रहा है। धौलासिद्ध प्रोजैक्ट 66 मेगावॉट का है

24.03.2026/1715/ए.जी.-एन.जी./2

अगर वह तैयार होगा और उसे कोई भी तैयार करेगा तो कम-से-कम 10 से 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी। तभी तो वह प्रोजैक्ट आज तक बन नहीं पाया। एस0जे0वी0एन0एल0 को इसीलिए प्रोजैक्ट दिया गया था ताकि वह प्रोजैक्ट धरातल पर लग जाए। जो उसकी डी0पी0आर0 बनी है उसके अनुसार उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट आ रही है। दूसरे प्रोजैक्टों की भी हालत ऐसी ही है। इसलिए हम मुख्य मंत्री जी से कहते हैं कि वापिस ले लो और प्रोजैक्ट स्वयं बनाओ तो सही क्योंकि उसकी भी कॉस्ट और इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो प्राइवेट प्रोजैक्ट वाले हैं, वे सारे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उन लोगों ने बैंकों से लोन ले लिया और उनका 50 प्रतिशत प्रोजैक्ट लग गया, उसके बाद पूर्ण नहीं हुआ और बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता रहा, उन पर चक्रवृद्धि ब्याज भी लग गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी भी कुर्की हो जाए, तब भी प्रोजैक्ट नहीं लगेगा।

सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले कम-से-कम उस पर विचार होना चाहिए कि किस तरह से उस पर काम किया जाए। क्योंकि अगर विचार नहीं करेंगे तो इसी तरह योजनाओं की लागत बढ़ेगी और इसी तरह से नुकसान होगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब आप उद्योग मंत्री बने तब आपने बड़े जोर-शोर से जिला सिरमौर में दो घोषणाएं की कि स्तोन में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे और आपने शायद अम्बोया में भी बोला था। इसके लिए मैंने आपका स्वागत भी किया था। मैं उस समय सोच रहा था कि ये इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बनेंगे? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे तो उसके लिए बिजली चाहिए होगी। उस समय बिजली का सिस्टम तो डवलप नहीं था।

24.03.2026/1715/ए.जी.-एन.जी./3

हमारी सरकार ने 33 के0वी0 के 6-7 नए सबस्टेशन बनाए थे और उस समस्या का समाधान किया। मैंने कई बार इस विधान सभा में कहा है कि हमारे 132 के0वी0 के सबस्टेशन गोंदपुर में बहुत अतिरिक्त जमीन है। वहां पर 220 के0वी0 का सबस्टेशन बना दो ताकि आगे हम वहां पर इंडस्ट्री लगा सकें। अभी उसका 124 करोड़ रुपये आए हैं। हमने अपने टाइम में 16 एम0वी0ए0 का नया ट्रांसफॉर्मर लगाकर दिया था। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि गोंदपुर में 220 के0वी0 का सबस्टेशन लगेगा और वहां साथ में ही 132 के0वी0 का सबस्टेशन है। मेरा आग्रह है कि उसके साथ ही एक नया 132 के0वी0 का सबस्टेशन लगा दिया जाए और इसके लिए सी0सी0आई0 राजबन में जमीन भी खाली पड़ी है। अगर वहां लग जाएगा तो हमारे 33 के0वी0 के आठ सबस्टेशन उसमें चल जाएंगे। जिसमें शिलाई, कफोटा, पनोग, सतौन, सी0सी0आई0 राजबन, डी0आर0डी0ए0, पुरूवाला, नघेता आदि शामिल हैं। इसके अलावा 15 सबस्टेशन गोंदपुर में रह जाएंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1720/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री सुख राम चौधरी जारी .....

बिजली के लोड का डिस्ट्रिब्यूशन भी हो जाएगा।

Chairman : Please wind-up.

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, अगर कोई ऐसी बड़ी इंडस्ट्री पांवटा में आ जाए तो हम आज की तारीख में इंडस्ट्री को बिजली का लोड देने की पोजिशन में नहीं हैं। इसलिए इसको जल्दी लगवाया जाए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। परंतु सवा तीन सालों से ये काम नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये काम बहुत जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है नहीं तो ये काम भी लटका रह जाएगा। क्योंकि अभी टेंडर होंगे, उसके बाद तो आपकी सरकार का समय भी पूरा हो जाएगा। आपका सपना पूरा नहीं हो

सकेगा, जो सपना आपने इंडस्ट्री लगाने का देखा था और आपने जिसे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप पांवटा में सड़कों की हालत देखिये कैसी है। उन सड़कों पर आप लोग कई बार जाते हैं। पांवटा में जितनी सड़कों के मैं नाम लूंगा, उसमें लगभग 15 सड़कें ऐसी हैं, जिनका पैच वर्क भी पांच वर्षों तक नहीं हुआ है। इतनी भारी बरसात हुई और 15 अगस्त, 2025 को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी भी पांवटा आये थे और मैं इनके साथ गाड़ी में था और उस दिन मंत्री जी ने अधिकारियों को भी आदेश दिए थे और कहा था कि तीन महीने के अंदर सारा काम कर देंगे।

Chairman: Hon'ble Member, please address to the Chair.

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कम-से-कम जहां विपक्ष के विधायक हैं। हम आपसे कोई नई स्कीम नहीं मांग रहे, आप हमें नई स्कीम मत दो। लेकिन बी0जे0पी0 की सरकार की वह स्कीम जिनका कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो गया, जो तीन सौ स्कीमें हैं, उनमें हमारी स्कीम को भी शामिल कर ले।

Chairman : Please wind-up.

24.03.2026/1720/ए0जी0/ए0पी0/-02

श्री सुख राम चौधरी : माननीय शिक्षा मंत्री जी तीन काम कर दें। साइंस लैब पूर्ववाला का 70 प्रतिशत काम कम्प्लीट है, दो सालों से वहां पर काम बंद है, उस काम को पूरा करवा दो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांवटा का 70 प्रतिशत काम कम्प्लीट है, उसका काम भी दो साल से बंद है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगेता का काम 80 प्रतिशत कम्प्लीट है लेकिन दो साल से वहां पर भी काम बंद पड़ा है। यह मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी को तीन बार लिख कर दे चुका हूं और आपको भी लिख कर दे देंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ये तीन काम तो पूरे कर दो, और हमने जो ये स्कीमें बताई हैं उनको भी पूरा कर दो। आप स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं सोचता हूं यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने लेने वाली बात है। मैं एक उदाहरण देता हूं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा में युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार

द्वारा आठ करोड़ रुपये में हॉकी का स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ बनकर तैयार है। वर्ष 2024 में इसका निर्माण किया गया था। बच्चे उसमें खेलते हैं। वहां पर गर्ल्स होस्टल भी है। वहां पर बिजली का कनेक्शन लगना था। उसमें बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए ढाई-से-तीन साल हो गए। हम बोलते रहे कि यहां पर बिजली का कनेक्शन दे दो। मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख के दिया, आर0डी0एस0एस0 में हिमाचल में 700 ट्रांसफॉर्मर लगाने हैं। एक ट्रांसफॉर्मर वहां भी लगा दो। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तुरन्त लगेगा, 15 दिन के अंदर-अंदर लगेगा। वो पंद्रह दिन पूरे नहीं हुए, धर्मशाला सत्र में भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख के दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि प्रदेश सरकार की नियत ठीक नहीं है, ये लगाना ही नहीं चाहते हैं। दो साल में एक ट्रांसफॉर्मर तक आप नहीं लगा सके और वह एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड उखड़ना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से मैंने कॉरेस्पोंडेंस किया। आपने 8 करोड़ रुपये से इस एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना दिया है तो आप ट्रांसफॉर्मर के पैसे भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे दें जो आपके प्रोजेक्ट का काम करने वाली कार्यकारी सस्थां है। मैंने चिट्ठी लिखी, मैं सदन में कह रहा हूं और उन्होंने पैसे भेज दिये। इस पर मेरा एक प्रश्न भी लगा था मैं अंतिम बात कह रहा हूं।

24.03.2026/1720/ए0जी0/ए0पी0/-03

मैंने विधान सभा सत्र में एस्ट्रोटर्फ माजरा (प्रश्न संख्या-3961) का प्रश्न भी लगया था, मैं आपको बताता हूं कि उसका जवाब क्या आता है? विद्युत कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगाने हेतु कार्यकारी संस्था को भुगतान कर दिया गया है तथा शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन व ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर दिया जाएगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1725/AT/AS/01

श्री सुख राम चौधरी जारी...

मैंने कहा कि आप यह ग्राउंड किसको हैंडओवर कर रहे हैं। मैंने गोमा जी से इसके बारे में बात की। स्कूल को ग्राउंड हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन स्कूल के पास न कोई स्टाफ है और न ही कोई पैसा है। इस ग्राउंड का रख-रखाव कौन करेगा? ग्राउंड खराब होना शुरू हो गया है। यह बहुत कीमती ग्राउंड है। वहां सिर्फ दो कर्मचारी आउटसोर्स पर रख दो, जो बिजली का बिल लगभग 25,000 रुपये महीने आएगा उसका इंतजाम कौन करेगा? ...(व्यवधान)

Chairman : Please wind-up.

श्री सुख राम चौधरी : आप उन चीजों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने बनाकर आपको दे दी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों वहां टूर्नामेंट हुआ। वह हिमाचल प्रदेश का टूर्नामेंट था और मैं उसमें चीफ गेस्ट के रूप में गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो बच्चों ने कहा कि इस ग्राउंड में खेल नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं है। हमने जनरेटर लगाकर मोटर चलाने की कोशिश की और लगभग 35,000 रुपये का जनरेटर का बिल देकर वहां टूर्नामेंट करवाया। यह सरकार की हालत है, यह कहती कुछ है, करती कुछ और बोलती कुछ और अगर आप इतने असंवेदनशील हैं और आप वांगरन स्कीम की रिपेयर नहीं करवा सकते, वहां सिंचाई की स्कीम नहीं चला सकते, वहां पर आप चैनलाइजेशन नहीं करवा सकते और हिमकैड के तहत लगे ट्यूबवेल की मोटरें नहीं डलवा सकते ...(व्यवधान)

Chairman : Please wind-up. Otherwise, it will not be part of the record. ...(Interruption) Hon'ble Member, please wind-up.

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, इस बजट में कुछ भी नहीं है। आपका बजट में आपकी घोषणाएं भी झूठी हैं। बजट के बारे में क्या कहें। मैं तो धरातल की बात कर रहा हूं। सड़कों की हालत खराब है। नाम लेना भी ठीक नहीं लगता। अगर RDSS की स्कीम

24.03.2026/1725/AT/AS/02

नहीं आती, तो आप बिजली के मीटर नहीं लगा सकते थे, पोल नहीं लगा सकते थे और कंडक्टर हिमाचल प्रदेश में मिलता। आपकी सरकार की हालत ही ऐसी है। इसलिए यह बजट एक खोखला बजट है, मुंगेरी लाल के सपनों को साकार करने वाला बजट है। इसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं। सभापति महोद, आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, हम तो आशा यह कर रहे थे कि जब समापन होता है वह बहुत प्रेम से होता है। लेकिन चौधरी साहब ने मेरे विभाग से संबंधित भी कुछ यहां पर विषय रखे। और जैसे चौहान साहब ने कहा कि पावंटा साहिब विधान सभा क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही अटूट संबंध हैं। क्योंकि क्योंकि हमारे दिवंगत नेता ठाकुर राम लाल जी का भी निवास स्थान भी वहां था। जो इन्होंने माजरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात की, जहां पर हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल भी है। और निश्चित रूप और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं वहां गया था। मैं मानता हूं कि वहां रख-रखाव मेंटेनेंस की आवश्यकता है। और उसके उपरांत लगभग 25 लाख रुपये की राशि हमने वहां स्वीकृत भी की और लगभग शिक्षा विभाग के अधीन 9 स्पोर्ट्स हॉस्टल थे, वो अब बढ़कर 11 हो चुकी हैं। जिसमें से एक शिलाई विधान सभा क्षेत्र में भी हमारा स्पोर्ट्स हॉस्टल स्वीकृत हुआ है। हमने लगभग 15 करोड़ रुपये की DPR सभी स्पोर्ट्स हॉस्टलों की बनाई है। जिसको हम प्रदेश सरकार के अपने संसाधनों से बजट आवटंन करने का प्रयास करेंगे, साथ ही केंद्र में भी पैब की मीटिंग में भी इसे ले जाएंगे।

तो निश्चित रूप में यहां पर जो वर्षों से आपके कोचों के पद रिक्त पड़े हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 9 स्पोर्ट्स हॉस्टलों की बात की है, दो इसके अतिरिक्त हमारे शिलाई और चौपाल में खुले हुए हैं। मैं धन्यवादी हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का समस्त कैबिनेट का कि हमारे लगभग 16 कोचों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें माजरा के लिए हॉकी कोच का पद भी शामिल है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी स्पोर्ट्स हॉस्टल आने वाले समय में अपग्रेड हों। इन्होंने अम्बोया स्कूल की भी बात की, जहां हम गए थे। उसी स्कूल के लिए भी मैं चौधरी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि वहां CBSE बोर्ड

24.03.2026/1725/AT/AS/03

लागू किया गया है। चौहान साहब भी वहां पर गए थे। तो निश्चित रूप से पावंटा साहिब विधान क्षेत्र के दो स्कूल आपने बताए कि जिनका 70-80 प्रतिशत कार्य अधूरा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने छोटे भाइयों को भी इन बातों से अवगत कराएं, ताकि हम मिलकर इसमें हर संभव सहयोग दे सकें।

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे श्री हरदीप सिंह बावा जी।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1730/केएस/एएस/1

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा भाग लेंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान पर चर्चा करने के लिए आपने मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे ही बजट की शुरुआत हुई, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो कि हमारे वित्ता मंत्री भी हैं, इसमें कहा गया कि 16वें वित्तायोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा आर0डी0जी0 बंद करने की बात की गई है और आर0डी0जी0 को बंद करना संविधान के अनुच्छेद 275 (1) तथा 280 (3)(बी) की भावना के विपरीत है। यह मुख्य रूप से अंकित किया गया। वर्ष 2026-27 में आर0डी0जी0 ना होने के बावजूद सरकार द्वारा, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट यहां पर पेश किया गया उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बड़ी मज़बूती के साथ और बहुत ही हौसले के साथ उन्होंने यह बजट यहां रखा है। किसान, मज़दूर, कर्मचारी, बागवान आदि हर वर्ग को इसमें कुछ ना कुछ देने का प्रयास मुख्य मंत्री जी ने किया है। आने वाले समय में हम सभी के समक्ष आर0डी0जी0 का जो व्यापक असर रहेगा, मैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं और जो प्राकृतिक नुकसान वर्ष 2023 से 2026 तक हमारे विधान सभा क्षेत्र में हुआ, मैं सोचता था कि आर0डी0जी0 ना होने के कारण हमारे विधान सभा क्षेत्रों में लम्बित पड़े प्रोजैक्ट्स, हमारे क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई हम किस तरीके से करेंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश

में कांग्रेस शासित सरकार है, अतः केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दिया और हम सभी को इस दुविधा में डालने का काम किया। आर0डी0जी0 का जो व्यापक असर है, आने वाले समय में डवलपमेंट प्रोजैक्ट्स किस तरीके से अफैक्ट होंगे, यह तो समय बताएगा क्योंकि सीधे तौर पर यह पैसा हमारे प्रोजैक्ट्स की कम्पलीशन में , जैसे अभी यहां माननीय सदस्य सुख राम जी कह रहे थे, इन्होंने अपने भाषण में इनके विधान सभा क्षेत्र के बहुत से प्रोजैक्ट्स को मैंशन किया जिनका 70-80 परसेंट काम हो गया है और केवल 20 या 30 परसेंट काम पैसे की पूर्ति ना होने की वजह से रुक गया है ऐसे ही कई प्रोजैक्ट्स मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी हैं और आज अगर आर0डी0जी0 मिलती तो इसी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पैसे की पूर्ति के होते उनके काम कम्पलीट हो जाते और उनके उद्घाटन हो जाते तथा जनता को समर्पित हो जाते। मैं फिर भी मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र पंजाब बॉर्डर के साथ

24.03.2026/1730/केएस/एएस/2

लगता क्षेत्र है। आधा इलाका मैदानी है और लगभग 40-45 परसेंट इलाका ही पहाड़ी है। जिस तरीके से किसान के प्रति मुख्य मंत्री जी ने सोच रखी, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नालागढ़ को मिल्क प्रोसैसिंक प्लांट देने की घोषणा की और लगभग 35 करोड़ रुपये की लागत से इस मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट का निर्माण होना है और एक साल के अंदर वह बनकर तैयार होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के पास पशु हैं। 20 हजार लीटर की क्षमता का प्लांट लगने से वे जो अन्य विधान सभा क्षेत्रों में, अन्य जिलों तथा वीटा व अमूल जैसी बड़ी कम्पनीज़ को दूध सप्लाई करने का काम करते हैं, आज उन्हें अपने ही विधान सभा क्षेत्र में दूध के सही दाम मिलेंगे और एक साल में बन कर वह तैयार होगा जिसके लिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एम0एस0पी0 की बात की, जहां हल्दी में 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये, अदरक में लगभग 30 रुपये,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

24.03.2026/1735/av/dc/1

श्री हरदीप सिंह बावा--------जारी

गेहूं पर 60 रुपये से 80 रुपये और मक्का पर 40 रुपये से 50 रुपये करने की बात कही, मैं उसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

यहां पर मुर्गा पालन पांच वर्षों में 62 करोड़ रुपये से Comprehensive Himachal Integrated Commercial Poultry Scheme (CHIC) को लागू करने की बात रखी, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव सनेड़, धबोटा और गांव माजरा में बड़े स्तर पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने पुलिस भर्ती के बारे में भी कहा है क्योंकि जिला सोलन के नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र से लोग बड़ी मात्रा में पुलिस में भर्ती होते रहे हैं। वे चाहे स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से हों क्योंकि हमारे यहां के लोग खेलों में बहुत रुचि रखते हैं। इसके अतिरिक्त एक बटालियन में मुख्य मंत्री ने 1000 कॉंस्टेब्लज की भर्ती करने की घोषणा की है, मैं उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। विपक्ष की विरोध के लिए विरोध करना एक आदत बन गई है और इन्होंने हमेशा ही विरोध करने का काम किया है। इनके द्वारा सरकार की ओर से किए गए सही कार्यों की कभी प्रशंसा नहीं की गई और हरेक पहल पर इन्होंने मुख्य मंत्री जी का मजाक उड़ाने का काम किया है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपने मुख्य मंत्रीत्वकाल में यानी वर्ष 2017 से 2022 तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के केवल दो दौरे किए और वे दो दौरे भी वर्ष 2022 के आखिरी तीन महीनों के दौरान किए गए। उससे पूर्व वर्ष 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उस समय हमारी सरकार ने जो डवलपमैंटल वर्क्स किए या जो-जो योजनाएं लाकर धरातल पर काम किए थे, उनमें से भाजपा की सरकार ने वर्ष 2017 से 2022 तक एक भी काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जिसके मुखिया स्वयं श्री जय राम ठाकुर जी थे। वहां पर 68 सिंचाई की

स्कीम्ज के शिलान्यास हुए परंतु उनमें से इनके पांच वर्षों के कार्यकाल में एक भी स्कीम तैयार होकर लोगों को समर्पित नहीं की गई। वर्ष 2016-17 में 16 वॉटर सप्लाई स्कीम्ज का शिलान्यास हुआ परंतु उनमें से सत्ता

24.03.2026/1735/av/dc/2

परिवर्तन होने के बाद भाजपा की सरकार ने एक भी स्कीम को लोगों को समर्पित नहीं किया। वहां पर दस चैक डैम्ज का शिलान्यास हुआ परंतु भाजपा की सरकार के कार्यकाल में एक भी चैक डैम बनकर तैयार नहीं हुआ। वहां पर हमारी सरकार ने आर0टी0ओ0, तहसील रामशहर और सब-तहसील पंजेरा खोली। वहां पर हमारी सरकार ने जितने भी ऑफिसिज खोले थे उनमें से इनकी भाजपा की सरकार द्वारा एक भी ऑफिस का शिलान्यास नहीं किया गया। हमारी सरकार अपने कार्यकाल में रामशहर कॉलेज के लिए 13 करोड़ रुपये की राशि छोड़कर गई थी परंतु इनके द्वारा पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में उसका टैण्डर तक नहीं करवाया गया। हमारी सरकार ने एक वर्ष में 68 में से लगभग 50 सिंचाई योजनाओं को लोगों को देने का काम किया है। वहां पर अब 16 में से 14 वॉटर सप्लाई स्कीम्ज लोगों को समर्पित की जा चुकी हैं। रामशहर कॉलेज का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। सब-तहसील पंजेरा का कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आर0टी0ओ0 ऑफिस की लगभग 11.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई बिल्डिंग का पिछले दो दिन पूर्व उप-मुख्य मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है और यह बिल्डिंग एक वर्ष में बनकर तैयार हुई है।

सभापति महोदय, विरोध के लिए विरोध करना भाजपा की आदत है।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1740/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री हरदीप सिंह बावा.... जारी

लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस वित्तीय स्थिति में भी जिसे पूरा देश जानता है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर वित्तीय संकट है, लगातार भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं बॉर्डर के विधान सभा क्षेत्र से संबंधित हूं और पंजाब के बॉर्डर में होने से चिट्टे का बहुत ज्यादा व्यापक असर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2026-27 में 12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक फ्लैगशिप पॉलिसी इनिशिएटिव, "खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान" प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से विशेषकर चिट्टे जैसी घातक प्रवृत्ति से दूर कर खेलों के माध्यम से अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक जीवन शैली की ओर अग्रसर करना है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। जहां तक अन्य मसलों की बात है, प्रदेश में मुख्य मंत्री जी लगातार हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और हर विधान सभा क्षेत्र में कुछ-न-कुछ कार्य इस वित्तीय स्थिति में भी किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, पूर्व भाजपा सरकार के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बल्क ड्रग प्लांट खोला गया है। यह बल्क ड्रग प्लांट, ए0पी0आई0 यूनिट (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट) है जो मेरे गांव पलासड़ा, ग्राम पंचायत गोल जमाला में स्थापित किया गया है। पिछले कल इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसे मुझे लीड करना था। इसी कारण से मुझे सदन में पहुंचने में भी देरी हुई। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 25 से 30 गांव सीधे तौर पर इस ए0पी0आई0 यूनिट से प्रभावित हैं। लोग अपने घरों में कैद होकर बैठने को मजबूर हैं। लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हैं। जिस प्रकार का एयर पॉल्यूशन और दुर्गंध इस प्लांट से फैल रही है, वह अत्यंत चिंताजनक है। यह वही प्लांट है जिसका उद्घाटन अगस्त, 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आज यह ए0पी0आई0 यूनिट लोगों

के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों को दमे की बीमारी हो रही है, स्किन कैंसर जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं और चारों ओर दुर्गंध फैल रही है। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हैं। मेरा इस माननीय सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। मैं इस विषय में विक्रम ठाकुर जी से भी बात कर रहा था। मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है लेकिन ये उस समय उद्योग मंत्री थे। जब वह यहां अपने वक्तव्य में बल्क ड्रग पार्क की बात कर रहे थे, तब मैंने उनसे कहा कि आप पार्क की बात कर रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में जो प्लांट लगाया गया है उससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। मुझे यह कहा गया कि आप प्लांट बंद करवा दो। लेकिन हमारा उद्देश्य प्लांट बंद कराना नहीं है बल्कि समस्या का निवारण करना है। जिस प्रकार यह प्लांट स्थापित किया गया, उसे आबादी से 15-20 किलोमीटर दूर होना चाहिए था। आज स्थिति यह है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और लोग प्रदूषित हवा में घुटन महसूस कर रहे हैं। इस विषय में मैंने मुख्य मंत्री जी से भी बात की है और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। खुद भाजपा के स्थानीय नेता भी पिछले कल

एन0एस0 द्वारा .... जारी

24-3-2026/1745/एन0एस0-एच0के0/1

श्री हरदीप सिंह बावा -----जारी

खुद भाजपा के स्थानीय नेता पिछले कल जो प्रोटैस्ट हुआ उसमें वे लोग भी शरीक थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ी मूवमैंट खड़ी हो रही है और यह भारत सरकार और भाजपा की पूर्व सरकार श्री जय राम ठाकुर जी की देन है। आपने 350 बीघे से ज्यादा जमीन एक रुपये मीटर के तौर पर दे दी। आज विपक्ष बताए कि उन्होंने अपने समय में लोगों को घर बनाने के लिए 3 बिस्वे जमीन कितने लोगों को दी है? आपसे उस समय जो लोग बेघर हुए थे उनको 3 बिस्वे जमीन नहीं दी गई । आपने इस उद्योग के लिए 1 रुपये मीटर के हिसाब से 350 बीघे जमीन दे दी। सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय कम है। मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान इस सदन में रखे हैं तो मैं इस बजट की सराहना करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिंद, जय हिमाचल, जय नालागढ़।

सभापति : अब इस चर्चा में डॉ0 हंस राज जी भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट अनुमान दिनांक 21 मार्च, 2026 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वे चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। सबने अपने-अपने तरीके से तकरीरें दी हैं। अब जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको तो इस बजट की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनका दायित्व है। इस बजट में हमने 4,000 करोड़ रुपये का झोल देखा है। रिवर्स गियर में गाड़ियां ज्यादा दिन नहीं चलती हैं और इससे गर्दन भी टेड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि यह इस तरह का बजट पेश हुआ है। हम आर0डी0जी0 पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ...(व्यवधान) गाडिंयों में शीशे तो पहले भी लगे होते थे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और एक तथ्य इसके लिए सही है कि आप कुल्हाड़ी से कपड़े भी धोते हो और दोष भी किसी ओर को देते हो। यह इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जब सत्ता में आए और सत्ता में आने से पहले आपने 10 गारंटियों की चर्चा की थी तो उस पर पूरा उतरना आपका दायित्व था तथा आपने उस संदर्भ में कोशिश भी की लेकिन 'थोथा चना बाजे घना' यहां पर कुछ माननीय सदस्य बातें कर रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि 'An empty vessels make much noise'. Some of the people are saying something here in the

House. मुझे ऐसा लगा कि यह (***) हो रहा है। जिस तरह से हमारे अपने लोगों ने सत्ता में बैठ कर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का नुकसान करना शुरू किया।

सभापति : (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। हम लोग हाउस में डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कोई (***) करने के लिए नहीं बैठे हैं।

डॉ0 हंस राज :...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप इतने शब्द एक्सपंज मत करवाएं। यदि शुद्धता का परिचय देना है तो शुद्ध भाषा का उच्चारण करते हैं। आपको यहां पर कई शब्दों का पता ही नहीं लगेगा और फिर आपको उसके लिए शब्दकोष खोलना पड़ेगा, यदि

आपने यहां पर उस तरह के शब्द चलाने हैं। हम वही शब्द बोल रहे हैं जो हिमाचल के लोगों को समझ आ जाएं। जब मुख्य मंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे तो (***)अब मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता कि (***) है या ग्रंथ है कि क्या है और क्या नहीं है? अब जिसकी चलती उसकी क्या गलती है। ऐसे तो होता ही है। आज की तारीख में इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि तथाकथित कुछ लोगों ने हमारी किस्मत खराब की, दोष सबका नहीं था लेकिन आपके कारण ऐसा हुआ है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। राणा जी ठीक कह रहे थे कि हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सुधारना ही नहीं चाहते। मैं यहां पर कहना चाहता हूं :

वो मुतमइन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता ,
मैं बेकरार हूं आवाज़ में असर दिखाने के लिए।

कुछ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ इस तरह की बात तो होनी चाहिए। एक बार जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी यहां भाषण दे रहे थे और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1750/RKS/HK-1

डॉ0 हंस राज जारी...

हमारी जीने लायक स्थिति उन्होंने ही बनाई है, आपने तो लोगों के पैसे ही काटे। यह सच्चाई है। मैं उनको याद करता हूं। हम उस समय विपक्ष में थे और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं हर बार इधर ही बैठता हूं। चाहे सत्ता में रहूं या विपक्ष मेंलेकिन मैं तीसरी बार भी इधर ही बैठ रहा हूं। कभी उस चेयर मेंकभी इस चेयर में लेकिन रहता यहीं हूं। उस समय जब मैं भाषण दे रहा था तो शायद उस वक्त हमारा मानस इस तरह से डवलप नहीं हुआ था कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने उनको कहा था कि जब परिवार का मुखिया कोई कर्ज लेता है तो उसको आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। मैं कल जब श्री विक्रमादित्य सिंह जी का वह लच्छेदार भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। श्री

विनोद कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि आपने पी0एम0जी0एस0वाई0 की तो बात की लेकिन आपने लोगों को क्या दिया? 'तम्बूरा'। अब पता नहीं यह शब्द सही है कि नहीं लेकिन इस शब्द को भी सेक्रेटरी साहब देख लेंगे। मेरा मानना है कि 'तम्बूरा' कोई गलत शब्द नहीं है। यह हिंदी का बड़ा शुद्ध शब्द है और हमने इस शब्द को बोल दिया है। आपने अलग-अलग जगह कई संस्थान खोल दिए हैं। अब राज्य में इतना भेदभाव होना शुरू हो गया है कि जहां शिक्षा का पोटेंशियल है वहां आप शिक्षा संस्थान नहीं खोल रहे हैं। जहां स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, वहां स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर में कहां क्या हो सकता है, हम उस तरफ बिल्कुल नहीं सोचते। मैं सीधे चम्बा की बात कर रहा हूं। जब मैं बजट पढ़ रहा था तो इसमें चम्बा जिला का जिक्र बहुत कम है। चम्बा जिला का सिर्फ हेलीपोर्ट के रूप में जिक्र हुआ है जोकि भारत सरकार की योजना है। पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पैसे आ रहे हैं इस बजट में उन्हीं चीजों का जिक्र है। आपने जो स्वास्थ्य विभाग में सैलरी की बढ़ोतरी की है, यह सारा पैसा भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में दिया है। मैं इसके आंकड़े नहीं दूंगा क्योंकि इसके आंकड़े आदरणीय जय राम ठाकुर जी पेश कर चुके हैं।मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जिला चम्बा भी इस प्रदेश का अभिन्न अंग है। ये चार ही जिले थे जिन्होंने हिमाचल को अस्तित्व में लाने के लिए स्वर्गीय वाई.एस. परमार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। आज आप यह चर्चा क्यों नहीं करते जब भारत सरकार यह कह ही रही है कि भारत के हर जिले को हमने फोरलेन के साथ जोड़ना है। यह छोटी सी बात है और पठानकोट

24.03.2026/1750/RKS/HK-2

तक तो पहले ही फोरलेन बन गया है। अगर आप 70-75 किलोमीटर और आगे एक्सटेंड करने की डी0पी0आर0 भेजकर उस जिले को भी जोड़ देंगे तो आपको क्या होगा? मैं अभी टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को फोन कर रहा था कि जो पेशेंट चम्बा से रेफर होकर टांडा आया है वह बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। खैर, प्रिंसिपल साहब हमारी बात सुन लेते हैं लेकिन आप यह सोचिए कि चम्बा में मेडिकल कॉलेज होते हुए भी हमारे मरीजों को वहां से हर बार टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर होना पड़ता है। चम्बा के लोगों ने आप लोगों के साथ ऐसा क्या किया है? मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार पर सीधा आरोप

लगाता हूं कि अगर चम्बा क्षेत्र निगलेक्ट हुआ है तो वह हर बार आपकी सरकारों में हुआ है। यह मैं आपके ऊपर सीधा आरोप लगाता हूं। (***)

(श्री आशीष बुटेल, सभापति पदासीन हुए।)

लेकिन मैं (***) यहां पर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करके लगातार चम्बा जिला की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं जब वर्ष 2012 में विधायक बना थातो मैंने अपने चुराह विधान सभा क्षेत्र के स्टूडेंट्स को यह कहा था कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है इसलिए आपको शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा और इसका टर्नआउट 10 सालों में आया है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी कमीशन निकलते हैंचाहे वह सिविल सर्विसेज के हों, चाहे हमारे लेक्चरर लगें, चाहे टी0जी0टी0 लगें, चाहे कोई सब-इंस्पेक्टर लगें, चाहे एक्साइज में लोग जाएं इनमें हमारे लोगों का शेयर 10 या 20 प्रतिशत बढ़ा है। हमारे लोगों ने अब और संघर्ष करना शुरू किया है। आप जितना आइसोलेटिड कर लें लेकिन हमारे लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया है। मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि हमारे लोगों ने और परिश्रम करना शुरू कर दिया है। हमें पता है कि सरकारें तथाकथित व्यक्तियों और तथाकथित क्षेत्रों के लिए बन रही हैं लेकिन हमारी सुध लेने वाले हम खुद ही हैं

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1755/बी.एस./एच.के.-1

डॉ0 हंस राज जारी...

लेकिन हमारी सुध लेने वाला मैं खुद ही हूं। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कितना पोटेंशियल है? भराड़ा का एक व्यक्ति निकला उसने 1994 में मटर का बीज लाया और धीरे-धीरे सारा क्षेत्र मटर की खेती में आगे निकल गए। उससे हमारी आजीविका भी सुधरी।

मुख्य मंत्री जी ने चर्चा तो सभी वर्गों की की। मुझे अच्छा लगा कि आपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हसबेंडरी, मतस्य और हर तबके को छूने की बात कही है। लेकिन आप डेवलपमेंट के लिए केवल 20 प्रतिशत ही पैसा रख रहे हैं। अगर 100 में से 20 रुपये ही विकास के लिए रखे हैं तो क्या हम सही मायने में विकास कर पाएंगे? मैं यहां जल शक्ति मंत्री, उप मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। वे यहां पर अभी नहीं बैठे हैं, दो साल हो गए। मैंने आई0पी0एच0 डिवीजन की बिल्डिंग बनाकर दे दी है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। अब मैं फिर कह रहा हूं। जैसे ही विधान सभा सत्र समाप्त होगा, एक्सियन राजी होगा चाहे नहीं होगा, मैं उसे जनता को समर्पित कर दूंगा। यह सुन कर तो शायद आप ऑनलाइन इसका उद्घान कर देंगे। यह मैं विधान सभा में कह रहा हूं क्योंकि इसे हमने खुद बनाया है। लोक निर्माण की बिल्डिंग हमने बना करके दी। हमारा बस अड्डा 11 करोड़ रुपये से बना है। जितनी बिल्डिंग्ज बननी थी बनी लेकिन बाहर टारिंग और मेटलिंग नहीं सकी। आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने मिनी सचिवालय दिया था। लेकिन अभी तक वहां केवल ग्राउंड बना है, पिलर तक नहीं लगे। यह तो कमाल हो गया। सब जज कोर्ट के लिए हमने जमीन दे दी, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। हमने बिजली बोर्ड का डिवीजन दिया, उसे आपने डिनोटिफाई कर दिया। चम्बा में केवल दो ही डिवीजन हैं। यह हमारे साथ अन्याय है कि आप हमारे हालात बदना ही नहीं चाहते। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकारें आती हैं जाती है परंतु वही व्यक्ति अजर-अमर रहता है जो प्रदेश के लिए कुछ योगदान करता है। हम कुछ करना ही नहीं चाहते।

हमने हाइड्रो पावर में हर बार कहा कि लगभग 31,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। अगर उसका दोहन कर लें तो लगभग 58,000 करोड़ रुपये सालाना आय हो सकती है। लेकिन आप उस दिशा में ध्यान नहीं देते। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में छह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। एक का काम 20-25 प्रतिशत तक हो गया और वह भी बन्दर बांट चली हुई है। इस ठेकेदार को काम दो उसको दो। परंतु जो हमारा दियोथल-चांजू का

प्रोजेक्ट है उसका काम ही शुरू नहीं होता। सही कोठी के बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि आपने ही ऑनलाइन इसका शिलान्यास किया है। उसका काम भी शुरू कीजिए। उसका भी काम नहीं चला है। यह सही कोठी वही है जो बक्का मुला के हम नारे लगाते थे। लेकिन मैं वह जिक्र नहीं कर रहा हूं।

जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक तारा था,
मन में बेहद प्यार था, जो टूट गया, वह टूट गया।
अंबर के आनंद को देखों कितने तारे टूटे, कितने प्यारे छूटे।

लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि चुराह विधान सभा क्षेत्र और पूरा चम्बा virgin destination है। साच पास आपको पूरा साल बर्फ मुहैया करवाता है आप उस साच पास की टनल की बात नहीं करते। सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि बजट बुक आपने बहुत बड़ी बनाई है। बहुत सारे पन्ने हैं, मेरी बेटी छुट्टी आई थी उसने कहा कि यह क्या है मैंने कहा बेटा इसे पढ़ने के लिए 4-4:30 घंटे लगे हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी की मेहनत की सराहना करता हूं। उनकी फिटनेस की भी सराहना करता हूं। लोक खामखाह बीमर बताते हैं। भाभी जी यहां से चले गए, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। कि उन्होंने मुख्य मंत्री जी का पूरा ख्याल रखा हुआ है। लेकिन 14-15 महीने बाद जब सरकार बदलेगी, तब स्थिति साफ हो जाएगी। आप आर0डी0जी0 का रोना बंद करें। भारत सरकार ने पहले ही इस पर विचार किया था कुछ राज्यों ने आपका विरोध करना शुरू कर लिया था। आप फ्री बीज की बात करते हैं। मुफ्त में कभी किसी समाज का भला नहीं हुआ है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में भी यह बात कहता हूं। दिल्ली के मुर्दे दिल्ली में दफन होंगे।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, अन्य माननीय सदस्यों ने 20-20 मिनट बोला है। मुझे तो अभी मात्र 13 मिनट ही हुए हैं। मैं सिर्फ 21:30 मिनट तक बोलूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बस यही निवेदन करना चाहता हूं श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1800/DT/YK-1

डॉ0 हंस राज जारी...

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं। मैं आपका बहुमूल्य समय नहीं लूंगा क्योंकि इस बजट में ऐसा मटेरियल ही नहीं है जिस पर मैं बोलू? मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ दुःख व्यक्त कर रहा हूं। जब कोई नया व्यक्ति प्रदेश का संचालन करता है तो उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल्ज हैं जिन स्कूल्ज में पिछले तीन-चार साल से प्रिंसिपल ही नहीं हैं। यह भी अपने आप में कमाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बेरागढ़-मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस विद्यालय में पिछले तीन साल से प्रिंसिंपल ही नहीं है। ऐसे कई स्कूल्ज मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जिनके भवन पिछली बरसात के कारण डेमेज हो गये थे। हमारी मुख्य सड़क जो चंबा से पांगी की ओर जाती है तीन-चार जगह उसकी हालात बहुत खराब हैं। सरेला-नाला में भी काफी खराब हालात रहे। चांजु नाला में भी हालात खराब हैं। पी0डी0एन0ए0 में जितना भी पैसा आया उस पैसे की बंदर बांट की गई। जिसने चिट दी उसको पेमेंट हो रही है और जिसने चिट नहीं दी उसकी पेमेंट ही नहीं हो रही। कई लोग मुझे व्हॉट्स एप पर मैसेज कर रहे हैं कि जनाब विधान सभा चल रही हैं फलां बंदे को बोलो शायद हमारी भी पेमेंट हो जाए? प्रदेश में यह किस प्रकार की बंदर बांट चली हुई है?...(व्यवधान) श्री संजय अवस्थी जी अगर यह सभी के लिए लागू हो तो फिर तो इसका लाभ है। लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए तो आर0डी0जी0 हर वक्त उपलब्ध है लेकिन आम जन के लिए यह उपलब्ध नहीं है। अगर बजट में यह बात होती कि सरकार ने चुराह विधान सभा क्षेत्र में 2 पी0एच0सी0 बेरागढ़ और कुहाल खत्म की उनको बहाल कर दिया है तो मैं सरकार को बधाई देता। इस बजट में सरकार अगर विकास खंड कोटी जो पूर्व सरकार के समय खोलना गया था, उसको दोबारा रिस्टोर करती तो मैं सरकार को बधाई देता। एक डिग्री कॉलेज पिछली सरकार ने मसरूंड में दिया था अगर उसको बहाल करते तो मैं सरकार को बधाइ देता। मैं सरकार को किस बात की बधाई दूं? मैं सरकार पर सीधा आरोप लगा रहा हूं इसलिए मैं बधाई नहीं दे रहा। मैं बधाई इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि सरकार क्षेत्रवाद के आधार पर राजनीति कर रही है जिसकी (***) इस प्रकार की विडम्बना पहली बार इस सदन में हुई है।(***) इसलिए आप सोचिए कि प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति है।

Chairman : Hon'ble Member, please wind-up now.

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

24.03.2026/1800/DT/YK-2

डॉ0 हंस राज : सभापति महोदय, अभी मुझे बोलते हुए केवल 15 मिनट ही हुए है बस मैं दो मिनट के भीतर अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मैं स्वयं भी इस आसन में बैठ चुका हूं और आपकी व्यथा को समझ सकता हूं। मैं लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगा। हमने डिबेटस में भाग लिया हुआ है और मुझे पता है कि एक मिनट का क्या मुल्य है।

सभापति जी आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह कहना है कि सरकार ने प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के संबंध में बड़ी बाते कहीं हैं। माननीय कृषि मंत्री जी इस समय सदन में नहीं हैं मैं उनसे इस बारे में कहता। वनों को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी बाते यहां पर कहीं गई। लेकिन जो लोग पौधों की नर्सरीज तैयार करते हैं उनकी सैलरी पिछले 17 महिनों से सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। सरकार इस प्रकार से वन कैसे बचायेगी? मैंने इस सदन में कहा भी था कि प्रदेश में जंगल कट रहे हैं। कशमल जो राजस्व का एक बड़ा साधन हो सकता है सरकार ने उन्हे ही उखाड़ना शुरू कर दिया। यह कशमल एक दम से नहीं पैदा होता इसे विकसित होने में सैंकड़ों वर्ष लगते हैं। प्रदेश सरकार तो अपनी संपदा लुटा रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बजट बनाना और बजट पढ़ना वे दो चार बाते जो अधिकारियों ने लिखी जिनका हमनें उस दिन विरोध भी किया, वह सहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने बजट बुक पढ़ी ही नहीं थी। जिसने बजट प्रस्तुत करना है उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हे सदन में क्या बोलना है और किसी से क्या बुलवाना है। यह तो मुख्य मंत्री जी के खिलाफ भी एक साजिश है। पता नहीं अंदर खाते क्या चल रहा है, इसलिए में कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आप भी अर्ल्ट मोड पर रहे यह कुछ भी बुलवा सकते हैं। जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनका मनस उस तरह से कार्य नहीं करता जिस तरह से उसको कार्य करना चाहिए। इसलिए रिटायरमेंट की एक ऐज रखी गई है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि यह बजट खोखली घोषणाओं का बजट है। आपने दिवास्वप्न देखें हैं और दिवास्वप्न को पूरा

करने के लिए आप ने कहीं-न-कहीं कुछ ऐसे शब्दों का सहारा लिया है जो आपके इस बजट को वाइडिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा-सीधा आरोप यह है कि सरकार को चाहिए था कि सरकार इस संदर्भ में सोचती और जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं उनको गोद ले लेती। मैं तो चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हमारे जैसे विधान सभ क्षेत्रों को गोद लें।

24.03.2026/1800/DT/YK-3

दो-दो साल हो गये हैं लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी अभी तक नहीं आये हैं। मैं न्यौता भी देता हूं और कहता हूं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.03.2026/1805/ए.जी.-एन.जी./1

डॉ0 हंस राज जारी..... जारी

दो-दो साल हो गए हैं और मुख्य मंत्री जी स्वयं भी नहीं आए हैं, मैं न्योता भी देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर पूरे प्रदेश की तस्वीर व तकदीर को बदलना है तो यहां के युवाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। यहां के किसानों और बागवानों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको टूरिज्म इंडस्ट्री और हाइड्रो में पोटेंशियल दिखाना है तो उस संदर्भ में सही मायनों में ग्रासरूट स्तर पर बहुत सारी चीज़ें उतारनी पड़ेंगी, तब जाकर हमारा भविष्य ठीक हो पाएगा। ऐसे भाषणों से कभी किसी प्रदेश या किसी प्रांत का भला नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है और मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद।

24.03.2026/1805/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री अजय सोलंकी भाग लेंगे। मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान रखें क्योंकि अभी भी 10 माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष हैं।

श्री अजय सोलंकी : सभापति महोदय, दिनांक 21 मार्च, 2026 को माननीय मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है और उस पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने इतनी विकट परिस्थितियों में बजट पेश किया है और अगर मैं इसे गांव व गरीब का बजट कहूं तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। इस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालक, भेड़पालक, मुर्गीपालक, मछलीपालक—इन सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री के जज़्बे को सलाम करता हूं। आर0डी0जी0 बंद होने के बाद यह बजट पेश किया गया है और किन परिस्थितियों में यह बजट पेश हुआ है, उससे पूरा प्रदेश अछूता नहीं है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार में जिस मात्रा में आर0डी0जी0 मिली, वह बहुत ज्यादा है। पूर्व सरकार को लगभग 71,000 करोड़ रुपये के करीब पैसा मिला। जिसमें 47,000 करोड़ रुपये आर0डी0जी0 के माध्यम से, 13,000 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन और 11,000 करोड़ रुपये कोविड के दौरान मिला है। कोविड में जो पैसा आया था, उसका पिछली सरकार ने क्या सदुपयोग किया, उससे पूरे प्रदेश की जनता विदित है। कोविड काल में क्या हुआ, उसे इस सदन के माननीय सदस्य और पूरे प्रदेश की जनता भलि-भांति जानती है।

24.03.2026/1805/ए.जी.-एन.जी./3

कोरोना काल में जिस तरह का भ्रष्टाचार और पैसों का दुरुपयोग हुआ तथा चंद धन्नासेठों की जेब में पैसा भेजा गया, कोविड काल में किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ, इससे प्रदेश की जनता भलि-भांति वाकिफ़ है और उसका जवाब प्रदेश की जनता ने वर्ष 2022 के चुनावों में दे दिया है।

सभापति महोदय, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया है और दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, मैं मानता हूं कि उससे पशुपालकों की आर्थिकी मजबूत होगी। हमारे किसान और पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में यह अहम फैसला साबित होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री के जज़्बे को सलाम करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से 80 रुपये किया, मक्की का समर्थन मूल्य 40 से 50 रुपये किया और हल्दी का समर्थन मूल्य भी 90 से 150 रुपये किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस बार बजट में उन्होंने अदरक का भी समर्थन मूल्य तय किया है। मैं जिला सिरमौर के किसानों व बागवानों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था व किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए यह बजट पेश किया है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में हमारे संसाधनों के रूप में नदियां और वन हैं। हिमाचल प्रदेश का ग्रीन कवर लगभग 29.5 प्रतिशत है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस बजट में आने वाले वित्त वर्ष में इसे बढ़ाकर लगभग 32.5 प्रतिशत करने का प्रावधान किया है और इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं तथा बधाई देता हूं। हमारी जो नदियां हैं, वे उत्तर भारत के सात राज्यों को फीड करती हैं, चाहे उनकी सिंचाई की बात हो या पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो। ग्रीन कवर से हमारे उत्तर भारत के सभी राज्यों

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1810/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री अजय सोलंकी जारी .....

को फीड करती है, चाहे उनकी सिंचाई की योजनाएं हों या पीने के पानी की व्यवस्थाएं। हमारा प्रदेश उन्हें यह सभी व्यवस्थाएं देता है। हमारे प्रदेश का ग्रीन कवर पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश को ‟लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया" कहा जाता है। लेकिन इसके बदले हमें जो ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, वह भी हमें नहीं मिला। बल्कि इसकी एवज में आर0डी0जी0 को बंद करके केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। सभापति महोदय, आर0डी0जी0 से सिर्फ प्रदेश सरकार का नुकसान नहीं है बल्कि हिमाचल के हर नागरिक का नुकसान है। यह प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता का नुकसान है। आने वाली पीढ़ियां भी देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी नहीं भूलेंगी। आज विडंबना यह है कि प्रदेश के हितों को लूटा और काटा जा रहा है और प्रदेश के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश सरकार का साथ नहीं दे रही। इसके साथ एक विषय यह भी है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो ट्रेड डील की गई है यह ट्रेड डील अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोप के साथ की गई है। इसमें किसानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। विशेषकर हमारे बागवानों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। हर एक प्रोडक्ट जो किसान पैदा करता है। किसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी आर्थिकी मजबूत करना चाहता है। लेकिन इस डील ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब यदि बजट की मुख्य विशेषताओं की बात करूं तो मैं सकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहूंगा। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री ने जो वर्ल्ड-क्लास हेल्थ फैसिलिटी देने का संकल्प किया है वह इस बजट में स्पष्ट दिखाई देता है। हर मेडिकल कॉलेज में 40 बेड, आई0सी0यू0 यूनिट, रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश के लोगों को वर्ल्ड-क्लास हेल्थ फैसिलिटी प्रदेश में दी जाएगी। आज तक हमारा प्रदेश किस स्थिति में था? हमारे प्रदेश के लोगों को छोटी-छोटी स्वास्थ्य जांचों के लिए भी चंडीगढ़, हरियाणा, यमुनानगर और देहरादून जाना पड़ता था। जहां उनका सैकड़ों करोड़ रुपये

24.03.2026/1810/ए0जी0/ए0पी0/-02

खर्च होता था। अब जब वही सुविधाएं प्रदेश में मिलेंगी तो पैसा भी प्रदेश में ही रहेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा, हर विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान चिन्हित किया गया है। उन आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पदों को बढ़ाने का प्रावधान भी सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न नए पदों का सृजन स्वास्थ्य व्यवस्था को ओर मजबूत करेगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्वालिटी ऐजुकेशन पर फोक्स किया है उसके लिए भी मैं शिक्षा मंत्री और समस्त मंत्री मण्डल को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिये जोकि इतिहासिक और साहसिक निर्णय है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किये हैं। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्री मण्डल को बधाई देता हूं और सलाम करता हूं कि बहुत से साहसिक फैसले थे जिनका निर्णय आसान नहीं था। लेकिन सरकार ने साहस दिखाया है और वे निर्णय लिये जिससे हमारे प्रदेश में भविष्य की पीढ़ी का भविष्य सुधारने के लिए बहुत असरदार निर्णय माने जाएंगे,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1815/AT/AS/01

श्री अजय सोलंकी जारी...

चाहे वह राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में शिक्षा संस्थान बनाने का निर्णय हो या डेढ़ सौ स्कूलों को सीबीएसई के अंतर्गत लाने का फैसला हो इस में शुरुआत में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की ओर से कुछ विरोध के स्वर जरूर आए। लेकिन अधिकांश अभिभावकों और स्थानीय निवासियों के समर्थन से आज सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है।

मैं इनके इस जज्बे को सलाम करता हूं और 150 स्कूलों को सीबीएसई के अंतर्गत लाने के निर्णय के लिए आपको बधाई देता हूं। अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है और हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में जाते हैं तो यह निर्णय बहुत अच्छा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि नाहन और पांवटा कॉलेज को खेलों के क्षेत्र में चयनित किया गया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य में जब वे नाहन आए तो उन्होंने लगभग 190 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसी दिन उन्होंने मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए 500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की और मैं धन्यवाद करता हूं कि बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं जिला सिरमौर के सभी निवासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज नाहन में अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत राजनीति की। माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यक्रम से निकले भी नहीं थे और हेलिपैड तक नहीं पहुंचे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रेस में अपनी प्रतिक्रिया देने पहुंच गए। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं। अपने कार्यकाल की कमियों को छिपाने के लिए बार-बार प्रतिक्रिया देना यह प्रदेश की जनता जानती है विशेषकर नाहन विधान सभा की जनता जानती है। इसका परिणाम पिछले चुनाव में भी मिला और आने वाले समय में भी मिलेगा।

24.03.2026/1815/AT/AS/02

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास केवल राजनीति करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर विशेषकर नाहन विधान सभा क्षेत्र में जिस तरह की राजनीति की गई, वह बहुत अशोभनीय है। जहां एक तरफ हमें माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्तमान में जहां मेडिकल कॉलेज स्थित है वहां बहुत अधिक कंजेशन है। वहां दो गाड़ियां भी ठीक से नहीं पहुंच

सकतीं और मोटरसाइकिल पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। जो नया स्थान चयनित किया गया है वह भी नगर परिषद (एम.सी.) क्षेत्र के भीतर ही है। नाहन नगर परिषद की लगभग 160 बीघा जमीन इसके लिए चुनी गई है जो वर्तमान मेडिकल कॉलेज से लगभग एक, सवा किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद इस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया। लेकिन विधान सभा क्षेत्र और जिला सिरमौर की जनता जानती है कि क्या उचित है। सभी ने इसका समर्थन किया है अगर जादा समर्थन जरूरत है तो आपके नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर देखिए लगभग 95 प्रतिशत लोगों के कमेंट्स उनके खिलाफ बोल रहे हैं।

Chairman: Please wind-up. अभी बहुत लोगों ने बोलना है।

श्री अजय सोलंकी: अभी 13 मिनट हुए हैं, सर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं केवल माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बजट में समाज के आखिरी पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए है एक जो आखिरी पंक्ति पर बैठे व्यक्ति की सेवा कर रहा हैं, उनके वेतनमान में वृद्धि की गई है यह बहुत सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, पंप ऑपरेटर, मल्टी टास्क वर्कर और एनएचएम के कर्मचारियों के वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1820/केएस/एएस/1

श्री अजय सोलंकी जारी ---

चाहे वह एन0एच0एम0 के कर्मचारियों के वेतन में अभूतपूर्व वृद्धि है, चाहे स्वास्थ्य अधिकारी (आयुष) का वेतन 50 हजार 260 रुपये से 60 हजार 780 रुपये किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी (डेंटल) के वेतन में 49 हजार 400 रुपये से 61 हजार 200 रुपये की वृद्धि की गई है। फार्मासिस्ट को 30 हजार 500 रुपये से 46 हजार 500 रुपये किया गया है। ए0एन0एम0 की सैलरी 26 हजार 650 रुपये से 38 हजार 500 रुपये की गई है। आशा

कोऑर्डिनेटर की सैलरी 30 हजार 775 रुपये से 45 हजार 750 रुपये की गई है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की सैलरी 41 जार 550 रुपये से 62 हजार 650 रुपये की गई है। डेंटल हाइजीनिस्ट की सैलरी 29 हजार रुपये से 42 हजार 650 रुपये की गई है। अकाउंटेंट की सैलरी 39 हजार 650 रुपये से 59 हजार 750 रुपये की गई है। लैब टैक्नीशियन की सैलरी 35 हजार 750 रुपये से 49 हजार 500 रुपये की गई है। इसी तरह से एन0एच0एम0 में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनमें स्टाफ नर्स की सैलरी 13 हजार 925 रुपये से 25 हजार रुपये की गई है। यह बहुत अभूतपूर्व वृद्धि है और सभापति महोदय, यह उन लोगों से पूछो जो बहुत ही कम वेतन में अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनकी लिस्ट बहुत लम्बी है। मैं सभी की तरफ से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और अपनी तरफ से भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि मैडिकल कॉलेज नाहन के लिए 500 करोड़ रुपये और मिल्क प्रोसैसिंग यूनिट जो नाहन में बनने जा रही है उसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आने वाले वित्तीय वर्ष में नाहन हैलीपोर्ट का निर्माण करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, आपके आदेशों का पालन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ में इस बजट का भी समर्थन करता हूं। निश्चित तौर पर यह बजट हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में एक अच्छा कदम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

24.03.2026/1820/केएस/एएस/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान पर चर्चा करने का आपने अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, पहली बार इस माननीय सदन में हुआ होगा कि जो हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, हिमाचल प्रदेश की जी0डी0पी0 में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है, जिनके योगदान से हिमाचल प्रदेश को पूरे विश्व में जाना जाता है, उन बागवानों की इस बजट में कोई चर्चा नहीं है और ना ही समर्थन मूल्य की इसमें बात की गई

है। इतिहास में जो आज आप सत्ता में हैं, शिमला पार्लियामेंट से 14 विधायक हैं और कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र में जिस तरह से बागवानों का गला काटा गया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक बागवानों के विरुद्ध पहली बार विधान सभा में ऐसा बजट आया है। इसके लिए मैं सभी को दोषी कहता हूं क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन्होंने इस बजट को बनाने केलिए मुख्य मंत्री महोदय को प्रैशराइज़ नहीं किया कि बागवानों का सबसे बड़ा योगदान है। उनकी वजह से पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में हिमाचल को जाना जाता है। और भी बहुत से कारण हैं परंतु बागवानी क्षेत्र का मुख्य योगदान है क्योंकि 8 हजार करोड़ रुपये की जी0डी0पी0 बागवानों की वजह से हिमाचल प्रदेश में है। पहली बार बजट इतना कम हुआ, आप सारे बजट निकालना, बजट कभी कम नहीं हुआ था। कोरोना काल में जय राम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश का 1 रुपये भी बजट कम नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की पूरी इंडस्ट्रीज़ बंद थीं। पूरा बिजनैस, पूरी एक्साइज़ बंद थी। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा था। एक रुपये का बजट भी हिमाचल प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष 2020-21, 2021-22 में कम नहीं किया। जिस तरह से पहली बार बजट कम हुआ है, हिमाचल प्रदेश की जनता को जो इसका नुकसान होगा वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

24.03.2026/1825/av/dc/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा--------जारी

सभापति महोदय, पावर में 472 करोड़ रुपये यानी 56.12 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसमें आधे से भी ज्यादा कटौती की गई है। मैं समझता हूं कि आज से पहले इतनी कटौती कभी नहीं की होगी। आप सारे बजट भाषण निकालकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि आज से पहले इतनी कटौती कभी नहीं की होगी।

रोड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सिविल एविएशन में 20.59 प्रतिशत कटौती की गई है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में 21.15 प्रतिशत कटौती की गई है। वॉटर सप्लाई जोकि मानव के लिए सबसे जरूरी है, उसमें भी 42.06 प्रतिशत कटौती की गई है और मैं समझता हूं कि इससे

पहले इतनी कटौती कभी नहीं की होगी। एलीमैंटरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी 44.47 प्रतिशत की कटौती हुई है और मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा कटौती इससे पहले कभी नहीं हुई होगी तथा इस कटौती से हिमाचल प्रदेश एजुकेशन में कहां पहुंचेगा वह इस कटौती से सब सामने आने वाला है। हैल्थ और आयुर्वेदा के अंतर्गत जो कटौती हुई है वह 47.61 प्रतिशत हुई है। मेरे हिसाब से हैल्थ और एजुकेशन में कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी परंतु इसमें भी बहुत ज्यादा की गई है।

यहां पर अभी माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नहीं बैठे हैं। रूरल डवलपमैंट में 52 प्रतिशत कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी कटौतियां की गई हैं। मेरे सत्ता पक्ष के साथी हर बार कहते हैं कि आर0डीजी0 से इनको ...(व्यवधान) नहीं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी आंकड़े गलत नहीं है क्योंकि मेरे पास सभी आंकड़ों का तथ्यों के साथ रिकॉर्ड है। वर्ष 2020-21 के दौरान श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय में 15वें वित्त आयोग के तहत 5524 करोड़ रुपये मिले थे जबकि काँग्रेस पार्टी की सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9374 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10126 करोड़ रुपये व वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11806 करोड़ रुपये मिले थे और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13949 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। पिछली भाजपा सरकार और वर्तमान सरकार के बीच में जो फर्क है वह 7171 करोड़ रुपये का

24.03.2026/1825/av/dc/2

है जोकि इनको 16वें वित्तायोग के समय में मिलना है। ये लोग उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं यह बात तथ्यों के साथ कह रहा हूं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि 196 केंद्रीय प्रायोजित स्कीम्ज के लिए हर वर्ष राशि बढ़ती है। वह हमारी भाजपा सरकार के समय में 3768 करोड़ रुपये मिलते थे जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में इनको 5600 करोड़ रुपये मिलेंगे जिसमें काफी एनहांसमैंट हुई है। इसके अतिरिक्त जो 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण है, उसमें आदरणीय श्री जय राम ठाकुर की सरकार को 250 करोड़ रुपये की राशि मिली थी जबकि आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1500 करोड़ रुपये

मिले थे। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2400 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3400 करोड़ रुपये और अभी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 4400 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। आप खुद ही 250 करोड़ रुपये और 4400 करोड़ रुपये में फर्क देख सकते हैं। इस बजट में आपको लगभग 11,000 करोड़ रुपये की राशि एनहांस होकर मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वे 53.06 प्रतिशत है जबकि हिमाचल प्रदेश की ओर से 47.06 राजस्व प्राप्तियां होती हैं।

सभापति : अभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय सदन का क्या मत है यानी सदन को कितनी देर तक बढ़ाया जाए?

सदस्यगण : सभापति महोदय, एक घण्टा बढ़ा दीजिए।

सभापति : इस सदन की बैठक एक घण्टा यानी 07.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।

माननीय विधायक टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1830/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश को जो राजस्व केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, वह 53.6 प्रतिशत है जबकि स्वयं प्रदेश का राजस्व 47.6 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश का अधिकांश विकास हो रहा है। जिस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वह बहुत ही दुःखद बात है। मैं आपके ध्यान में एक और महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं। एक्सटर्नल एडेड प्रोजैक्ट्स जिनकी गारंटी केंद्र सरकार ने दी है उनके तहत हिमाचल प्रदेश में 19 प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, जिन पर लगभग 16,760 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। ये प्रोजैक्ट्स JICA, ADB और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से संचालित हो रहे हैं और इनकी पूरी गारंटी केंद्र सरकार की है। इनके माध्यम से 16,760 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश में खर्च हो रहे हैं लेकिन इतने बड़े निवेश का कहीं उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जय राम ठाकुर जी के समय में अनेक जनहित योजनाएं चलाई गई थीं, जैसे विभिन्न पेंशन योजनाएं, जनमंच, स्वावलंबन योजना, शगुन योजना और पानी के बिल में राहत इत्यादि। किसानों से पानी का बिल नहीं लिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पुनः लागू किया है। महिलाओं के लिए बस किराया आधा था और 125 यूनिट बिजली भी फ्री में प्रदान की जाती थी। सभापति महोदय, इन योजनाओं को बंद करके प्रदेश के साथ अन्याय किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 90:10 का अनुपात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए लागू किया है, उन्हीं स्कीमों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है। नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी हैल्थ प्रोजैक्ट्स चल रहे हैं, वे सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से संचालित हो रहे हैं। समग्र शिक्षा और शिक्षा सैक्टर में भी वर्ष 2026-27 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से ही पैसा आया है। पहली बार पंचायतों को सीधे फंड दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायतों के लिए इसका प्रावधान किया है जिसमें लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्ष 2026-27 में पंचायत राज संस्थाओं को काफी अधिक धनराशि मिलने वाली है। क्या किसी ने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में एम्स बनेगा जिस पर लगभग 3000 करोड़ रुपये

खर्च होंगे, क्या किसी ने सोचा था कि अटल टनल जैसी परियोजना बनेगी, जिस पर लगभग 3200 करोड़ रुपये खर्च होंगे? पिछले 3 वर्षों में लगभग 6000 करोड़ रुपये एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिए हैं। सड़कों की मरम्मत, पानी और बिजली के कार्यों में जो भी सुधार हो रहा है, वह केंद्र से प्राप्त धनराशि से ही संभव हो रहा है। दुःख की बात यह है कि इन सभी योजनाओं का कहीं उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) के तहत लगभग 4100 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। इसी योजना के माध्यम से बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड किए जा रहे हैं, कंडक्टर लगाए जा रहे हैं और बिजली विभाग के सभी कार्य संचालित हो रहे हैं। यह सारा पैसा केंद्र

सरकार दे रही है लेकिन इसके लिए धन्यवाद तक नहीं किया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इस योजना के तहत लगभग 100 ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड या स्थापित किए जाने हैं। इसी प्रकार, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 18000 गरीब और वंचित लोगों को मकान दिए गए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तीसरे चरण में लगभग 2800 करोड़ रुपये और चौथे चरण में लगभग 2100 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 सड़कें बन रही हैं जिन पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इससे क्षेत्र का व्यापक विकास हो रहा है। ... (व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा .... जारी

24-3-2026/1835/एन0एस0-एच0के0/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----जारी

...(व्यवधान) सभापति महोदय, अभी सारे मंत्री यहां पर मौजूद हैं और वर्ष 1864 में ब्रिटिश राज द्वारा शिमला को अधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। सर जॉन लारेंस द्वारा राजधानी को कलकत्ता से शिमला शिफ्ट किया गया था। 162 वर्षो के बाद पूरे देश की राजधानी शिमला थी, उसको डी-सेंट्रलाइज करने या वीक करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्लियामैंट से 14 विधायक और 5 मंत्री हैं। धृतराष्ट्र तो अंधे थे और इस वजह से वे छूट गए थे लेकिन आप लोग न तो अंधे हैं और न ही बहरे हैं इसलिए आप लोग नहीं छूट सकते। आप सभी के पूर्वज स्वर्गीय श्री राम लाल ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी और स्वर्गीय श्री गुमान सिंह जी को बड़ी पीड़ा हो रही होगी कि हमारे वंशज कैसे मूकदर्शक बने हुए हैं और शिमला को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं? जिस शिमला को आपके पूर्वजों ने 50 वर्षों तक सींचा है, वह शिमला खत्म न हो, हमें सिर्फ पद नहीं चाहिए बल्कि शिमला भी बचना चाहिए। यहां पर सेब के बारे में एक भी माननीय सदस्य ने बात नहीं की और इस बजट में सेब का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है। सेब की पैदावार से बागवानों ने पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन

किया तो उसके बारे में इस बजट में कोई चर्चा नहीं की और न ही कोई बजट प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, यहां से एच0पी0टी0डी0सी0 का कार्यालय शिफ्ट किया गया। मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरी जगहों पर कुछ नहीं कीजिए, आप दूसरी जगहों में इससे ज्यादा कीजिए लेकिन शिफ्टिंग गलत है। शिमला के अस्तित्व को खत्म करना गलता है और शिमला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसे अच्छी तरह से समझें। रेरा, ओ0बी0सी0 कार्यालय, कामगार बोर्ड, कौशल विभाग, एच0पी0सी0टी0एस0 यानी कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कार्यालय को शिफ्ट किया गया और नशा निवारण बोर्ड, फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ विंग, आर्म्ज पुलिस एंड ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट किया गया। आप कांगड़ा में चाहे 20 ऑफिस खोलिए और इससे बड़े ऑफिस खोलें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेफिक जाम से बचना चाहते हैं तो आप कार्यालयों को शिमला ग्रामीण या कसुम्पटी की तरफ ले जाएं। हमें कोई एतराज नहीं है। आप जितने मर्जी फ्लाई ओवर

बनाएं। हमारा मकसद यह नहीं है कि हम किसी क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि शिमला की जनता हमारे पास इस बात को उठा रही है।

(***) शिमला पार्लियामैंट में आपने इस बजट बुक में क्या दिया है? आपने इतनी बड़ी बजट बुक में शिमला पार्लियामैंट को कुछ नहीं दिया है। शिमला पार्लियामैंट के मत्री सिर्फ पद ग्रहण करके शिमला के विकास के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। शिमला पार्लियामैंट में पांच मंत्री और कुल 14 विधायक हैं और वे मुझे बताएं कि इस बजट बुक में शिमला पार्लियामैंट के लिए क्या दिया है?

सभापति महोदय, कल माननीय भवानी सिंह पठानिया जी ने बड़ी गलत स्टेटमैंट इस माननीय सदन में दी है कि अमरीका से सेब 40 रुपये प्रतिकिलो आ रहा है। मैं इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अमरीका से सेब कम-से-कम 80 रुपये प्रतिकिलो आएगा और उस पर 25 प्रतिशत टैक्स होगा, भारत में 105 रुपये से कम सेब

नहीं आएगा। उसको भी कोटा बेस्ड किया है और सिर्फ 1 लाख मीट्रिक टन आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में सेब हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में होता है और जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब होता है तथा 24 लाख मीट्रिक टन सेब इन प्रदेशों में होता है। भारत को सेब की 32 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है। जो रिमेनिंग सेब है वह इटली, चीन व अन्य देशों से आता है। देश में 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है तो उसमें चीन से सेब आता था और हमारे सेब की वैल्यू जीरो करता था। भाजपा की सरकार देश में आई और

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

24.03.2026/1840/RKS/HK-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

अब चाइना से एक दाना भी सेब नहीं आ रहा है इसलिए हमारे सेब की वैल्यू देश में बढ़ी है।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया आप अपनी बात समाप्त करें क्योंकि अभी और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सर, मुझे थोड़ा और बोलने का समय दीजिए। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के समय में कर्मचारियों के वेतन में 3.59 प्रतिशत की इंक्रीज हुई थी। आपके इन तीन सालों का जो मेरे पास डेटा उपलब्ध है उसके अनुसार -2.33, -2.64 और -2.90 प्रतिशत डिक्रीज हुई है जोकि कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप हमेशा लोन की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी के समय कुल ऋण 48,500 करोड़ रुपये था और उसके बाद वर्ष 2022-23 तक 68, 600 करोड़ रुपये ऋण हुआ। इसके बाद का लोन 39,400 करोड़ रुपये है। इस टोटल लोन का 40 प्रतिशत लोन

आपकी सरकार ने इन तीन सालों के कार्यकाल में ले लिया है। वर्तमान में यह लोन 1 लाख 8 हज़ार करोड़ रुपये पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश की जनता इसमें बुरी तरह से फंस गई है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 में जो विकास कार्य के लिए बजट खर्च होना है वह सिर्फ 20 प्रतिशत ही है। पेंशन में 21 प्रतिशत, ब्याज अदायगी में 9 प्रतिशत, ऋण अदायगी में 13प्र तिशत और 20 प्रतिशत सिर्फ विकास कार्यों के लिए खर्च किए जाने हैं। श्री जय राम ठाकुर जी के समय में विकास कार्यों के लिए 43 प्रतिशत, 41 प्रतिशत और 39 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता था। सभापति महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों की बात करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी गैंती भी नहीं मारी गई है। वहां सारे काम केंद्र प्रायोजित योजनओं के माध्यम से हो रहे हैं। वहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत सब काम बंद पड़े है। वहां पर कोई भी डवलपमेंट नहीं हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का विकास ठप पड़ा हुआ है। वहां पर साढ़े तीन साल में एक भी संस्थान नहीं खोला गया

24.03.2026/1840/RKS/HK-2

है। जिस तरह से चौपाल विधान सभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है, मैं इस दर्द को इस विधान सभा में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वहां के किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। यह बजट दिशाहीन, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, सरकारी कर्मचारी विरोधी, श्रमिक विरोधी, विकास विरोधी, बागवानों का विरोधी और अपंग लोगों का विरोधी है। मैं इस बजट का समर्थन ही नहीं कर सकता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने जो विषय उठाए हैं मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो इन्होंने सेब का मुद्दा उठाया है उसमें कहीं-न-कहीं ध्यान भटकाने की बात की गई है। हमारे सेब उत्पादक आशा कर रहे हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने रिज मैदान में सेब की इम्पोर्ट ड्यूटी तीन गुना बढ़ाने की घोषणा की थी। वर्मा जी आप भी उस समय वहां उपिस्थत थे। उन्होंने सेब को स्पेशल कैटेगिरी में लेने की बात की थी। माननीय प्रधान मंत्री जी को सोलन के ठोडो मैदान और हमीरपुर जिला के सुजानपुर में भी

सेब याद आए थे। उन्हें ये बातें सिर्फ चुनाव के समय ही याद आती हैं। वर्ष 2014, वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के पार्लियामेंट इलैक्शन के समय इस प्रमुख मुद्दे को सेब बहुल्य क्षेत्र के लोगों के लिए उठाया गया था। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी को वोट पड़े और तीनों पार्लियामेंट के चुनावों में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद बने। लेकिन जहां करने की बात है क्योंकि कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है। आज आप मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं परंतु यह तो मुद्दा ही नहीं था। यह तो आपसे कोई मांग ही नहीं कर रहा है। हमारी जो SAFTA (South Asian Free Trade Area) countries है, नेपाल के माध्यम से टर्की से रिकॉर्ड तोड़ इम्पोर्टिड सेब भारत वर्ष आ रहे हैं। पिछले 12-13 सालों से मोदी जी सत्ता में है। ...(व्यवधान) आप मोदी जी को तो छोड़िये, आप नेहरू जी को भी नहीं भूल रहे हैं। आपकी 12-13 सालों से केंद्र में सरकार है और तब से रिकॉर्ड तोड़ इम्पोर्टिड सेब भारत वर्ष में आ रहा है जिसका यहां के बागवानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से हमारे European Union, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ समझौते हो चुके हैं उसका नुकसान भी अवश्य होगा। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो मोदी जी ने पब्लिकली अनाउंस किया है। आप या तो इस बात को पब्लिकली डिनाउंस करें या फिर आपको ये बोलना नहीं चाहिए था।

24.03.2026/1840/RKS/HK-3

मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की तो कहीं बात ही नहीं हुई है जिसका आंकड़े आप यहां दे रहे हैं। इन्होंने समर्थन मूल्य का पैसा देने की भी बात की है। समर्थन मूल्य का जो पैसा

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1845/बी.एस./ वाई.के.-1

शिक्षा मंत्री जारी...

दूसरा, एक और बात की है कि जो हमारा समर्थन मूल्य का पैसा है। जिसको मिनिमम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत दिया जाता है, यह 50-50 प्रतिशत के आधार पर दिया

जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर आदरणीय मोहन लाल ब्राक्टा जी ने भी सुबह कहा कि 170 करोड़ रुपये के आसपास, कि हमने गत 3 वर्षों में एम0आई0एस0 के तहत पेमेंट्स की हैं और वह 170 करोड़ में से 90 करोड़ वह था जो पिछली सरकार के कार्यकाल का था। सरकार अपनी कंटिन्यूटी में कार्य करती है। लेकिन यह भी एक fact of the matter है कि फरवरी, 2024 में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लाया, जो लगभग 4000 करोड़ रुपये के आसपास का आपका एम0आई0एस0 के तहत पैसा होता था, वह उन्होंने शून्य कर दिया। सिर्फ 1 लाख रुपये का टोकन बजट रख दिया है। वह आपकी स्कीम ही खत्म कर दी है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार 110 करोड़ रुपये के आसपास बजट है, वह 100 परसेंट वर्ष 2024 के बाद एम0आई0एस0 का टोटल है, एक तरह से पूरी निर्भरता स्टेट गवर्नमेंट पर आ चुकी है। केंद्र ने जो अपने हाथ खड़े कर दिए, इसका भी नुकसान हमारे को हो रहा है।

एक चौपाल की बात की, अभी हाल में हमने आपको स्पोर्ट्स हॉस्टल दिया, उसका भी धन्यवाद कर दीजिए। आदरणीय वर्मा जी मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं इनसे टाइम टू टाइम आगाह करना पड़ता है और ये हमारे मित्र भी रहे हैं।

सभापति : अभी पिछले वक्ता की स्पीच में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था जहां पर दो कांस्टीट्यूएंसीज का नाम लेकर उस सैंटेंस का ऐंड (***) शब्द से किया गया था। उसे यहां से एक्सपंज कर दिया जाए। इसे डिक्सनरी खोलकर देखना पड़ेगा but expunge this unparliamentary sentence please.

24.03.2025/1845/बी.एस./ वाई.के.-2

अब माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी भाग लेंगे।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2026-27 के वित्तीय बजट अनुमान जो पेश किये हैं, इस पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का समय दिया आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बजट किसानों का, बागबानों का और गरीब परिवारों का बजट है। मैं जो समझता हूं कि इसे आम गरीब का बजट कहा जाना चाहिए। क्योंकि इसके

साथ-साथ आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्य मंत्री जी की एक सोच, जो हिमाचल प्रदेश को एक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की है, मैं समझता हूं वह भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल तब बनेगा, जब एक आम परिवार की और गरीब परिवार की इस सदन के अंदर चर्चा होगी। आज उन किसानों के बारे में, दूध पैदा करने वाले लोगों के बारे में, जो हमारे पिछले सेशन में भी, पिछले बजट में भी और इस बजट में भी जब हमेशा उन लोगों की चर्चा होती है। हमारे प्रदेश के 95 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। जो छोटी-मोटी खेतीबाड़ी करते है और अपना परिवार चलाते हैं। आज हम इस बजट के माध्यम से उन परिवार और किसानों की बात करते हैं जो पैसा किसान की जेब में सीधा जा रहा है। उससे वे लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि कम-से-कम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समृद्ध राज्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें अकेला छोड़ा जा रहा है, हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। परंतु मैं समझता हूं कि उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। कल को यह इतिहास में लिखा जाएगा हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी ने सोच रखी है और समृद्ध राज्य बनाने के लिए तो मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी का नाम हमेशा इसको गोल्डन वर्ड्स में नाम लिखा जाएगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छी सोच को लेकर मुख्य मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष वाले जो लोग हैं, उनकी चर्चा हमेशा यही रहती है कि हिमाचल कब समृद्ध हिमाचल बनेगा? मैं कहता हूं कि समृद्ध हिमाचल बनने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि जो आपने पिछले 5 वर्षों में व्यवस्था को बिगाड़ा है उसको सुधारने में भी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इस तरीके से, आपकी सरकार ने व्यवस्था का पतन किया था, आज मुख्य

24.03.2025/1845/बी.एस./ वाई.के.-3

मंत्री जी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और उसका जीता-जागता उदाहरण है और यह ग्राउंड पर दिख रहा है। मैं एजुकेशन की बात करूंगा, हेल्थ की बात करूंगा और अन्य सेक्टर्ज की बात भी करूंगा। आज हमेशा पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर हिमाचल कब

बनेगा? यह कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट बन जाएगी। कम से कम इस बात को समय लगता है। जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण काम कर रहे हैं हमारा प्रदेश अवश्य आत्मनिर्भर बनेगा। हिमाचल में इतनी आपदा आने के बाद भी, उसके बाद हिमाचल जो है,

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1850/DT/YK-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी..

कम-से-कम इस बात को समय लगना है। जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं और मंत्री मंडल के सभी मंत्री काम कर रहे हैं। विपक्ष ने तो प्रदेश में फाइनेंशियल क्रासिज लाने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश के लिए आर0डी0जी0 केंद्र सरकार के द्वारा बंद की गई है। जब आर0डी0जी0 बहाल करने के लिए विशेष सत्र बुलवाया गया और उस पर चर्चा हुई तब भी विपक्ष के द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया। आज भी नेता प्रतिपक्ष दिल्ली गये हुए हैं, हमें पता है वे क्यों दिल्ली गये हैं? केंद्र सरकार से जो प्रदेश सरकार को फंड मिलने हैं वे उनको रूकवाने के लिए ही दिल्ली गये हुए हैं। यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। जब प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि आर0डी0जी0 बहाल करने के लिए हम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में चलने को तैयार हैं तो ये हमारे साथ क्यों नहीं जाते? ये इसलिए साथ नहीं चलना चाहते क्योंकि हमकों भी पता है कि इन्होंने उनसे अकेले में क्या बात करनी है। अगर हमारे साथ गये तो फिर तो ये बात नहीं कर सकते। ये तो पीठ के पीछे बात करने वाली बात है या पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ तो वैसे ही नहीं है पर ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ भी नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता इन्हें देख रही है कि विपक्ष का व्यवहार प्रदेश के लोगों के प्रति कैसा है। नेता प्रतिपक्ष कल अपने वक्तव्य में बार-बार यह बात बोल रहे थे कि मैंने एक डेटा लेने के लिए बड़ी भारी मेहनत की। मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि इससे आधी मेहनत भी आपने अपने कार्यकाल में की होती तो आज प्रदेश के यह हाल नहीं होते। आपने सरकार पर टीका-टिप्पणी करने के लिए तो मेहनत की है। हिमाचल प्रदेश की आज जो आर्थिक स्थिति है उसमें सबसे अहम रोल उनका ही है। आर0डी0जी0

के संबंध में कभी भी विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आर0डी0जी0 प्रदेश का हक है और प्रदेश को वह मिलना चाहिए। लेकिन आज प्रदेश का वह हक केंद्र सरकार के द्वारा छिना गया है। विपक्ष बोल रहा है कि उत्तराखंड की आर0डी0जी0 भी बंद कर दी गई है। फिर कहते हैं कि केरल की आर0डी0जी0 भी बंद कर दी गई है। हमने उत्तराखंड या केरल से क्या लेना? हमनें तो अपने प्रदेश की बात करनी है। हमें तो हिमाचल के लोगों ने चुन कर भेजा है। हमने इस सदन में किसी और राज्य की बात क्यों करनी। मुझे चिंतपूर्णी की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस सदन में भेजा और अगर मैं चिंतपूर्णी के लोगों की आवाज इस सदन में न उठा सकूं तो फिर मेरा क्या लाभ? उन्हें मुझे यहां पर काली कॉफी पीने के लिए थोड़ा भेजा है।

24.03.2026/1850/DT/YK-2

इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमें हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र में मिलकर जोर शोर से रखने की आवश्कयता है। जिन राज्यों का उल्लेख विपक्ष यहां करता है उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं अपने क्राइसिज हैं। उनके प्रदेश के पास इंकम के अन्य साधन हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात का विरोध करना है यह उनकी मर्जी है। हम अपने प्रदेश की बात इस विधान सभा के अंदर रखेंगे और रखना भी चाहिए। मुझे चितपूर्णी विधान सभा के लोगों ने चुनकर भेजा है और मैं हर मंच में अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रखता हूं और मैं अपनी आवाज को दबने भी नहीं देता।

श्री रणधीर शर्मा जी इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के द्वारा 4 घंटे तक बजट पढ़ा और पानी पी-पी कर बजट पढ़ा। मैं एक बात इस सदन में कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया वह आम जनता का बजट है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो पानी पीकर बजट पढ़ा लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अपने कार्यकाल में जब बजट पढ़े तो लोगों का लहू चूस-चूस कर बजट पढे आपने पूरे प्रदेश का लहू पिया इसलिए आज हिमाचल प्रदेश का ये हाल है।

मैं इस सदन में विपक्ष के साथियों के वक्तव्य को बड़े आराम से सुन रहा था। श्री प्रकाश राणा जी ने कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश का पानी ही साफ नहीं है। माननीय सदस्य खुद क्या पी रहे हैं क्या वे मिनरल वॉटर पी रहे हैं या अपना पानी अपने घर से लेकर आ रहे हैं। पूरा हिमाचल प्रदेश यही के जल स्त्रोतों का पानी पी रहा है। हिमाचल

प्रदेश में पानी कहां से आ रहा है? हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र का पानी ठीक नहीं हो सकता उस पर बात की जा सकती है, लेकिन यह कहना कि पूरे हिमाचल प्रदेश का पानी ठीक नहीं है-यह गलत बात है।

विपक्ष के साथी इस सदन में जोर-जोर से चिल्लाते हैं कि हमनें अपनी सरकार के समय इतने डाक्टर्ज भर्ती किए, हमने इतने अध्यापक भर्ती किए, हमने इतने एस0डी0ओ0 लगाये, इतने जे0ई0 लगाये, अगर लगाये तो वे कहां गये? उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। जब हमारी सरकार आई तो मैंने देखा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही 20 स्कूल ऐसे थे जहां पर अध्यापक नहीं थे। लेकिन आज मेरी विधान सभा का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर अध्यापक न हो। जोर-जोर से चिल्लाने से प्रदेश के मुद्दे हल नहीं होते। अगर हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया तो आपके समय में जो डाक्टर्ज, एस0डी0ओज0 या जे0ईज0 लगाये गये थे वे कहां गये? पहले मेरी विधान सभा के अंब के हस्पताल में 4 स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज थे आज वहां पर

24.03.2026/1850/DT/YK-3

7 स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज हैं। 3.50 करोड़ रुपये नई ओ0पी0डी0 ब्लॉक के निर्माण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिए हैं। आज उस हस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है। जो टेस्ट पहले नंगल या होशियारपुर पंजाब में जाकर 1000 रुपये में होते थे वह अब अंब होस्पिटल में हो रहे हैं। ये तो फोके फायर हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

24.03.2026/1855/ए.जी.-एन.जी./1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू..... जारी

और दिवाली के पटाखों की तरह हैं। वैसे तो इन्होंने चलना ही नहीं और अगर चलना भी है तो किसी की जेब में चलना है। मैं एक बात सुनाना चाहता हूं कि एक बच्चा था और उसने पटाखे लेकर दिवाली के दिन चलाने की कोशिश की और एक दूसरा बच्चा जोकि थोड़ा छोटा था, गरीब था तथा साइड में खड़ा था। उसने देखा कि पटाखा चल नहीं रहा था, तो

उसने उसे उठाया और जेब में डाल लिया। वह पटाखा उसकी जेब में ही चल गया। वह बम्ब ये लोग हैं। जिन्होंने कभी चलना नहीं है और अगर चलना है तो दूसरे की जेब में चलना है। ये लोग ऐसे बम्ब हैं कि शादी में चलें या न चलें लेकिन किसी की अर्थी पर जरूर चलेंगे। इन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर जरूर बोलना है लेकिन अपने समय में किया कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से यहां पर बातें रखने की कोशिश की जा रही है, उससे हिमाचल की जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश की जनता इन्हें पूरी तरह से जानती है। पिछले कल भी माननीय सदस्य, श्री दीप राज जी बड़े शायराना अंदाज से बोल रहे थे कि यह बजट एस0सी0 विरोधी है। मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी से आता हूं। मैं सुन रहा था कि ये कोई एक शब्द तो बोलें कि किस तरीके से यह बजट एस0सी0 विरोधी है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल बोलने से नहीं बल्कि फैक्ट पर बात करो कि यह बजट किस तरीके से एस0सी0 विरोधी है। अगर कोई एस0सी0 विरोधी है तो भाजपा की सरकार और आर0एस0एस0 के लोग हैं, जिन्होंने आज तक आर0एस0एस0 के अंदर Scheduled Caste के लोगों की एंट्री नहीं होने दी थी। मैं समझता हूं कि अगर एस0सी0 के बारे में किसी ने सोचा है तो वह कांग्रेस की सरकार है। मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करूंगा। वर्ष 1972 में जब मुजारा एक्ट आया, तो वह हमारे पूरे देश के एस0सी0 समाज के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था। उस समय हमें जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था।

24.03.2026/1855/ए.जी.-एन.जी./2

उस एक्ट के बाद हमें जमीनें दी गईं। हमें मुजारा एक्ट के तहत उन जमीनों का गैर मौरूसी मालिक बनाया गया। हमारे लोगों के लिए रिजर्वेशन भी कांग्रेस सरकार ही लेकर आई। आज अगर आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में हैं तो यह हमारी कांग्रेस पार्टी की देन है। उस समय जो लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए, उन्हें भी 10-10 कनाल जमीन दी गई। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी वर्ग, चाहे एस0सी0 हो या

ओ0बी0सी0, की हितैषी कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आज हमें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री की जो सोच है, उसके लिए विपक्ष के लोग कहते हैं कि उन्होंने गलत फैसले लिए हैं। क्या गलत फैसला लिया? हमने ओ0पी0एस0 दी, क्या यह गलत फैसला था? हमने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के बारे में सोचा, क्या यह गलत स्टैप था? हमने मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना बनाई और उसके तहत ऐसे हजारों बच्चों के लिए काम किया, जो कभी यह सोचते थे कि उनका कोई नहीं है लेकिन आज उनके लिए सरकार ही माता और सरकार ही पिता है। यह ऐसी योजना है जो पूरे भारत में पहली बार केवल हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है। क्या यह गलत कदम था? आज हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वे सभी आम लोगों के लिए हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वह सराहनीय है। विपक्ष के लोगों का केवल एक काम है कि जो लोग केन्द्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको टारगेट करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया शून्य काल के दौरान श्री अनिल ढ़डवाल के संदर्भ में एक मामला लेकर आए थे और उन्हें केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा श्री सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया। जब हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उसे भी पूरे देश के अंदर एक जुर्म बनाकर पेश किया गया। क्या आज प्रोटेस्ट करना भी गलत हो गया है? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी गलत हो गया है? लेकिन मैं देखता हूं कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है

24.03.2026/1855/ए.जी.-एन.जी./3

आज श्री सोनम वांगचुक भी जेल से बाहर आ चुके हैं और श्री अनिल ढ़डवाल भी बाहर आ चुका है। अभी मैं माननीय सदस्य, श्री राकेश कालिया से बात कर रहा था और हमारे होनहार कार्यकर्ता, जोकि युवाओं की आवाज उठाते हैं, वे भी बाहर आ गए हैं। केन्द्र की सरकार ने तो उन्हें भी तिहाड़ जेल में डालने की कोशिश की थी। हमारे यूथ कांग्रेस के जो

लड़के रोहडू से रेस्क्यू किए गए थे, आज वे भी जेल से बाहर आ चुके हैं। क्योंकि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हमेशा होकर रहता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज इन लोगों को यह सिखाना चाहिए। अगर इन्होंने सोचा होगा कि लोगों को डराकर या धमकाकर उनकी आवाज दबा देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आज माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरीके से हिमाचल के किसानों के बारे में सोचा है, उसके तहत गाय के दूध का दाम 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये तथा भैंस के दूध का दाम 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये किया गया। मेरे ख्याल से पूरे देश में दूध की सबसे ज्यादा एम0एस0पी0 हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। इसके अलावा हल्दी पर भी काफी फोकस किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है, बंदर, नीलगाय और अन्य जानवर फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जानवर भी नहीं खाते और उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। आज हिमाचल में हल्दी का रेट 90 से 150 रुपये तक पहुंचाया गया है और 30 रुपये अदरक का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी लाभ देने वाली योजना होगी। माननीय कृषि मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और मैं इस माननीय सदन के माध्यम से अपने चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र तथा पूरे जिला ऊना के लोगों की ओर से धन्यवाद करना चाहुंगा। मैंने पूर्व में आपके सामने मांग रखी थी कि हमारे जिला में आलू की खेती बहुत ज्यादा होती है

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1900/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी .....

प्रदेश में 80 प्रतिशत आलू हमारे जिला ऊना में होता है। मैंने डिमांड की थी कि जो व्यापारी बाहर से आते हैं वे मेरे विधान सभा क्षेत्र से आलू खरीदते हैं और हमारे लोग उनसे ठगे जाते हैं। आपने आलू का प्रोसेसिंग यूनिट मेरी विधान सभा को दिया और अभी उसका टेंडर भी हो गया है। बहुत ही जल्द उसका काम चालू हो जाएगा। लगभग 65 करोड़ रुपये की

लागत से पहला हिमाचल में आलू का प्रोसेसिंग यूनिट लगने जा रहा है। यह प्रोसिसिंग यूनिट मेरी विधान सभा की धंधडी पंचायत में लगने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मैं माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बरसात में अम्ब नगर पंचायत में बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। उस समय मुझे साढ़े सात करोड़ रुपये तटीकरण के लिए दिए गया (बांध लगाने के लिए)। भैरा-से-चरूडू रोड के लिए 13 करोड़ रुपये दिये गये और सर आपने शहीद अनमोल कालिया राढ़ा-पैढ़ा किन्नुसे के लिए 16 करोड़ रुपये दिये। न्यू ओ0पी0डी0 अम्ब हॉस्पिटल के लिए साढ़े 3 करोड़ रुपये, जवासनारी-बिला थप्प्ल के लिए 12 करोड़ रुपये दिये। इसके अतिरिक्त, टेम्पल के लिए 130 करोड़ रुपये प्रसाद योजना के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र को दिये गये थे। जैसे विपक्ष कह रहा था प्रसाद योजना के तहत 55 करोड़ रुपया दिये गये है जोकि केन्द्र सरकार से आया था लेकिन वह पैसा हमने हाईकोर्ट में केस लड़कर लिया। इन्होंने मना कर दिया था कि हम वो पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद सर सोहारी-टिकोली रोड के लिए 14 करोड़ रुपये दिये गये, माता चिन्तपुरनी स्कीम जोकि आई0पी0एच0 की स्कीम है, उसके लिए 13 करोड़ रुपये दिये गये। इरिगेशन स्कीम के लिए हमें 12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं एक विशेष मुद्दा माननीय सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे चिंतपूरनी का टेंपल जिस पर माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी ने भी बात की थी। उससे हम बहुत लोगों को

24.03.2026/1900/ए0जी0/ए0पी0/-02

राहत देते थे। उस मंदिर के ट्रस्ट से हम गरीब परिवार को शादियों के लिए पैसा देते थे। वह पैसा देना माननीय कोर्ट ने बंद कर दिया। मैं फिर इस सदन के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि उसके ऊपर जरूर ध्यान आकर्षित किया जाए। उससे गरीब लोगों का फायदा होता था क्योंकि बाहर के जो लोग जो आते हैं। वहां पर हम लोगों को क्या मिलता है। धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन मिलता है। आज हम उन जगह से अगर किसी गरीब का फायदा कर सकते हैं तो उसमें भी माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उसी तर्ज पर हमारे वहां पर एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है बाबा बड़भाग सिंह जी। बाबा बड़भाग सिंह जी का जो स्थान

है वहां पर हजारों लोग, लाखों श्रद्धालु, पंजाब के लोग, बाबा बड़भाग सिंह स्थान पर आते हैं। सर, चिंतपुरनी टेंपल का तो कहीं-न-कही योगदान है। वहां पर अपने परिसर में वह अपने लिये काम कर रहे हैं। बाबा बड़भाग सिंह जी का जो गुरुद्वारे हैं वहां पर पैसा कि जो चढ़त होती है। उनका कोई भी योगदान हमारे समाज के लिए नहीं है। वहां पर अगर कोई टॉयलेट्स बनाने या कुछ काम करना है हमारी ही सरकार, हमारा प्रशासन वहां पर कार्य करता है। हमारे सैंकड़ों पुलिस के अधिकारी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। वहां पुलिस सेवाएं देती है।

Chairman: Please wind-up now.

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सर उसके ऊपर मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या माननीय सदन इसके ऊपर काई ऐसा काम करेगा जैसे चिंतपुरनी टेंपल के ऊपर नीति बनाई है। क्या बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा के लिए भी कोई नीति बनाई जाएगी। इवन कि हमारी पुलिस फोर्स, एस्कॉर्ट करके उनको पैसा पंजाब में छोड़ने जाती है। मैं यह समझता हूं कि इसके लिए विशेष रूप से एक हाई लेवल की कमेटी बनानी चाहिए और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मैं यह समझता हूं कि उसका कम-से-कम, कुछ-न- कुछ योगदान तो हिमाचल के उन लोगों के लिए होना चाहिए। जिन लोगों के लिए मेड़ी, जवाहर, पोलिया-पड़ोता, रिपो, नेरियां गांव के अंदर लोग जो हैं वे उस समय इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैजब वहां पर बाबा बड़भाग सिंह मेला खत्म होता है। सर वहां पर कम-से-कम पंद्रह-बीस दिन अगर बारिश ना हो वहां पर कोई भी लोग जा नहीं पाते हैं। इतनी गंदगी वहां पर फैल जाती है, टॉयलेट का प्रॉपर प्रबंधन नहीं हो पाता है। इसके ऊपर मैं

24.03.2026/1900/ए0जी0/ए0पी0/-03

विशेष रूप से आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। सर इसके साथ ही मेरा कामखया मंदिर है। सर यह एक बहुत पवित्र मंदिर है। कामखया मंदिर हमोर पोलिया-पडोता गांव के अंदर पड़ता है।माता कामखया देवी का मंदिर है। बहुत लोग वहां पर आते हैं। वहां पर एक मंदिर टॉपर है। वहां पर दोनों साइड जो रोड है वह ज्वार से आकर पोलिया-पडोता को लगता है। वहां पर एक पुल की जरूरत है। मैं माननीय सदन के ध्यान उस तरफ लेकर

आना चाहूंगा कि पुल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।सर एक मेरा फायर सर्विस स्टेशन है उसके लिए अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी इस विषय पर बात रखी थी। आज मैं एजुकेशन पर बात बोलना चाहूंग, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं। आज हम व्यवस्था परिवर्तन के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले सके। अगर गांव का बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके लिए पांच हजार रुपये प्रति स्टूडेंट देने की नींव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखी है। सर मैं माननीय कृषि मंत्री जी के सामने बात रखना चाहता हूं कि जिस तरीक से पेस्टीसाइड पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रहा है। मेरे विधान सभा में जो आलू की फसल होती है, वहां पर अंधाधुंध पेस्टीसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी स्वां नदी में जो बाहरी राज्यों जैसे यू0पी0 के राई क्षेत्र के लोग आते हैं। वे लोग वहां पर फसल और सब्जियां तैयार करते हैं। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि उनकी फसलों पर कितने प्रतिशत पेस्टीसाइड का प्रयोग होगा। वह लोग रेत में भी सब्जियां तैयार कर लेते हैं। वहीं पेस्टीसाइड हमारे बच्चों के अंदर जा रहे हैं। वही जहर हमारे बच्चे खा रहे हैं। आज हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसे मामलों तेजी से बढ़ते जा रहे है। इसका सबसे बडा कारण पेस्टीसाइड है। सर मैं माननीय सदन

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1905/AT/AS/01

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी.....

सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है और बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसी तरह पेस्टिसाइड्स भी बिना विशेषज्ञ की सलाह के इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि कौन-सी दवाई सही है, यह हमें पता नहीं होता। सभापति महोदय, यू0पी0 और बिहार के लोग वह बिना सही जानकारी के धड़ाधड़ स्प्रे कर रहे हैं।

मैं आपका धन्यवाद करता हूं और चिंतपूर्णी कॉलेज के बारे में भी कहना चाहूंगा। माननीय बिक्रम जी यहां से चले गए हैं, उनकी विधान सभा में मेरा चिंतपूर्णी कॉलेज पड़ता है। उसकी हालत बहुत खराब है। पिछले पांच वर्षों में इन्होंने बहुत कहा कि हमने यह किया, वह किया है।

मैं खेल मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरी विधान सभा के निषाद कुमार जो एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उन्हें आपने 7 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया, इसके लिए में माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसी तरह से मेरी पंचायत सूर्य से सुनील कुमार ने भी ओडिशा में नेशनल पैरा गेम्स में दो कांस्य पदक जीते हैं और दुबई में भी पदक जीते हैं। क्या उसके लिए भी कोई पुरस्कार की व्यवस्था की जा सकती है?

अब मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मैंने पहले शेर मुख्य मंत्री जी के प्रति पड़ा था। आज मैं आप लोगों के प्रति पढ़ रहा हूं क्योंकि पांच गुटों में बटी हुई भाजपा, आज वह छटपटा रही हैं।

मरीज हमें दवाइयां बताने लगते हैं,
बुरा वक्त हो तो सब आज़माने लगते हैं।
खुदा आपको सलामत रखे,
वरना खून के रिश्ते भी रुलाने लगते हैं।

24.03.2026/1905/AT/AS/02

नए अमीरों के घर में भूलकर भी कभी मत जाना,
वरना घर में रखे हर सामान की कीमत बताने लगते हैं।
वो दिल और दिमाग में कितनी खटास रखते हैं,
जो जिस्म पर महंगे लिबास रखते हैं।

धन्यवाद सर। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, जो मुख्य मंत्री जी लेकर आए हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपूर्णी।

24.03.2026/1905/AT/AS/03

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी।

श्री आशीष शर्मा : सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय विधायकों और प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां भगवती के चरणों में एक छोटी-सी स्तुति अर्पित करके अपनी बात शुरू करता हूं।

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते।

मां भगवती हम सबका और इस प्रदेश का कल्याण करें, यही मेरी कामना है। सभापति महोदय, इस बजट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे वर्ष 2023-24, 2024-25 और वर्ष 2025-26 के बजट थे, वैसे ही यह बजट भी केवल आंकड़ों में उलझाने वाला है। उदाहरण के तौर पर, पहले कहा गया था कि 31 मार्च, 2026 तक हमारा प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा। लेकिन अब वह संभव नहीं लग रहा है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में ग्रीन एनर्जी तो दूर, जो हरियाली थी उसका भी दोहन लगातार हो रहा है। अब मैं युवाओं की बात करना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं को इस बजट से बहुत उम्मीद थी। बजट में कहा गया है कि विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली जाएंगी। लेकिन पिछले साढ़े तीन वर्षों से केवल घोषणाएं ही हो रही हैं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, तब वादा किया गया था कि एक साल में एक लाख युवाओं को रोजगार देंगे और पाँच साल में पाँच लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब यह संभव नहीं है, यह सबको पता है। लेकिन फिर भी कुछ तो रोजगार के अवसर देने चाहिए। जब आप सारे संस्थान और इंस्टिट्यूशन बंद कर देंगे, तो बच्चे कहां जाएंगे? मैंने यह प्रश्न लगाया था

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी.....

24.03.2026/1910/केएस/एएस/1

श्री आशीष शर्मा जारी ---

यह इसी सदन की सम्पत्ति है हालांकि मुझे इसका जवाब बहुत समय बाद मिला था। पहले सूचना ही एकत्रित की जा रही थी। मैंने पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत ढाई वर्षों में कितने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोज़गार मिला? क्योंकि इसमें पिछले से पिछले सत्र का जवाब सरकार द्वारा दिया गया और सभापति महोदय, जो आंकड़ा आया उसके अनुसार 439 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोज़गार दिया गया। मैंने यह भी कहा था कि मुझे नाम व एड्रैस सहित जानकारी दी जाए। मुझे पूरे जिला की जानकारी दी गई। हमारा छोटा सा जिला है और मुख्य मंत्री जी का गृह जिला है। 439 युवाओं को रोज़गार दिया गया जिनमें गैर सरकारी के नाम भी डाल दिए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पैरा फीटर्ज़ के नाम भी डाल दिए गए और कहा गया कि 439 युवाओं को रोज़गार दिया गया। मैं तो युवा होने के नाते केवल इतना कहना चाहता हूं कि 1 लाख नौकरी आप एक साल में भी और पांच साल में भी छोड़ो, साढ़े तीन वर्षों में अगर आपने 10 हजार नौकरी भी सरकारी क्षेत्र में दी हैं तो कृपा करके नाम/पते सहित आंकड़ा इस विधान सभा के पटल पर रखा जाए। अगर सरकार के पास प्रिंटिंग के लिए बजट नहीं है, क्योंकि जो मुझे रिप्लाई आया है इसमें एक पेज पर 10 बच्चों का नाम दिया गया है, तो 10 हजार बच्चों के नाम व पते के लिए 1 हजार पेज लग जाएंगे तो उसका भी प्रावधान हो और अगर हमें उसका पैसा जमा करवाने के लिए बोलेंगे तो वह भी करवा दिया जाएगा। मेरी गुजारिश सिर्फ यह है कि सरकार युवाओं को धोखा देना बंद करे। क्योंकि सरकार ने अभी तक पिछले साढ़े तीन वर्षों में केवल आंकड़ों में सारे प्रदेश को उलझा कर रखा हुआ है। आज इस सरकार ने युवाओं को दुखी किया है, महिलाओं को दुखी किया है। माताएं व बहनें 1500 रुपये का इंतज़ार कर रही हैं। उनसे तीन-तीन, चार-चार बार फॉर्म भरा दिए गए हैं। बेरोज़गार सड़कों पर हैं, वे दुखी हैं। महिलाएं दुखी हैं। पैंशनर अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आज जो मरीज हैं, ठीक है, मुख्य मंत्री जी ने हिमकेयर कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ में बंद किया है लेकिन इस सदन के माध्यम से मेरी गुजारिश है, मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं कि जो लोग

डायलिसिस करवाते हैं, क्योंकि कहीं भी सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधा नहीं है कि सभी का डायलिसिस हो सके। अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ में सारी बीमारियों को हिमकेयर के अंतर्गत नहीं लेना है तो

24.03.2026/1910/केएस/एएस/2

केवल डायलिसिस को अलाउ किया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार डायलि स का 2000 रुपये खर्च आता है और हफ्ते में अगर दो बार डायलिसिस करवाया जाता है तो 4 हजार रुपये लगते हैं। महीने में टैक्सी में आने जाने के साथ 20-25 हजार रुपये लग जाते हैं जो कि गरीब व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे हॉस्पिटल में केवल 50 मरीज डायलिसिस करवा सकते हैं अगर उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब किसी अगले मरीज का नम्बर आता है। कृपा करके केवल डायलिसिस के लिए हिमकेयर कार्ड को प्राइवेट हॉस्पिटल्ज़ में खोल दें क्योंकि ये खोलने बहुत जरूरी हैं।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार के समय की सहारा पैंशन योजना बंद कर दी गई। जो व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से जूझ रहे थे उनको केवल 3 हजार रुपये महीने का मिलता था लेकिन वह भी पिछले डेढ़ वर्ष से नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, वे दुखी हैं। पैंशनर्ज़ दुखी हैं। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, किसी महान संत ने कहा है कि :-

दुखिया को मत सताइए, दुखिया देगा रोय,
और जब दुखिया का मुखिया सुने, तो तेरी गति क्या होय।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करुं तो मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं जिन्होंने प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज हमीरपुर को देने की घोषणा की। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैडिकल कॉलेज हमीरपुर की तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी पिछले 21 मार्च को अमर उजाला में खबर लगी थी कि

मैडिकल कॉलेज को नहीं मिला अपना कैम्पस। अध्यक्ष महोदय, यह जो मैडिकल कॉलेज है, मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी है कि वह जोनल हॉस्पिटल में कई वर्षों से चला हुआ है। हालांकि जोलसप्पड़ में कैम्पस बन रहा है और मुख्य मंत्री जी ने भी उसमें प्रयास किए हैं, केंद्र से भी उसमें बजट मिला है। आदरणीय जय राम जी की सरकार में वर्ष 2018 में उसका शिलान्यास हुआ था। आदरणीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री

24.03.2026/1910/केएस/एएस/3

थे तो वे वहां पर आए और अभी भी क्योंकि वह मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र का कॉलेज है, ये खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन इस न्यूज़ में लगा था कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

24.03.2026/1915/av/dc/1

श्री आशीष शर्मा--------जारी

वहां फर्नीचर के लिए 17 करोड़ रुपये की राशि चाहिए जिसकी वजह से यह डिले होता जा रहा है। मुख्य मंत्री महोदय, यह आपके विधान सभा क्षेत्र का कॉलेज है और आपका ड्रीम प्रोजैक्ट है। अगर यह कॉलेज चलेगा तो पूरे-के-पूरे जिले को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि हमीरपुर के जोनल होस्पिटल में बहुत ज्यादा क्राउड होता है और गायनी वार्ड में एक-एक बैड पर तीन-तीन मरीज होते हैं। यहां तक कि वार्ड के बाहर भी मरीज सो रहे होते हैं। आप जो रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीन्ज खरीद रहे हैं, यदि आप इसको भी सीरियस लेंगे और चाहे आपके ही कर-कमलों द्वारा उसका शुभारम्भ हो जाए। परंतु कृपा करके इसको शुरू कीजिए ताकि पूरे हमीरपुर जिला की जनता को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री के समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे वहां पर एक शहीद स्मारक का शिलान्यास भाजपा सरकार के समय में भी हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री ने भी उसका शिलान्यास किया है। वह एक छोटा-सा प्रोजैक्ट है और उसके लिए वहां पर केवल 70 लाख रुपये की राशि चाहिए। उस पर अभी तक 13 लाख

रुपये व्यय हो चुके हैं। हमीरपुर वीरों की भूमि है और वहां हर तीसरे घर से एक सैनिक था या सैनिक है। वहां पर मुख्य मंत्री जी गए थे तथा इन्होंने वहां पर उसका शिलान्यास भी किया। मैं आपका उसके लिए धन्यवाद करता हूं परंतु कृपा करके उसको पूरा किया जाए। उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है, वहां पर केवल 70 लाख रुपये की राशि लगेगी। उसके लिए इस बजट में पैसों का प्रावधान कीजिए ताकि जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनकी याद में उसको समर्पित कर सकें। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी इस बात का ध्यान रखेगी।

यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जी0एस0एस0एस गर्ल्ज को बॉय्ज स्कूल के साथ मर्ज कर दिया है और कहा गया है कि गर्ल्ज स्कूल में कॉलेज की क्लासिज चलेगी। वहां उस जी0एस0एस0एस0 बॉय्ज स्कूल को सी0बी0एस0ई0 करके उसको को-एड कर दिया गया है। मैं उसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने उसको सी0बी0एस0ई0 किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जी0एस0एस0एस0

24.03.2026/1915/av/dc/2

गर्ल्ज में 450 छात्राओं की स्ट्रैंथ थी। यदि उस स्कूल को भी वहीं रहने दिया जाएगा चाहे उस स्कूल को भी आप को-एड कर लीजिए परंतु उसको एच0पी0 बोर्ड रहने दीजिए। ऐसा करके वहां पर एक स्कूल सी0बी0एस0ई0 और एक एच0पी0 बोर्ड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों स्कूल्ज शहर के बीच के स्कूल हैं। ये दोनों ही बहुत पुराने स्कूल्ज हैं और इनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन दोनों स्कूल्ज में स्ट्रैंथ भी ठीक है। एन0सी0ई0आर0टी0 और सी0बी0एस0ई0 का आठवीं कक्षा तक लगभग सेम सिलेब्स है। लेकिन आठवीं कक्षा के बाद सिलेब्स में फर्क है और कुछ बच्चे एन0सी0ई0आर0टी0 के सिलेब्स के साथ कोप-अप नहीं कर पाते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस बारे में विचार करेंगे तो पूरे हमीरपुर की जनता मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करेगी कि इन्होंने उनकी बात को सुना है।

अभी यहां पर माननीय लोक निर्माण मंत्री उपस्थित नहीं है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेन हमीरपुर से चाहे वह मुख्य मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है और अध्यक्ष महोदय, आप भी वहीं से आते हैं। जब रंगस से हमीरपुर की तरफ आते हैं तो पूरे-का-पूरा रोड टूटा हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने पीछे वहां मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। अगर पक्का भ्रो से जोल सप्पड़ की ओर टर्न करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पूरा रोड टूटा हुआ है। जब हमीरपुर बाई पास से निकलते हैं तो टिक्कर तक पूरा रोड टूटा हुआ है। यहां तक कि वहां पर पैच वर्क भी नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि वहां के लिए कुछ-न-कुछ प्रावधान किया जाए। वहां के लिए या तो फ्रैश टारिंग की जाए, अगर टारिंग के लिए पैसा नहीं है तो वहां पर पैच वर्क ही कर दिया जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो और दुर्घटनाएं न घटे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्रिज हैं जिनका मैंने डी0सी0 के माध्यम से विरोध भी किया था और मैंने उसके संदर्भ में लोक निर्माण मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था कि एग्जिस्टिंग ब्रिज तोड़ दिए गए तथा रोड वहीं पर खड्डों से डाइवर्ट कर दिया गया। जिसकी वजह से हमीरपुर-जाहु मुख्य रोड पर एक गुदवीं खड्ड पर ब्रिज है और दूसरा ब्रिज जमली खड्ड पर है। वहां पर इतनी ज्यादा असुविधा हो रही है कि बारिश के दिनों में वहां से बच्चों की स्कूल बसिज नहीं जा रही हैं। जबकि वह एम0डी0आर0 रोड था। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी उसमे संज्ञान लें और विभाग को निर्देश दिए जाएं कि 6 महीने के अंदर-अंदर उन दोनों ब्रिजिज का काम पूरा किया जाए।

टी सी द्वारा जारी

24.03.2026/1920/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

श्री आशीष शर्मा... जारी

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह जो बजट है, यह दिशाहीन बजट है। क्योंकि भगवान के बाद सरकार होती है और लोगों की अपेक्षाएं सरकार से होती हैं। भगवान और सरकार दोनों देने वाले होते हैं, लेकिन यह बजट लेने वाला है यानी दूसरों का हक लेने वाला है। यह बिल्कुल पाप के समान है

और मैं समझता हूं कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है। इसलिए मैं इसका समर्थन कतई नहीं कर सकता।

24.03.2026/1920/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेडिकल कॉलेज की बात की है। मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में कई बार कई बातें सामने आती हैं। हमारे समय में, जब गुलाम नबी आजाद हैल्थ मिनिस्टर थे, उस समय 2 मेडिकल कॉलेज एक चंबा और एक नाहन में खोला गया । ये क्षेत्र एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किए गए थे और साथ ही कैंसर इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए गए। उस समय मेरे उनके साथ अच्छे संबंध थे। मैंने उन्हें फोन किया और वे मण्डी में थे। उसके बाद मेरे कहने पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। उस समय विनीत चौधरी जी हमारे सेक्रेटरी हैल्थ थे और कौल सिंह ठाकुर जी मंत्री थे। कई बार ऐसा होता है कि माननीय एम0पी0 साहब आते हैं और बहुत-सारी बातें करते हैं। उसी समय उसका नाम डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज रखा गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 169 करोड़ रुपये दिए लेकिन 169 करोड़ रुपये से कार्य पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार चंबा और नाहन में भी समान स्थिति रही। जब 169 करोड़ रुपये मिले, तब तक हमारी सरकार चली गई थी क्योंकि एफ0सी0ए0 केस नहीं हुआ था। बाद में एफ0सी0ए0 केस होने के बाद श्री जय राम ठाकुर जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। आज तक उस मेडिकल कॉलेज पर लगभग 550 करोड़ रुपये और चंबा में लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। नाहन के लिए मैंने 500 करोड़ रुपये का स्पेशल प्रावधान किया है, जिसे आगामी सत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। जहां तक मेडिकल कॉलेज के संचालन की बात है, यह सही है कि नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक के मेडिकल कॉलेज पूरी तरह सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया और पाया कि सबसे बड़ी समस्या फैकल्टी की कमी है। जब फैकल्टी ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज कैसे चलेंगे?

आई0जी0एम0सी0 और टांडा में हमने कई वर्षों बाद पी0जी0 और एस0आर0शिप शुरू की क्योंकि फैकल्टी की कमी के कारण ये मेडिकल कॉलेज नहीं चल पा रहे थे। इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा कि हमने कुछ डॉक्टरों को एम्स जाने के लिए एन0ओ0सी0 दे दी, जिससे वे वहां चले गए और फैकल्टी कम हो गई। अब हमने निर्णय लिया है कि मेडिकल कॉलेजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पी0जी0 की सीटें बढ़ानी होंगी। जब पी0जी0 की सीटें बढ़ेंगी, तभी डॉक्टर उपलब्ध होंगे और मेडिकल कॉलेज ठीक से चल पाएंगे। कैजुअल्टी में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वे या तो एस0आरशिप करने वाले

24.03.2026/1920/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

होते हैं या पी0जी0 करने वाले होते हैं। पिछले 40 सालों में लगभग 270 पी0जी0 सीटें सृजित की गई। जब तक नाहन में पी0जी0 शुरू नहीं होगी मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा क्योंकि वहां डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होगें। इसी तरह से अन्य कालेजों की भी यही स्थिति है। इन तीनों कॉलेजों का पिछले तीन सालों से सिर्फ मेडिकल कॉलेज नाम था और ये रैफरल हॉस्पिटल बन गए थे। हमने मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष के लिए 270 पी0जी0 की सीटें सृजित की हैं। सभी कॉलेजों में गाइनी, कार्डियक, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स जैसे सैक्टर में एसोसिएट पद भी सृजित किए जा रहे हैं। आज ही मैंने एक और निर्णय लिया है कि डायरेक्टोरेट ऑफ हैल्थ सर्विसेज से जो 50 प्रतिशत प्रमोशनल पोस्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनके लिए 4 वर्ष का कैडर बनाया जाए। हम उनके कल परसों तक चार मेडिकल कॉलेज में ऑर्डर करने जा रहे हैं ताकि जो डेजिग्नेटिड प्रोफेसर हैं जो किसी अन्य कारणों से लग जाते हैं उनको उनके पेरेंट्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए और जो मेडिकल कॉलेज में खपत होने वाले अगले 4 साल की प्रमोशन्ल पोस्ट पर है उनके लिए हम एक -दो दिनों में 114 डॉक्टर के ऑर्डर करने वाले हैं ताकि मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह चल सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार एजुकेशन सैक्टर में सुधार किया जा रहा है, उसी प्रकार हैल्थ सैक्टर में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मैं स्वयं एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन दोनों की निगरानी कर रहा हूं। एक वर्ष के भीतर एजुकेशन और हैल्थ

दोनों क्षेत्रों में सभी पदों को भरा जाएगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां हाई टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जहां तक जोल सप्पड़ सड़क का प्रश्न है, उसे मैंने स्वयं देखा है। उसके लिए मैंने एन0एच0ए0आई0 के साथ मामला उठाया है और शीघ्र ही हमें 38 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल जाएगी।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री नीरज नैयर जी चर्चा में भाग लेंगे ।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

24-3-2026/1925/एन0एस0-एच0के0/1

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान सभा के पटल में पढ़े, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों के अंदर प्रदेश को बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। वर्ष 2025 में प्रदेश को तकरीबन 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद प्रदेश में एक मैन मेड आपदा आई जिसमें हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। मुझे याद है कि इस माननीय सदन में ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है। आजकल नवरात्रि लगे हुए हैं और मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान ने स्वयं आकर हमारी सरकार को बचाया है। उसके बाद दोबारा से उप-चुनाव हुए और हमारी पार्टी के जीते हुए विधायको की संख्या फिर से 40 हुई। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद भी उन्होंने एक बेहतरीन बजट पेश किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की आर0डी0जी0 बंद कर दी गई जिससे प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है और इसमें समाज के हर वर्ग को कुछ-न-कुछ दिया गया है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी मेरे से पूर्व वे सरकार के बारे में काफी कटाक्ष कर रहे थे और केंद्र सरकार

की बड़ी-बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। ठीक है, केंद्र सरकार है और हरेक प्रदेश को पैसा देती है लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि जब प्रदेश में वर्ष 2025 में आपदा आई तो हमने इस माननीय सदन से उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा और ऐसा नहीं हो पाया। उत्तराखंड में जब ऐसी आपदा आई तो केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये की मदद की। वर्ष 2025 में जब आपदा आई तो प्रधानमंत्री जी स्वयं धर्मशाला आए और वहां पर 1500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की लेकिन यह राशि आज तक हमें नहीं मिली। उसके बाद बिहार के विधान सभा चुनाव आए। वहां पर डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 10,000 करोड़ रुपये 1 लाख 500 महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लोकसभा और राज्यसभा

के चुनावों में 6 सांसद भेजे हैं लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को कुछ नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हिमाचल प्रदेश भी उससे अनूठा नहीं है। हमारी लगभग 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है। हमारे प्रदेश के लोग खेतीबाड़ी करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने इस बार का जो बजट बनाया है उसमें विशेष तौर पर गांव के लोगों को बहुत तरज़ीह दी गई है, चाहे दूध पर एम0एस0पी0 देने की बात हो, चाहे हल्दी पर एम0एस0पी0 देने की बात हो और चाहे गेहूं पर एम0एस0पी0 देने की बात हो।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया एक मिनट बैठें। सत्र की कार्यवाही सायं 07.30 बजे तक बढ़ाई गई थी। अभी और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 08.00 बजे तक बढ़ाई जाती है।

आगे------ आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

श्री नीरज नैय्यर : चाहे गेहूं और अदरक पर MSP की बात हो, मुझे लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बड़ा संतुलित बजट पेश किया है। अभी मेरे भाजपा के साथी बोल रहे थे कि चम्बा को इस बजट में क्या मिला? मैं इस मंच से खुले तौर पर बोलना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बनकर आया था तो चम्बा, मेडिकल कॉलेज का कार्य पूर्ण तरीके से बंद था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस काम को शुरू करने के लिए 175 करोड़ रुपये जारी किए हैं जिसकी बदौलत फेज-1 की बिल्डिंग पूरे तरीके से बनकर तैयार हो गई है। हमारे जिला के कुछ साथी बोल रहे थे कि चम्बा जिला को क्या मिला? लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि फेज-II में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 194 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चम्बा मेडिकल कॉलेज के बारे में भली-भांति परिचित हैं। आप वहां गए भी हैं। जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी चम्बा आए थे तो उस वक्त उपायुक्त महोदय के साथ बचन भवन में हमारी एक मीटिंग हुई थी। हमने फेज-II के बारे में श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार हमें 194 करोड़ रुपये फेज-II में मिले हैं। हमें यह भी खुशी है कि उस मेडिकल कॉलेज के अंदर 40 बेडिड ICU सैंक्शन किए गए हैं। चम्बा दूर-दराज का इलाका है और वहां कैथ लैब की स्थापना के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा चम्बा जिला दूर-दराज का क्षेत्र है। अगर किसी को heart problem हो जाए तो आदमी रेफरल होस्पिटल में नहीं पहुंच पाता। चाहे टांडा जाना हो, चाहे चंडीगढ़ या किसी अन्य जगह जाना हो लेकिन हमें खुशी की बात है कि Angiography और Angioplasty अब चम्बा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही शुरू होगी। अब यह कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आज बोला और कल कार्य हो जाएगा। लेकिन इस बजट के अंदर उस ओर कदम बढ़ाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा और आपका चम्बा-चुवाड़ी टनल का सपना है, उसके लिए आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से 4.30 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाये हैं। इसकी DPR पूर्ण तरीके से तैयार हो गई है। यह टनल साढ़े चौदह

किलोमीटर लम्बी होगी और इसे PPP मोड पर बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि जो हमारा aspirational जिला है उसको

24.03.2026/1930/RKS/HK-2

कुछ एडवेंटेज मिले। यह सिर्फ चम्बा-चुवाड़ी की बात नहीं है। यह पूरे इलाके के लिए टनन बन रही है जिससे पूरे चम्बा जिला के लोगों की भाग्य रेखा बदलेगी। यह साढ़े 14 किलोमीटर की टनल मंगला से निकलते हुए सीधे चुवाड़ी निकलेगी। क्योंकि आजकल गाड़ियों की अच्छी स्पीड होती है इसलिए चौदह मिनट के अंदर हम चंबा से चुवाड़ी पहुंच जाएंगे। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो दो-अढ़ाई घंटो के अंदर चम्बा, धर्मशाला के साथ लिंक हो जाएगा। यह कितनी बड़ी बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और अध्यक्ष महोदय को इसके लिए बधाई देना चाहूंगा क्योंकि इनकी बदौलत यह कार्य शुरू हो सका है। मैं एक और चीज के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने साहू बालिका आश्रम के लिए अठारह करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। साहू का इलाका तकरीबन ग्यारह पंचायतों का हैडक्वार्टर है। यहां सब-तहसील भी खोली गई है। यहां पर 2 करोड़ रुपये की लागत से बालिका आश्रम का निर्माण कियाजाएगा। हमारा चम्बा का जो भूरि सिंह म्यूजियम है उसमें हमारे इतिहास और संस्कृति को संरक्षित रखा गया है। उसके नवीनीकरण के लिए भी इस बजट के अंदर लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। हमारे चम्बा का जो metal craft और चम्बा चुख है, उसे जी0आई0 टैग दिलवाने के बारे में इस बजट में उल्लेख किया गया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

24.03.2025/1935/बी.एस./वाई.के.-1

श्री नीरज नैय्यर जारी...

तो यह कुछ अच्छी चीज है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बातें कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर गद्दी-गुर्जर लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार गद्दी-गुर्जर और जनजाति समुदाय के लिए 300 करोड़ रुपये की पहल योजना शुरू की गई है और इसके माध्यम से तकरीबन 40,000 लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनको सामाजिक रूप से मजबूत किया जाएगा। ऊन लिए 100 रुपया प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। यह एक बहुत अच्छी पहल इस बजट के अंदर की गई है।

मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी मेरे जिला के साथी यह कह रहे थे कि चम्बा के लिए इस बजट में कुछ भी मेजर नहीं है। भाई, मैं आपके विधान सभा क्षेत्र के बारे में नहीं जानता, हालांकि, मैं अध्यक्ष महोदय को उस समय देख रहा था। परंतु मुझे स्पष्ट तौर पर सुनाई नहीं पड़ा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 वर्षों से मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाजपा का विधायक रहा है। हर विधायक काम करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि चंबा में इंडोर स्टेडियम के लिए 11 करोड़ रुपये, मिनी सचिवालय के लिए 36 करोड़ रुपये, हेलीपोर्ट (सुल्तानपुर) के लिए 13 करोड़ रुपये, ओल्ड बस स्टैंड की पार्किंग के लिए 13 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि चम्बा शहर के हाई एण्ड सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 7.50 करोड़ रुपये दिए। सरोल-हरिपुर-राजपुरा सीवरेज के लिए जो हमारा डेवेलपिंग एरिया है और ये एरियाज बस रहे हैं, उसके लिए 20.22 करोड़ रुपये सीवरेज के लिए दिए हैं। साहू इलाके के लिए 5 करोड़ रुपये कूहल के लिए दिए।

मैंने 14 सड़कें अपने क्षेत्र में पी0एम0जी0एस0वाई0-4 में डलवाईं हैं और 8 सड़कें पी0एम0जी0एस0वाई0-3 में डलवाईं हैं। मैं दिल्ली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये सड़कें स्वीकृत हुईं। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। अगर पैसा आया है और टेंडर लगे हैं तो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो डी0पी0आर्ज0 थीं, ये मैंने 14 डी0पी0आर्ज0 स्वयं बैठकर तैयार करवाई हैं और मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए भेजीं हैं। साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी और डिप्टी सी0एम0

24.03.2025/1935/बी.एस./वाई.के.-2

साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक आई0पी0एच0 रेस्ट हाउस, मंगल में 4 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है जो लगभग तैयार होने वाला है।

मैं विशेष रूप शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और जब वे पिछले वर्ष चंबा आए तो चंबा डिग्री कॉलेज, जिसमें 4200 बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए इन्होंने एम0ए0 सोशियोलॉजी का कोर्स दिया, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0 और एम0कॉम का कोर्स भी दिया। चार नई स्ट्रीम्ज पी0जी0 कॉलेज चम्बा के लिए शिक्षा मंत्री जी ने दी हैं।

मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, इस बार जब वे चम्बा आए, तो उन्होंने 6 करोड़ रुपये साहू के साइंस ब्लॉक के लिए दिये और चनेहड़ साइंस ब्लॉक के लिए दिये। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की साइट पर भी ये स्वयं गये हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी एफ0आर0ए0 जल्द पूरी हो जाए। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि साहू के मेले को डिस्ट्रिक्ट लैवल का दर्जा दिया गया। जो हमारा सूई का मेला है उसको डिस्ट्रिक्ट लैवल का दर्जा दिया गया। इतने सारे काम तीन वर्षों के अंदर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय चंबा वालों का खास ध्यान रखते हैं। कृपया मुझे 2 मिनट और दें।

मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि वे पक्षपात की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पक्षपात किसी और सरकार ने नहीं किया। मुझे याद है जब मैं चुनाव हारा था उस समय देखा था कि जितने भी आई0पी0एच0 के टेंडर होते थे, वे अधिकतर मण्डी के लोग ही चंबा में लेते थे। शायद इसी कारण से भाजपा ने मण्डी में 9 सीटें जीती। क्योंकि इतना बड़ा पक्षपात हुआ कि lopsided development एक ही क्षेत्र में हुई और इसी कारण से मैं भी जीतकर आया। आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि because of this lopsided development, अन्य जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र थे वहां से कांग्रेस के विधायक जीत करके आए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। धन्यवाद।

श्री डी.टी. द्वारा जारी.....

24.03.2026/1940/DT/YK-1

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप इस चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट बढ़ने के बजाय कम हुआ है। जो बजट 21 मार्च को पेश किया गया, यह बजट जनविरोधी है और कर्ज व कटौती पर आधारित है। यह बजट प्रदेश के गठन से लेकर आज तक का सबसे कमजोर बजट है, जो हिमाचल प्रदेश की लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

इस बजट में सरकार द्वारा बार-बार दी जा रही गारंटियाँ केवल कागजों तक सीमित हैं और सरकार द्वारा इन तीन वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यह प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। इस बजट में कई ऐसी घोषणाएँ हैं, जो जमीनी स्तर पर कोई ठोस राहत नहीं दे सकतीं। प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। इस बजट में विकास के नाम पर केवल सरकार ने अपना प्रचार किया है।

इस बजट में आर0डी0जी0 के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। पहले भी स्पेशल सत्र में ऐसा किया गया था, और अभी भी इस बजट की शुरुआत आर0डी0जी0 से ही की गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि प्रदेश की आम जनता को आर0डी0जी0 से कोई मतलब नहीं है। जनता ने जिस सरकार को चुना है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश को अच्छे से चलाए। जनता विकास चाहती है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विकास करे और जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करे, न कि बहाने बनाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले नाहन में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने आर0डी0जी0 के बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया, लेकिन उनके बैनर में आर0डी0जी0 की जगह आर0जी0बी0 लिखा हुआ था। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही इसकी समझ नहीं है, तो आम जनता को इसकी समझ कैसे होगी? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आर0डी0जी0 का यह मुद्दा उठाना बंद करें और जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए अपना कार्य करें।

24.03.2026/1940/DT/YK-2

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रामीण स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों को खोलने की बात कही गई है। क्या आपने निजी क्षेत्र में लगने वाले बी0एम0सी0 की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के मरीयोग में मिल्क सोसाइटी है, लेकिन वहाँ बी0एम0सी0 न होने के कारण दूध खराब हो जाता है या लोगों को वापस घर ले जाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ-जहाँ ग्रामीण स्तर पर बी0एम0सी0 की आवश्यकता है, वहाँ इसके लिए प्रावधान अवश्य करें। मरीयोग में तो मैंने अपने विधायक निधि से

श्री एन0जी0द्वारा जारी..

24.03.2026/1945/ए.जी.-एन.जी./1

श्रीमती रीना कश्यप..... जारी

एम0एल0ए0 फंड से फंडिंग कर दी है और जल्दी ही बी0एम0सी0 की मशीन वहां पर पहुंच जाएगी। मगर बहुत से लोग हैं जिनकी इस प्रकार की डिमांड्स रहती हैं, क्योंकि दूध बढ़ रहा है और उनका दूध खराब न हो, इसके लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने दूध के रेट तो बढ़ा दिए, मगर आज लोगों की जो शिकायतें आती हैं कि वे परेशान हैं और वह इस बात से परेशान हैं कि उन्हें समय से पेमेंट नहीं मिलती। कई बार तो तीन-तीन महीने हो जाते हैं कि उन्हें दूध की पेमेंट नहीं हो पाती। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि लोगों को समय से दूध की पेमेंट की जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में लगभग 300 अधूरे कार्यों की एक लंबी सूची बनाई गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, जो अधूरे पड़े हैं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की बात करना चाहूंगी, जोकि हब्बन स्कूल के बारे में है। माननीय शिक्षा मंत्री को इस विषय के बारे में मालूम है कि वहां के बच्चे आज भी पंचायत घर में कमरे लेकर रह रहे हैं और वहां पर किराए के कमरों में क्लासिस चलती हैं। मेरा आपसे

निवेदन रहेगा कि आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हब्बन की बिल्डिंग के लिए बजट का प्रावधान करें। यह वहां के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में हमारे धरोटी स्कूल में भी फंड न होने के कारण बिल्डिंग अधूरी है। थोयना-बस्तोत्री स्कूल का कार्य भी अधूरा पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, जो 300 कार्यों की सूची बनाई गई है, उसमें हमारे पच्छाद क्षेत्र के अधूरे काम भी शामिल हों, ऐसा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी। अगर मैं 10 गारंटियों की बात करूं तो ऐसी कौन सी गारंटी है जो सरकार ने पूर्ण रूप से पूरी की है? अगर मैं महिलाओं की बात करूं और मुझे महिलाओं की बात करनी पड़ेगी क्योंकि प्रदेश की महिलाओं को कहीं-न-कहीं लगता है कि उनकी बात सदन में रखी जाए।

24.03.2026/1945/ए.जी.-एन.जी./2

अगर मैं उनकी बात करती हूं, तो उनके लिए क्या हुआ? सरकार ने 1500/- रुपये की गारंटी हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को दी थी, क्या आपने प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500/- रुपये दे दिए। 1500/- रुपये के नाम पर महिलाओं को बार-बार ठगा जा रहा है। अभी केवल 35,667 महिलाओं को 1500/- रुपये दिए गए हैं, जबकि प्रदेश में लगभग 28 लाख के आसपास महिलाएं हैं। महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं। यदि अनुमान लगाया जाए, यह मेरा अनुमान है और सरकार का पता नहीं कैसा अनुमान होगा? यदि एक महिला को प्रति माह 1500/- रुपये मिलता है तो एक साल में उसे 18,000/- रुपये और 5 साल में 90,000/- रुपये मिलेंगे। आज महिलाएं 1500/- रुपये के लिए 5 साल का हिसाब करती हैं तो पूरे प्रदेश की हरेक महिला को आपको 90,000/- रुपये देने पड़ेंगे। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि महिलाओं को समय से 1500/- रुपये पेंशन दी जाए, नहीं तो प्रदेश की महिलाओं का बकाया आपके ऊपर चढ़ जाएगा। मेरा निवेदन है कि 1500/- रुपये की गारंटी को आप समय से दे दें। यह आपकी बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है क्योंकि यहां पर जितने भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उन्होंने चुनावों के समय सबसे ज़्यादा जोर इसी 1500/- रुपये की बात पर दिया था। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब किसी

व्यक्ति को बुखार होता है तो वह बड़बड़ाता रहता है। बुखार में कुछ-न-कुछ बोलता रहता है और बाद में उसे पता नहीं चलता है कि उसने क्या बोला। आपको भी सत्ता में आने का बुखार था। आपने उस बुखार में इतनी सारी गारंटियां दे दीं, यानी के 10 गारंटी दे दीं और 1500/- रुपये के बारे में तो इस तरह से बोला गया कि हर परिवार की महिलाओं को, चाहे वह जेठानी हो, देवरानी हो, सास हो, सबको मिलेगा। मगर आज क्या हुआ? जब बुखार उतरा तो आज पता चला कि नहीं भाई, सब महिलाओं को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। आपको महिलाओं को 1500/- रुपये की जो पेंशन देनी है, उसके लिए हर बजट में आप कुछ-न-कुछ नए नियम जोड़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार पिछले बजट में सरकार द्वारा मुख्य मंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना चलाई गई थी

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

24.03.2026/1950/ए0जी0/ए0पी0/-01

श्री श्रीमती रीना कश्यप जारी ...

इस योजना के तहत मैं पूछना चाहूंगी कि एकल नारी और विधवा नारी को कितने मकान मिले? अभी कुछ महीने पहले हमारी वेलफेयर कमेटी हर ज़िले में गई, वहां पर जब प्रश्न पूछा गया कि एकल नारी को कितने मकान मिले, तो उत्तर शून्य था। तो आप बताइए, आपने यह गारंटी पूरी की या नहीं? यह बहुत सोचने का विषय है कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं या एकल नारी हैं, उन्हें इस सुविधा की कितनी आवश्यकता है। यह आपकी गारंटी भी है, और इसे आपको पूरा करना चाहिए, मैं इस सदन के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी। साथ ही, जिस प्रकार इस बजट में बताया गया कि शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को बंद कर दिया गया है और इन दोनों योजनाओं को जोड़कर एक नई योजना शुभ विवाह योजना बनाई गई है—यह अच्छी बात है। जब हमारी सरकार थी, तब शगुन योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवारों की बेटियों को 31,000 रुपये शगुन के रूप में दिए जाते थे। आपकी सरकार ने जो सोचा, वह ठीक सोचा होगा। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि यदि आप सच में बेटियों के प्रति चिंतित हैं, तो इस राशि को

51,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया जाए। तब हम मानेंगे कि आप हिमाचल की बेटियों के लिए आप चिंतित हैं। इसके साथ ही, बजट बुक में छैला-नेरिपुल-यशवंतनगर-औछघाट-लवास चौकी-प्रीत नगर सड़क का जिक्र है, पिछले विधान सभा सत्र में मैंने इस सड़क का जिक्र किया था। मैंने इस पर प्रश्न भी किया था और माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर भी दिया था। और उन्होंने कहा था कि इसकी डी0पी0आर0 केंद्र को भेज दी जायेगी। यह छैला-नेरिपुल-यशवंतनगर-औछघाट-लवास चौकी-प्रीत नगर मार्ग पांच विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ता है। यह मार्ग मेरे मायके तथा सोलन को भी जोड़ता है। मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और माननीय संतोष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके सहयोग से 204 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अलावा, मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सरांह-चंडीगढ़ सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है। यह सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी शामिल थी इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि वह इस विषय में भी जरूर सोचें। साथ ही, सोलन—मिनरेज रोड, जो सोलन- राजगढ़-नौराधार-शिलाई और

24.03.2026/1950/ए0जी0/ए0पी0/-02

उत्तराखंड को जोड़ती है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है। लंबे समय से लोगों की मांग है कि इसे डबल-लेन किया जाए, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर भी आवश्यक संज्ञान लिया जाए। अंत में मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हुए कहना चाहूंगी कि पिछले बजट में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें हर प्रकार की सुविधा जैसे 6 जो विशेषज्ञ डॉक्टर मेडिसन, सर्जन, स्त्री रोग, बाल रोग, अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट्स आदि ऐसी सेवाएं देनी थी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

24.03.2026/1955/AT/AS/1

श्रीमती रीना कश्यप जारी ....

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक यह आदर्श स्वास्थ्य संस्थान नहीं खुला है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि तीन सालों से मुझे इस सदन में आश्वासन ही मिल रहा है। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से लोगों की डिमांड के अनुसार यह संस्थान नारग में खुलना चाहिए था वहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुले और साथ में जो हमारा सरांह हॉस्पिटल है वह 100 बेडिड किया जाए ताकि वहां पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले बजट में आउटसोर्स के माध्यम से स्टाफ नर्स की भर्ती सराहं में की गई थी और उनके पदों को भरा गया था। मगर दुख का विषय है कि उनकी भर्ती मेरी विधान सभा से नहीं बल्कि दूसरी विधान सभा से स्टाफ नर्सिज को रखा गया था जबकि रूचिका शर्मा सराहं अस्पताल में में वह पांच वर्षों से कार्यरत थी। मुझे नहीं पता है कि उन्हें वहां क्यों नहीं रखा गया। जबकि कोरोना के समय भी उन्होंने दिन-रात अपनी सेवाएं दीं। मैं कहना चाहूंगी पक्षपात हुआ, दूसरी विधान सभा से वहां पर भर्ती करवाई गई। साथ ही, मैं राजगढ़ हॉस्पिटल की भी बात करना चाहूंगी। यहां हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है और स्टाफ भी नहीं है। काफ़ी लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको भी संज्ञान में लाना चाहूंगी कि वहां ब्लड बैंक होना चाहिए। इसके अलावा, एक्स-रे की मशीन खराब है, जिसके कारण हमारे राजगढ़ के मरीजों को सोलन और शिमला जाना पड़ता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में रखना चाहूंगी। यहां मैं पत्रकारों के विषय में भी ज़रूर बोलना चाहूंगी जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपके घोषणा पत्र में उनसे भी वादा किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग और लोक निर्माण विभाग में भी राजगढ़ और सरांह में कई पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। राजगढ़ में हमारे खंड विकास अधिकारी लम्बे समय से नहीं है। पिछले बजट में आपने राजगढ़ में अग्निशमन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। स्वीकृति होने के बाद भी वह अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर भी ज़रूर विचार किया जाए। मुझे अपनी बात यहां कम समय में कहने को बार-बार कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि विधायक निधि में जो कटौती की गई है, वह बिल्कुल गलत फैसला है। इससे स्थानीय विकास कार्य प्रभावित होंगे। विकास निधि जनता का अधिकार है और यह पूरी तरह से विधायक को मिलनी चाहिए। यह बात मैं यहां पर रखना चाहती हूं।

अंत में, मैं केवल व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने बाले को इतना ही कहना चाहूंगी कि :-

24.03.2026/1955/AT/AS/2

बेबसी का आलम देखो ज़रा वहां,
झूठे वादे करते हैं, चलते फिर भी सीना तान,
और कहते फिरते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है हमारी पहचान।

अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। यह बजट पूरी तरह झूठा है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, 25 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 24 मार्च, 2026 **सचिव।**